चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

सरकार क्यों चाहती है एनसीईआरटी बंद हो

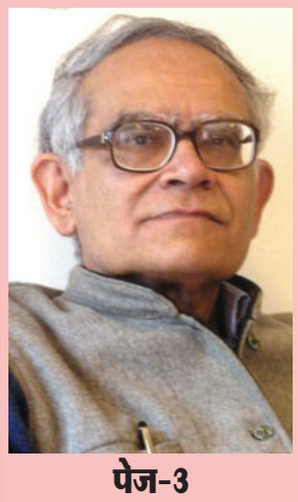

पेज-3

टीम अन्ना में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है

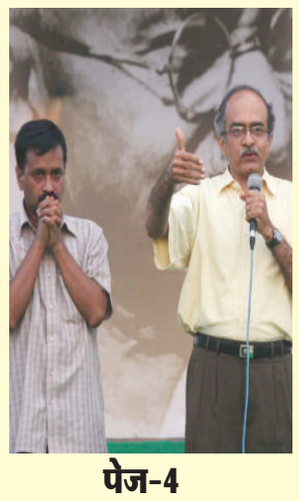

पेज-4

सरकार और विपक्ष ख़ामोश क्यों है

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 31 अक्टूबर-06 नवंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

एटॉर्नी जनरल का असली चेहरा

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

एटॉर्नी जनरल सरकार का सबसे बड़ा क़ानूनी अधिकारी होता है, उसे महान्यायवादी कहा जाता है. वह सरकार की आंख, नाक और कान माना जाता है. उसका काम जनता के हित में सरकार को सलाह देना है, लेकिन वर्तमान एटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती के कारनामों और उनकी पृष्ठभूमि से यह साबित होता है कि उन्होंने एटॉर्नी जनरल के पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा. सरकार ने इस संस्था का भी राजनीतिकरण कर दिया. मामला चाहे मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ सीबीआई के मुकदमे का हो या फिर थलसेना अध्यक्ष वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद का या फिर 2-जी घोटाला, एटॉर्नी जनरल वही सलाह देते हैं, जो सरकार के कुछ लोगों का हित साधती हो. कई बार तो उन्होंने कोर्ट में ऐसी-ऐसी दलीलें दीं, जिन्हें सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिमाग़ चकरा गया. डर लगता है कि कहीं सरकार संवैधानिक संस्थाओं को चौपट करने पर आमादा तो नहीं है. एक तरफ़ पीएसी और सीएजी पर सवाल खड़ा किया गया और अब देश के एटॉर्नी जनरल को सरकार की गलतियों को छुपाने वाला मोहरा बना दिया गया.

रूबी अरुण

भारत के एटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती सवालों के घेरे में हैं. उनकी क़ानूनी सलाहों को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है. देश के शीर्ष क़ानूनी पद पर बैठे वाहनवती की संदिग्ध भूमिका से सरकार की प्रतिष्ठा और आमजनों के विश्वास को ठेस पहुंची है. सवाल यह है कि क्या भारत के एटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती और गृह मंत्री पी चिदंबरम की टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में वाकई कोई भूमिका है? क्या इस मामले के मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और डी बी रियलिटी के पार्टनर शाहिद बलवा द्वारा इन दोनों पर लगाए गए आरोप सच हैं? क्या वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी अभी तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें इस घोटाले की हक़ीक़त और सूत्रधारों की वास्तविकता मालूम है? हालांकि गुलाम ई वाहनवती और पी चिदंबरम अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर चुके हैं, लेकिन देश के शीर्ष क़ानून अधिकारी गुलाम ई वाहनवती और गृह मंत्री पी चिदंबरम से जुड़े जो पुख्ता तथ्य हमारे पास हैं, वे इन दोनों को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं. ये चंद वैसी सच्चाइयां हैं, जो पूरे देश की क़ानून व्यवस्था और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा करती हैं.

एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भूमिका से उनके सहयोगी तक ख़फ़ा हैं. महाधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम का इस्तीफ़ा भी इसी की एक कड़ी है. सुब्रह्मण्यम देश के दूसरे सबसे अहम क़ानून अधिकारी के पद पर थे. वह गुलाम ई वाहनवती के कामकाज के तौर तरीक़ों से ख़फ़ा थे. लिहाज़ा गुलाम ई वाहनवती ने संचार मंत्री कपिल सिब्बल से कहकर सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रोहिंगटन नरीमन की नियुक्ति करा ली. चूंकि कपिल सिब्बल पर भी यह आरोप है कि उन्होंने रिलायंस टेलीकॉम को फ़ायदा पहुंचाया है. इसलिए उन्हें भी एक ऐसे क़ानूनी नुमाइंदे की ज़रूरत थी, जो उनका पक्ष उनके मुताबिक़ ही अदालत में रखे. ज़ाहिर है कि यह स्थिति भी गुलाम ई वाहनवती की छवि को दाग़दार करती है.

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. पूछताछ की औपचारिक प्रक्रिया अभी भी जारी है. ए राजा, सिद्धार्थ बेहुरा और शाहिद बलवा ने भारत के महान्यायवादी गुलाम ई वाहनवती का नाम अपने बयान में बतौर आरोपी लिया, लेकिन सीबीआई ने उन्हें अपना गवाह नंबर 32 बना लिया. गृह मंत्री पी चिदंबरम से सवाल-जवाब करने की हिम्मत तो सीबीआई जुटा ही नहीं पाई. यह अलग बात है कि एक पत्र के लीक होने और प्रणव मुखर्जी के क्षुब्ध होने की वजह से तनाव पैदा हुआ और सरकार एक बारगी सकते में आ गई, पर फिर सब कुछ अपनी राह चल पड़ा. लेकिन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की पेशानी पर अभी भी बल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें गृह मंत्री पी चिदंबरम और एटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती की असली भूमिका की जानकारी है.

आइए हम बताते हैं कि क्या हैं वे राज, जो गृह मंत्री और एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संदिग्ध बनाते हैं. गुलाम ई वाहनवती के बेटे हैं एस्साजी वाहनवती. यह भी अपने पिता की तरह वकालत के पेशे में हैं. एस्साजी वाहनवती उस वेदांता कंपनी के विधि सलाहकार हैं, जिसमें गृह मंत्री पी चिदंबरम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे. एस्साजी वाहनवती मुंबई में स्थित एक लॉ फर्म एजेडबी में पार्टनर हैं, जिसमें उनके साथ हैं देश की नामचीन कमर्शियल टैक्स वकील जिया मोदी. जिया मोदी पूर्व एटॉर्नी जनरल सोली जहांगीर सोराब जी की इकलौती बेटी हैं. सोली जहांगीर सोराब जी और गुलाम ई वाहनवती दोनों ही लॉ फर्म एजेडबी के संस्थापक सदस्य हैं. एस्साजी वाहनवती और जिया मोदी के अलावा इस लॉ फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहराम वकील, अजय बहल, अरिहंत पटनी एवं अपूर्वा पटनी भी शामिल हैं. इस लॉ फर्म की ट्रस्टी हैं सोली जहांगीर सोराब जी की पत्नी और इसके मुख्य क्लाइंट्स हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सुनील मित्तल, एमटीएन वेदांता, वोडाफोन, एस्सार जैसे लोग और कंपनियां. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में इन सभी कंपनियों के नाम दर्ज हैं. डी बी रियलिटी के पार्टनर शाहिद बलवा और रिलायंस टेलीकॉम के मालिक अनिल अंबानी दोनों स्वान टेलीकॉम में शेयर होल्डर हैं. स्वान टेलीकॉम पर रिलायंस टेलीकॉम की फ्रंट कंपनी होने का आरोप है. स्वान टेलीकॉम के 9.9 फ़ीसदी हिस्से को डेल्फी को बेचे जाने को लेकर अनिल अंबानी सहित कई लोगों की सीबीआई जांच चल रही है. हालांकि कोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि उसे ऐसा कोई मौखिक या लिखित सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो कि अनिल अंबानी की इस घोटाले में कोई संदिग्ध भूमिका है. लेकिन इसी मामले में शाहिद उस्मान बलवा तिहाड़ जेल में है.

इसके अलावा स्वान टेलीकॉम का नाम ख़ास तौर पर उद्धृत है. दूरसंचार मंत्रालय में सचिव स्तर के एक अधिकारी और भारत के रिटायर्ड वायरलेस एडवाइज़र आर पी अग्रवाल ने अदालत में दिए बयान में यह कहा है कि देश के तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल गुलाम ई वाहनवती ने टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी टीडी सेट को दिए हलफ़नामे में स्वान टेलीकॉम को उच्च प्राथमिकता पर दिखाया था. देश के एक बड़े न्यायविद् कहते हैं कि जब यह बयान अदालत में दर्ज है तो फिर सीबीआई ने गुलाम ई वाहनवती की घोटाले में भूमिका की जांच क्यों नहीं की, उन्हें सीबीआई ने अपना गवाह कैसे बना लिया?

दूसरी बात यह कि जिस स्वान टेलीकॉम की एटॉर्नी जनरल ने पैरवी की, बाद में उसी के ख़िलाफ़ बयान दिया. स्वान का एमडी शाहिद उस्मान बलवा जेल में है, जिसके क़रीबी रिश्ते मराठा छत्रप शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले से हैं, जिसका सबूत हम पिछले अंक में छाप चुके हैं. गुलाम ई वाहनवती भी महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं. तो क्या उस समय वह कृषि मंत्री शरद पवार या सुप्रिया सुले के दबाव में थे या फिर चूंकि जब घोटाले की पृष्ठभूमि बन रही थी, तब कांग्रेस और राकांपा के बीच रिश्ते मधुर थे, इसलिए गुलाम ई वाहनवती ने ऐसा किया. और अब चूंकि कांग्रेस की अपनी सहयोगी पार्टी से खटास बढ़ रही है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए शाहिद बलवा को मोहरा बनाकर शरद पवार को तोड़ने की योजना है. सीबीआई को गुलाम ई वाहनवती की सहभागिता की जांच करते हुए इन सभी मुद्दों पर ग़ौर करना होगा.

गुलाम ई वाहनवती ने देश के शीर्ष क़ानून अधिकारी के तौर पर दिसंबर 2010 में अदालत में दिए गए अपने हलफनामे में ए राजा की सभी कार्रवाइयों को जायज़ ठहराया है और अब वह इन सभी बातों से मुकर रहे हैं. इसके अलावा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा प्रधानमंत्री को 26 दिसंबर, 2007 को लिखे पत्र में इस बात का साफ़ तौर पर ज़िक्र है कि उन्होंने टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर सॉलिसिटर जनरल गुलाम ई वाहनवती और मंत्री समूह के अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी से गहन चर्चा की. एनडीए सरकार द्वारा 2001 में तय की गई नीति पहले आओ पहले पाओ पर अपनी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

विवादों में घिरे वाहनवती

भारत के महान्यायवादी गुलाम ई वाहनवती ने न सिर्फ़ टू जी स्पेक्ट्रम मामले में सरकार की किरकिरी कराई है, बल्कि वह पहले भी अपने फ़ैसलों से सरकार को मुसीबत में डालते रहे हैं. ताज़ा विवाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव की आय से अधिक संपत्ति का सीबीआई में दर्ज मामला है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में एटार्नी जनरल ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ धारा 218 और 120 बी आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि गुलाम ई वाहनवती ने सीबीआई पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वह मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले को रफा-दफा करे. विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि भारत के महान्यायवादी गुलाम ई वाहनवती अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार को अवैध तरीक़े से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

इसके अलावा वाहनवती ने भोपाल गैस त्रासदी के मसले पर भी सरकार की ऐसी तैसी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आधारहीन और अधकचरे तथ्यों की बिना पर गुलाम ई वाहनवती ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर करने की सलाह दे दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. थलसेना अध्यक्ष के उम्र विवाद पर भी उनकी भूमिका ने उनके पद की गरिमा को धूमिल कर दिया है. देश के इस सर्वोच्च क़ानूनी अधिकारी पर यह आरोप भी है कि उन्होंने अपने बेटे एस्साजी वाहनवती को बेजा फ़ायदा पहुंचाने की गरज से सरकारी निर्देशों की अवहेलना की. मामला वेदांता नामक कंपनी से जुड़ा है. गृह मंत्री पी चिदंबरम इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे. गुलाम ई वाहनवती के बेटे एस्साजी वाहनवती वेदांता के क़ानूनी सलाहकार हैं. अगस्त 2010 में वेदांता ने घोषणा की कि वह कैरन इंडिया लिमिटेड की 60 फ़ीसदी हिस्सेदारी ख़रीदना चाहता है. यह फाइल तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल वाहनवती के पास सीधे पहुंच गई. मामला गैस और पेट्रोलियम का था. नियम यह है कि किसी भी राज्य में स्थित गैस पेट्रोलियम के भंडार पर पहले ओएनजीसी का स्वामित्व होता है, लेकिन यहां गुलाम ई वाहनवती के बेटे की वजह से वेदांता की फाइल सीधी केंद्र तक पहुच गई. हालांकि इस मसले पर बाद में बेहद विवाद हुआ और वाहनवती एवं कानून मंत्रालय को इस बात पर सफाई भी देनी पड़ी.

विनोद राय ने कहा है कि सीएजी न केवल सार्वजनिक व्यय, बल्कि सरकार की नीतियों का भी लेखा-जोखा रख सकता है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सीएजी को बाबुओं का सहयोग चाहिए

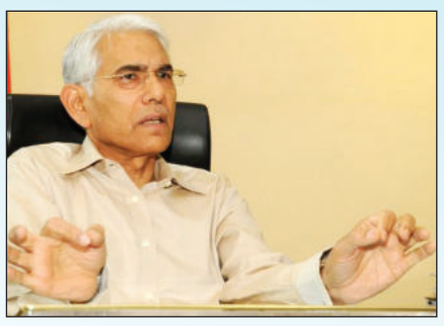

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को कई घोटालों का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, उस पर जनता विश्वास करती है, लेकिन अब वह अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है. इसके लिए निवर्तमान सीएजी विनोद राय ने कई वरिष्ठ बाबुओं का सहयोग लेने की कोशिश शुरू कर दी है. उन्होंने शिमला में एक बैठक की, जिसमें सचिव स्तर के लगभग 10 अधिकारियों को बुलाया गया. बैठक में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों में सीवीसी प्रदीप कुमार, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव सुमित बोस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण सचिव अलका सिरोही आदि प्रमुख थे. विनोद राय ने कहा है कि सीएजी न केवल सार्वजनिक व्यय, बल्कि सरकार की नीतियों का भी लेखा-जोखा रख सकता है. यह बताना तो अभी जल्दबाजी होगा कि विनोद राय अपनी योजना में कितने कामयाब होते हैं, लेकिन अगर वे बाबुओं को विश्वास में ले भी लेते हैं तो नेताओं को अपने साथ करना उनके लिए आसान नहीं होगा.

कैडर का खेल

चंडीगढ़ एक संघ शासित प्रदेश है, लेकिन यहां के कई महत्वपूर्ण पदों पर पंजाब या हरियाणा कैडर के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे उलट दिया गया है. इस संघ शासित प्रदेश के अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर यूटी (यूनियन टेरेटरी) कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है. संघ शासित प्रदेश के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद यूटी सलाहकार का होता है. अभी इस पद पर के के शर्मा हैं, जो 1983 बैच के यूटी कैडर के अधिकारी हैं. उनके पास इसके अलावा आवास और चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार है. यही नहीं, प्रदेश के गृह सचिव राम निवास हरियाणा कैडर के हैं, लेकिन उनके बाद जिन सत्या पाल को उनका चार्ज दिया जाना है, वह यूटी कैडर के हैं. हालांकि पुलिस विभाग में स्थिति अभी पहले जैसी है, लेकिन कहा जा सकता है कि इस परिवर्तन के कारण यूटी कैडर के अधिकारियों का गुस्सा कुछ कम जरूर होगा.

उड़ीसा के परिश्रमी बाबू

उड़ीसा में आई बाढ़ ने बाबुओं का काम बढ़ा दिया है. वैसे तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बाबुओं के प्रति अपने नरम रवैये के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया है. इस बार कई बाबुओं को पूजा की छुट्टी के समय भी काम करना पड़ा, यहां तक कि गांधी जयंती के राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी. दरअसल, नवीन पटनायक विपक्षियों को हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहते. वह जानते हैं कि अगर बाढ़ पीड़ितों की सही तरीके से सहायता नहीं की गई तो विपक्षी दल इसका फायदा उठाएंगे. इसलिए वह राहत कार्यों में तत्परता दिखा रहे हैं. इसके लिए वह बाबुओं के साथ बैठकें और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं. अब जब राज्य के मुखिया इतने व्यस्त हैं तो फिर बाबुओं को फुर्सत कहां होगी.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

कविता संयुक्त निदेशक बनेंगी

1985 बैच की आईएएस अधिकारी डॉ. कविता गुप्ता को विदेश व्यापार महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक बनाया जा सकता है. वह संजय रस्तोगी का स्थान लेंगी.

जयंत को सेवा विस्तार नहीं

1977 बैच के आईएएस अधिकारी जयंत एम मौस्कर का सेवा विस्तार रद्द हो गया है. वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर थे.

होजांग होंगे निदेशक

1995 बैच के आईएएस अधिकारी हारा कुमार होजांग को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग में निदेशक बनाया जाएगा. वह श्यामल मिश्रा की जगह लेंगे, जिन्हें भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) में निदेशक बनाया गया है.

श्रीश जाएंगे यूएआईडी

1989 बैच के आईओएफएस अधिकारी श्रीश कुमार को भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूएआईडी) में निदेशक बनाया जा सकता है. यह पद पहली बार सृजित किया गया है.

प्रदीप चले लंदन

1992 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार यादव अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा रहे हैं. उनकी जगह आईडीएसई अधिकारी दयाल गुप्ता लेंगे.

एटॉर्नी जनरल का असली चेहरा

पृष्ठ एक का शेष

स्वीकृति की मुहर लगाई. गुलाम ई वाहनवती ने ही यह सलाह दी कि जो लोग शाम के साढ़े चार बजे तक लेटर ऑफ इंटेट पेश करेंगे, उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल गुलाम ई वाहनवती ने कट ऑफ डेट और अन्य शर्तों को देखने के बाद ही अपनी मंजूरी दी थी.

प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में जब विस्तृत ब्योरा मांगा तो प्रणव मुखर्जी ने उन्हें पत्र तो लिखा, पर आश्चर्यजनक बात यह रही कि उन्होंने उस पत्र में ए राजा के साथ हुई अपनी बैठक का ज़िक्र तक नहीं किया. यह पत्र 26 दिसंबर, 2007 को लिखा गया, लेकिन प्रणव मुखर्जी को इसकी रिसीविंग 3 जनवरी, 2008 को मिली. 10 जनवरी, 2008 को 15 कंपनियों को 121 लाइसेंसों के लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए और 15 जनवरी, 2008 को चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा कि राजा ने जो किया, वह अध्याय बंद है. 30 जनवरी, 2008 को राजा ने चिदंबरम के साथ ऑपरेटरों की संख्या और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को सुरक्षित करने की ज़रूरत के बारे में चर्चा की. 4 जुलाई, 2008 को प्रधानमंत्री, चिदंबरम और राजा ने स्पेक्ट्रम शुल्क और 6.2 मेगाहर्ट्ज के परे क़ीमत पर चर्चा के लिए बैठक की. 23 सितंबर, 2008 को स्वान ने एतिसलात के साथ सौदा किया और एक महीने बाद ही यूनिटेक ने टेलीनॉर के साथ सौदा कर लिया. मतलब यह कि स्वान टेलीकॉम की यह बेधड़क सौदेबाज़ी गुलाम ई वाहनवती की सिफारिशों की वजह से ही मुमकिन हो सकी.

तारीखी पत्र बताते हैं कि टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले से जुड़ी सभी जानकारियां गुलाम ई वाहनवती, पी चिदंबरम और प्रधानमंत्री को थीं. प्रणव मुखर्जी को भी इन फ़ैसलों से वाक़िफ़ कराया गया, फिर भी गड़बड़ियां होती रहीं. आख़िर वजह क्या रही? वजह रहे गुलाम ई वाहनवती. पहले तो उन्होंने पहले आओ पहले पाओ के मसौदे को मंजूरी दी. फिर जब राजा ट्राई एक्ट के सेक्शन 11 का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रहे थे, तब भी देश के महान्यायवादी होने के नाते उन्होंने विधि मंत्रालय को सतर्क नहीं किया. अक्टूबर 2007 में राजा ने ट्राई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर स्वान, यूनिटेक और एस टेल को अपनी इक्विटी बेचने की इजाज़त दी, तब कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने आंखें क्यों बंद कर रखी थीं और आज क़ानून मंत्री के तौर पर वह फिर चुप हैं. गुलाम ई वाहनवती सभी फ़ैसलों से वाक़िफ़ होते हुए भी ख़ामोश क्यों रहे?

अब बात करते हैं इस घोटाले की

एटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती

वजह से हुए सरकारी राजस्व के नुक़सान की. सीबीआई ने जो आरोप पत्र तैयार किया है, उसमें उसने एक ही आरोप पत्र में ए राजा, यूनिटेक के संजय चंद्रा और स्वान के शाहिद बलवा सहित 14 नाम रखे हैं. हैरानी की बात यह भी है कि संजय चंद्रा और शाहिद बलवा, जो बिल्डर होने के नाते व्यवसायिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं, के बीच साठगांठ दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके सबूत अभी तक नहीं मिले हैं. राजा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 12 कंपनियों को औने-पौने दामों पर स्पेक्ट्रम जारी किया, पर अब सिर्फ़ दो कंपनियों को ही सरकारी राजस्व के नुक़सान का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है. यहां सरकारी राजस्व के नुक़सान के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उनमें भी भिन्नता है.

पिछले साल नवंबर में जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इसका आकलन किया तो इसके लिए ट्राई को आधार बनाया. ट्राई ने कहा कि टू जी असल में 2.75 जी स्पेक्ट्रम या जो 3-जी स्पेक्ट्रम से बहुत अलग नहीं था और इसके लिए पिछले वर्ष की गई 3-जी नीलामी को आधार माना जाए तो नुक़सान 1,76,645 करोड़ रुपये तक का हो सकता है. अगर सत्यम, बोफोर्स और कॉमनवेल्थ खेल आदि घोटालों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उस कुल रकम से भी यह रकम कई गुना ज़्यादा है, लेकिन पेंच इसमें भी है. 2008 में सीबीआई ने कहा था कि ए राजा की वजह से जो नुकसान हुआ, वह 20,000 करोड़ रुपये का ही था. जबकि इस साल की शुरुआत में सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाख़िल किया, उसमें इसे बढ़ाकर 30,984.55 करोड़ रुपये कर दिया गया. जब प्रवर्तन निदेशालय ने अपना अनुमान पेश किया तो यह रकम बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो गई. उस पर तुर्रा यह कि जब प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया तो कहा कि टू जी स्पेक्ट्रम की बिक्री से सरकार को नुक़सान नहीं हुआ है. गृह मंत्री और स्पेक्ट्रम बिक्री के वक़्त वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने भी यही बात कही. संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इसी बात को दोहराया.

देश की सर्वोच्च अदालत के एक न्यायविद् कहते हैं कि ए राजा को शुरू से ही पता था कि वह जो कर रहे हैं, वह पूरी तरह ग़लत है, पर वह निश्चिंत हैं, क्योंकि तमाम घटनाक्रमों पर नज़र डालें तो यह लगता है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि भारत के महान्यायवादी की भूमिका भी उन्हीं की तरह है. इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि लापरवाहियां गुलाम ई वाहनवती से भी हुई हैं. यही वजह है कि राजा अदालत में अपना पक्ष खुद रखने की तैयारी में हैं, क्योंकि खुद राजा को देश की क़ानून व्यवस्था और अदालती प्रक्रिया पर यकीन नहीं है. उनका मानना है कि अगर कोई दूसरा वकील अदालत में उनका पक्ष रखेगा तो वह मामला बिगाड़ सकता है. सच सामने आने के लिए यह ज़रूरी भी है, क्योंकि देश के शीर्ष कानूनी पद पर बैठे व्यक्ति पर आरोप लगे हैं. यह न सिर्फ़ कानूनी प्रक्रिया की अस्मिता, बल्कि देश के आम आदमी की क़ानून और न्यायिक व्यवस्था पर आस्था का भी सवाल है, जिसका जवाब मिलना ही चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

शरद पवार

शाहिद बलवा

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 34
दिल्ली, 31 अक्टूबर-06 नवंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने 6 सितंबर, 2004 को एनसीईआरटी के निदेशक का पद संभाला था, इस हिसाब से उन्हें सितंबर 2009 में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें मार्च 2010 तक सेवा विस्तार दे दिया गया.

सरकार क्यों चाहती है एनसीईआरटी बंद हो

पिछले एक साल से भी अधिक समय से एनसीईआरटी का न तो कोई निदेशक है और न सचिव. 300 से अधिक एकेडमिक स्टाफ की सीटें ख़ाली हैं. पूर्व निदेशक प्रो. कृष्ण कुमार के ख़िलाफ़ सीवीसी से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायतें भेजी गईं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. कपिल सिब्बल देश की इस महत्वपूर्ण संस्था की समस्याओं को हल करने के बजाय कहते हैं कि वह एनसीईआरटी को जल्द ही एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवा देंगे. आख़िर क्यों? हालात बता रहे हैं कि सरकार एनसीईआरटी को शायद बंद कर देना चाहती है. क्या देश को एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं रही, इस संस्था के साथ बार-बार खिलवाड़ क्यों किया जाता है?

डॉ. क़मर तबरेज़

देश जब आज़ाद हुआ तो 1961 में इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना की गई कि यह संस्था भारत सरकार को शिक्षा से संबंधित सुझाव देगी और बताएगी कि देश के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए. इसके तहत शिक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई, जिनके ज़िम्मे यह काम सौंपा गया कि वे देश-विदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करके यह मालूम करें कि देश के बच्चों की शिक्षा किस स्तर पर की जाए, ताकि वे देश के विकास में अपना किरदार निभा सकें. शिक्षा विशेषज्ञों की इस टीम को हर पांच साल के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जिसकी बुनियाद पर केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा सकें. इस प्रकार एनसीईआरटी का काम केंद्रीय स्तर पर एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना था, जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके. विशेषज्ञों की टीम ने जब पाठ्यक्रम तैयार करने का काम पूरा कर लिया तो फिर यह समस्या सामने आई कि अब किताबें कैसे तैयार की जाएं. इसी को मद्देनज़र रखते हुए एनसीईआरटी के अंदर ही विषयों के हिसाब से विभिन्न विभाग बनाए गए, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इतिहास विभाग, भाषा विभाग और प्राथमिक शिक्षा विभाग आदि. इन विभागों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज़ पर लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स की नियुक्तियां की गईं, ताकि वे अपने-अपने विषयों पर शोध कार्य करें और देश के अन्य शैक्षिक संस्थानों के एकेडमिक स्टाफ के सहयोग से एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें तैयार करें. एनसीईआरटी के अंदर ही एक प्रकाशन विभाग बनाया गया, जिसे किताबों के प्रकाशन और फिर उन्हें सीबीएससी बोर्ड और देश के विभिन्न राज्यों के बोर्डों के तहत चलने वाले स्कूलों तक भेजने का काम सौंपा गया.

एनसीईआरटी अपना यह काम पिछले 50 वर्षों से ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करती आई है. यहां पर तैयार होने वाली किताबों की गुणवत्ता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा एनसीईआरटी की किताबों को ही प्राथमिकता देते हैं और फिर कामयाब होकर आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी बनते हैं. इसके अलावा एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किताबों को यूनिसेफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से भी मान्यता मिल चुकी है. यहां की किताबें खाड़ी और अफ्रीकी देशों के कई स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल की गई हैं. इन सभी सच्चाइयों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों से देश की इस महत्वपूर्ण शैक्षिक और अनुसंधानिक संस्था के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है. क्या देश को अब एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, क्या हमारे यहां विद्वानों एवं शिक्षा विशेषज्ञों का अभाव हो गया है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार को सरकार ने जे एस राजपूत के बाद यहां का निदेशक बनाकर भेजा था, ताकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण संस्था में जो गड़बड़ियां की थीं, उनका निवारण किया जा सके, जैसे राजपूत पर सबसे बड़ा आरोप यह था कि वह एनसीईआरटी के निदेशक के पद पर रहते हुए शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा रिश्ता रहा है, ख़ासकर उन पर एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तकों को संघ के नज़रिए से लिखवाने का आरोप लगा. लेकिन कृष्ण कुमार ने भी अपने ढंग से मनमानी शुरू कर दी. इनके ख़िलाफ़ सीवीसी से लेकर प्रधानमंत्री तक भी शिकायतें लिखकर भेजी गईं, लेकिन न कोई जांच हुई और न कोई पूछताछ की गई.

चौथी दुनिया के पास एनसीईआरटी के स्टाफ द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्रों की प्रतियां मौजूद हैं, जिनमें यह अपील की गई है कि संस्था में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर रोक लगाकर इसे बचाया जाए, लेकिन सरकार ने इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया. आख़िर सरकार इस संस्था को बर्बाद करने पर क्यों तुली है, वह इसकी समस्याएं हल करने में कोई रुचि क्यों नहीं ले रही है? ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि सरकार को देश के बच्चों के भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है. वह नहीं चाहती कि देश का हर बच्चा मूल और बेहतर शिक्षा हासिल करे. यह तो सरासर क़ानून और संविधान का उल्लंघन है. चौथी दुनिया की जांच से पता चला कि पिछले कई वर्षों से एनसीईआरटी के एकेडमिक स्टाफ की कुल 630 सीटों में से 371 सीटें ख़ाली हैं. ज़ाहिर है, इस वजह से एनसीईआरटी का बुनियादी काम प्रभावित हो रहा है. न तो शोधकार्य ठीक ढंग से हो पा रहे हैं और न पाठ्य पुस्तकें समय पर तैयार हो पा रही हैं. पिछले दिनों जब स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर एनसीईआरटी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल यहां आए तो बजाय इसके कि वह इसकी समस्याओं को हल करने की बात करते, उन्होंने कहा कि वह एनसीईआरटी को बहुत जल्द एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल देंगे. हालांकि 1972 के एक प्रस्ताव के अनुसार, एनसीईआरटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से ही हासिल है. यहां के एकेडमिक स्टाफ को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हैं, जो देश के आम केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टाफ को मिलती हैं. उन्हें वेतन यूजीसी के नियमानुसार मिलता है, नियुक्ति और सेवानिवृत्ति भी यूजीसी के नियम-क़ानून के अनुसार होती है, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यहां के स्टाफ के सामने और भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, इसलिए वह मंत्रालय के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर है. हुआ यह कि देश में छठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद यूजीसी ने अपने नियम-क़ानून में संशोधन करते हुए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्टाफ की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी और साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं भी एक पैकेज के रूप में दे दीं. एनसीईआरटी के एकेडमिक स्टॉफ को भी ये तमाम सुविधाएं क़ानूनन मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यहां के स्टॉफ को यूजीसी के पूरे पैकेज का लाभ

जिस समय एकेडमिक स्टाफ की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की गई थी, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 27 जुलाई, 1998 को जारी अपने नोटिफिकेशन नंबर 1-22/97 यूआई द्वारा एनसीईआरटी के रेगुलेशन 41 की बुनियाद पर यहां के एकेडमिक स्टाफ की भी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी थी. इसलिए अब जबकि यूजीसी ने उसमें और विस्तार करके उसे 65 साल कर दिया है तो फिर उसका लाभ एनसीईआरटी के एकेडमिक स्टाफ को लेने से क्यों मना किया जा रहा है.

प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने तमाम नियम-क़ानूनों को नज़रअंदाज़ करते हुए न केवल अपने चहेतों को एनसीईआरटी के विभिन्न विभागों का अध्यक्ष बनाया, बल्कि कई बड़े फ़ैसले भी लिए. 30 जनवरी, 2010 को उन्होंने अपने चहेतों को विभागीय प्रोन्नति के हिसाब से ऊंचे पदों पर नियुक्त किया. 5-8 फरवरी 2010 को लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स के पदों पर नियुक्तियां भी कीं.

उठाने पर रोक लगा दी. ऐसे में 62 वर्ष के बाद यहां के जितने स्टाफ को सेवानिवृत्ति दे दी गई, उन्होंने अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत में मुक़दमा दायर कर दिया है. उनका तर्क है कि अतीत में जिस समय एकेडमिक स्टाफ की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की गई थी, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 27 जुलाई, 1998 को जारी अपने नोटिफिकेशन नंबर 1-22/97 यूआई द्वारा एनसीईआरटी के रेगुलेशन 41 की बुनियाद पर यहां के एकेडमिक स्टाफ की भी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी थी. इसलिए अब जबकि यूजीसी ने उसमें और विस्तार करके उसे 65 साल कर दिया है तो फिर उसका लाभ एनसीईआरटी के एकेडमिक स्टाफ को लेने से क्यों मना किया जा रहा है. चौथी दुनिया के पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उपरोक्त नोटिफिकेशन की प्रति मौजूद है. चौथी दुनिया की जांच यह भी बताती है कि एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर धांधलियां कीं, उनके ख़िलाफ़ सीवीसी और प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायतें भी की गईं, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की. मिसाल के तौर पर कृष्ण कुमार ने प्रोफेसर एम एम चौधरी और प्रोफेसर मृणाल मीरी की नियुक्ति एनसीईआरटी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उस समय की, जब उनकी आयु 75 साल से अधिक हो चुकी थी और इसके लिए उन्हें बतौर वेतन लाखों रुपये दिलवाए गए, जो कि क़ानून और एनसीईआरटी के नियमों का उल्लंघन था. इसी तरह उन्होंने वंदना सिंह और लतिका गुप्ता की नियुक्ति बतौर सलाहकार की, हालांकि ये दोनों महिलाएं किसी दूसरे सरकारी संस्थान में स्थायी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं. प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने 40 चहेते अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी पसंदीदा जगह पर स्थानांतरित कराया, नियम-क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने पसंदीदा लोगों को कई विभागों का अध्यक्ष बनवाया, उन्हें सरकारी आवास दिलाए. ख़ुद निदेशक के लिए एनसीईआरटी परिसर में ही एक बंगला है, लेकिन कृष्ण कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान इस बंगले में रहना कभी पसंद नहीं किया और दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित अपने निवास से एनसीईआरटी आते-जाते रहे, जिसके लिए सरकार को अलग से करोड़ों रुपये ख़र्च करने पड़े. कृष्ण कुमार ने निदेशक बनने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को गुमराह किया कि वह कुछ दिनों तक किसी वजह से एनसीईआरटी में निदेशक के लिए बने बंगले में नहीं रह पाएंगे और बाद में शिफ्ट हो जाएंगे. हद तो तब हो गई, जब उन्होंने इस बंगले को गेस्ट हाउस बनाने की मंज़ूरी एनसीईआरटी के सचिव से प्राप्त कर ली, हालांकि सचिव को यह अधिकार नहीं है, ऐसी अनुमति मंत्रालय से लेनी पड़ती है.

एनसीईआरटी के एकेडमिक स्टाफ ने 2008 में जब निदेशक के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को एक शिकायती पत्र भेजा तो प्रोफेसर कुमार ने उनमें से 6 लोगों का तबादला एनसीईआरटी के दिल्ली से बाहर स्थित अन्य केंद्रों में कर दिया. इससे नाराज़ होकर उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) का दरवाज़ा खटखटाया तो कैट ने न केवल उनके तबादले पर रोक लगाई, बल्कि निदेशक को जमकर फटकारा भी. प्रोफेसर जे रवींद्रा, जो एनसीईआरटी के सह निदेशक थे, की भी कृष्ण कुमार से कभी नहीं बनी, क्योंकि वह उनके भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाते रहे. आख़िरकार उन्हें इतना परेशान किया गया कि वह अपना पद छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए. इसके बाद प्रोफेसर बी के त्रिपाठी सह निदेशक बने, जो कृष्ण कुमार के चहेते हैं. यह नियुक्ति भी क़ानून का उल्लंघन करके की गई, क्योंकि सह निदेशक के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, जिसके पास बतौर प्रोफेसर पांच वर्ष का अनुभव हो, लेकिन प्रोफेसर त्रिपाठी इस शर्त को पूरा नहीं करते, फिर भी वह एनसीईआरटी के सह निदेशक बने हुए हैं. सचिव का भी यही हाल हुआ. इस पद पर हमेशा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से किसी न किसी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती रही है. मसलन एनसीईआरटी के सभी पूर्व सचिव जैसे आर एस पांडेय, सतेंद्र सिंह, ए के भारद्वाज और अनीता कोल आदि सभी आईएएस अधिकारी थे, लेकिन अनीता कोल के बाद प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने एनसीईआरटी के मुख्य लेखाधिकारी आर के सिंह को यहां का सचिव बना दिया, जो सरासर क़ानून का उल्लंघन था. मार्च 2010 के बाद से यह पद भी ख़ाली पड़ा है. प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने 6 सितंबर, 2004 को एनसीईआरटी के निदेशक का पद संभाला था, इस हिसाब से उन्हें सितंबर 2009 में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें मार्च 2010 तक सेवा विस्तार दे दिया गया. क़ानून यह कहता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता और न कोई नियुक्ति कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने तमाम नियम-क़ानूनों को नज़रअंदाज़ करते हुए न केवल अपने चहेतों को एनसीईआरटी के विभिन्न विभागों का अध्यक्ष बनाया, बल्कि कई बड़े फ़ैसले भी लिए. 30 जनवरी, 2010 को उन्होंने अपने चहेतों को विभागीय प्रोन्नति के हिसाब से ऊंचे पदों पर नियुक्त किया. 5-8 फरवरी 2010 को लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स के पदों पर नियुक्तियां भी कीं. अब जबकि उनके सेवानिवृत्त होने के बाद यानी मार्च 2010 से एनसीईआरटी के निदेशक का पद ख़ाली पड़ा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) के कुलपति प्रोफेसर आर गोविंदा को एनसीईआरटी का निदेशक (प्रभारी) बना दिया है. वर्ष 2008 में एकेडमिक स्टाफ के ख़ाली पदों को भरने के लिए अख़बारों में विज्ञापन दिया गया था, जिसके लिए 17-18 अक्टूबर को साक्षात्कार लिए गए. ज़ाहिर है, लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स के पदों पर इस समय जो नियुक्तियां होंगी, उनका अंतिम फ़ैसला प्रोफेसर आर गोविंदा ही करेंगे, लेकिन क़ानून किसी भी प्रभारी निदेशक को ऐसे फ़ैसले लेने से मना करता है. बावजूद इसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय ख़ामोश है. आख़िर क्यों जानबूझ कर क़ानून का उल्लंघन करने की अनुमति दी जा रही है? लगता है कि सरकार को देश के बच्चों के भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है और वह नहीं चाहती कि एनसीईआरटी का अस्तित्व क़ायम रहे, अन्यथा वह इस मामले में अवश्य कोई प्रभावी क़दम उठाती और देश की इस महत्वपूर्ण संस्था को बचाने की कोशिश करती.

tabrez@chauthiduniya.com

टीम अन्ना में आंतरिक लोकतंत्र के अभाव और कोर कमेटी की बैठक न होने का आरोप लगाते हुए दो सदस्यों ने टीम को गुड बॉय बोल दिया.

बिहार

सरकार के चहेते सिविल सर्जन

नीरज कुमार सिंह

भ्रष्टाचार और विवाद से पूर्णिया सदर अस्पताल का रिश्ता गहराता जा रहा है. यह सिलसिला इसलिए जारी है, क्योंकि सिविल सर्जन राम चरित्र मंडल ख़ुद कई तरह के आरोपों के घेरे में हैं. राज्य सरकार द्वारा नियम-क़ानूनों को ताख पर रखकर मंडल पर की जा रही मेहरबानी शक पैदा करती है. मंडल के फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र का मामला अदालत में विचाराधीन है, पर उनका रुतबा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है. हद तो यह है कि मंडल की जाति से संबंधित कोई रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. कई घोटालों से घिरे मंडल ठाठ से पूर्णिया में जमे हुए हैं. जदयू किसान सभा के प्रदेश सचिव गौतम वर्मा मंडल पर करोड़ों रुपये के दवा घोटाले, महिलाओं के फ़र्ज़ी बंध्याकरण के नाम पर पैसों की निकासी, अमौर रेफरल अस्पताल में 8 लाख एवं के. नगर स्वास्थ्य केंद्र में 6 लाख रुपये के गबन, फर्जी जाति प्रमाणपत्र के सहारे प्रोन्नति और कई अन्य अनियमितताओं-घोटालों में संलिप्तता आदि के आरोप लगाते हैं.

गौतम वर्मा ने एक अप्रैल, 2010 को आईडी संख्या 169/10 के तहत मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उक्त आरोप लगाए. इस पर मुख्यमंत्री सचिवालय के उपसचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी शमीम अहमद ने संदर्भ संख्या-000010710090026 के तहत मामले को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भेज दिया. फिर 15 अप्रैल, 2010 को गौतम वर्मा ने सूचना अधिकार क़ानून के तहत जाति प्रमाणपत्र से संबंधित सूचना मांगी. 31 जुलाई, 2010 को जानकारी दी गई कि संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. आर एन पांडेय के जांच प्रतिवेदन के अनुसार पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉ. आर सी मंडल के फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर सिविल सर्जन के पद पर प्रोन्नति के संबंध में स्थिति यह है कि उक्त आरोप बंकिम चंद्र सिंह द्वारा परिवाद पत्र, दिनांकित 13 फरवरी, 2009 में लगाया गया है और यह विभाग से संबंधित है. चूंकि उक्त मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए विभाग द्वारा डॉ. मंडल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है और मंडल का जाति प्रमाणपत्र स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध नहीं है.

सवाल यह है कि अगर उनका जाति प्रमाणपत्र स्वास्थ्य विभाग में मौजूद नहीं है तो उन्हें सिविल सर्जन पद पर किस आधार पर प्रोन्नति दी गई. गौतम वर्मा ने सूचना अधिकार क़ानून के तहत उपनिदेशक सह लोक सूचना पदाधिकारी स्वास्थ्य सेवाएं से मंडल के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगी. उपनिदेशक डॉ जगदीश सिंह ने जानकारी दी कि आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल के सचिव के पत्र संख्या-1960, 11 अगस्त, 2010 द्वारा डॉ. मंडल के ख़िलाफ़ अनुशासनिक कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है. गौतम वर्मा ने 4 जुलाई, 2011 को

गौतम वर्मा

आर.सी. मंडल

माधव सिंह

एक बार फिर उपनिदेशक से स्पष्टीकरण के संबंध में सूचना मांगी, जिसके जवाब में उपनिदेशक ने जानकारी दी कि पत्र संख्या-1085(9), 14 सितंबर, 2010 द्वारा जो स्पष्टीकारण मांगा गया था, वह अब तक अप्राप्त है. मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र संख्या- 5100344, 20 अप्रैल, 2010 के आलोक में कार्रवाई की जा रही है. उधर पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव ने प्रधान सचिव को भेजे अपने पत्र में बताया कि बिहार प्रदेश जनता दल (यू) किसान सभा के प्रदेश सचिव गौतम वर्मा द्वारा दिए गए परिवाद पत्र के आधार पर डॉ. आर सी मंडल के विरुद्ध जांच का आदेश विभागीय पत्र संख्या-1478, 19 मई, 2009 द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णिया प्रमंडल को मिला था. उन्होंने परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच करके पत्रांक-149, 28 मई, 2010 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया, जिसके अनुसार सभी पांचों आरोपों को सही पाया गया. सीडब्ल्यूजेसे- 18013/2009 के न्यायादेश द्वारा सिविल सर्जन के विरुद्ध लगाए आरोपों की जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है. अत: उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए.

इसके बाद 19 अगस्त, 2011 को राज्य सरकार के अवर सचिव सीताराम मिश्र ने पत्र संख्या-9/आ0-9-06/2010-758 (9) द्वारा डॉ. मंडल से स्पष्टीकरण देने को कहा. पत्र में कहा गया कि विभागीय पत्र संख्या-1085 (9), 14 सितंबर, 2010 के आधार पर क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णिया से कराई गई जांच में आप पर लगे आरोप सही पाए गए हैं. पत्र में एक पखवारे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया, परंतु मंडल द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. इस पर एक बार पुन: 19 अगस्त, 2011 को एक पखवारे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

लोक जनशक्ति पार्टी के ज़िला अध्यक्ष माधव सिंह एवं वरिष्ठ नेता शंकर झा ने भी पूर्णिया के ज़िला पदाधिकारी को पत्र लिखकर सिविल सर्जन राम चरित्र मंडल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. लोजपा नेताओं का कहना है कि सदर अस्पताल भ्रष्टाचार की गंगोत्री है. राम चरित्र मंडल फतवे जाति के हैं और उन्होंने चौपाल जाति (अनुसूचित जाति) के प्रमाणपत्र के आधार पर प्रोन्नति हासिल की. अभी हाल में किशनगंज में तांती जाति के लोगों द्वारा चौपाल जाति बताकर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला प्रकाश में आया है. अस्पताल में आहार वितरण और साफ-सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है. यहां तैनात एक नर्स के पति को ग़लत ढंग से रोगी कल्याण समिति का सदस्य बना दिया गया, उसकी एक एंबुलेंस भी अस्पताल में चल रही है. इस संबंध में जब राम चरित्र मंडल से बातचीत का प्रयास किया गया तो उन्होंने व्यस्तता का बहाना बनाकर मिलने से इंकार कर दिया.

feedback@chauthiduniya.com

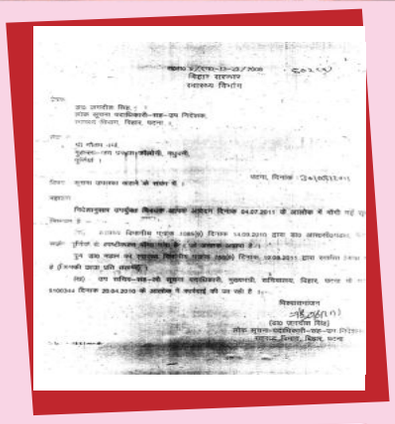

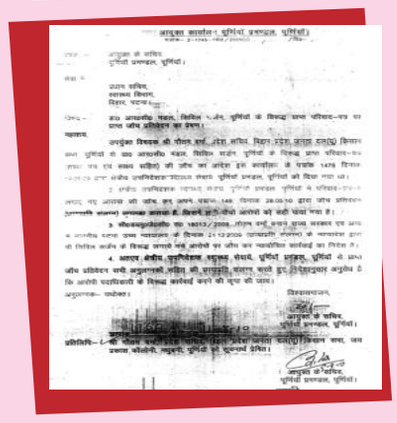

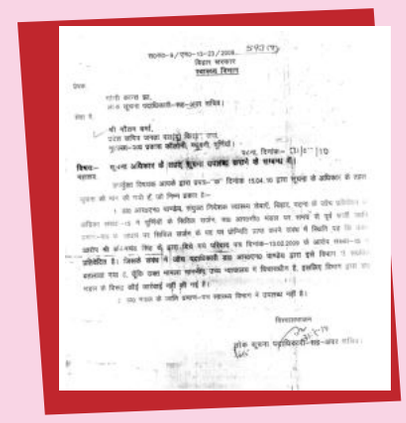

टीम अन्ना में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है

टीम अन्ना ने रामलीला मैदान के आंदोलन बाद जो भी निर्णय लिया या अभियान चलाया, उनसे कई सवाल खड़े होते हैं. सवाल टीम में उस आंतरिक लोकतंत्र का है, जिसकी कमी बताकर टीम अन्ना के सदस्य धीरे-धीरे टीम से बाहर जा रहे हैं. सवाल जनता के उस विश्वास का भी है, जो उसने टीम अन्ना पर किया. क्या टीम अन्ना उस विश्वास की रक्षा कर पाएगी?

शशि शेखर

टीम अन्ना हमेशा कहती रही है कि वह जन लोकपाल की राजनीति कर रही है और राजनीतिक दल चुनावी राजनीति कर रहे हैं. अब जबकि राजनीति हो रही है, भले ही जन लोकपाल के लिए, तब इस बात की ज़रूरत बढ़ जाती है कि टीम अन्ना उस तर्ज पर राजनीति न करे, जिस तर्ज पर देश की अधिकांश पार्टियां करती हैं यानी लोकतंत्र की बात करने वाली किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. टीम अन्ना भी जाने-अनजाने यही गलती कर गई. आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ है कि क्या टीम अन्ना ने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ उन सभी मुद्दों पर चर्चा की, जिनका संबंध इस देश की जनता से है? टीम अन्ना में विभिन्न मुद्दों पर लड़ाई लड़ने वाले संगठनों के लोग शामिल थे. क्या कभी इन लोगों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर सामूहिक चर्चा हुई? इसके अलावा हिसार उपचुनाव में कांग्रेस के विरोध की बात हो या उत्तर प्रदेश के दौरे का निर्णय, इस बारे में कोर कमेटी के सदस्यों के बीच क्या चर्चा हुई, किनकी राय ली गई, इसे टीम अन्ना ने कभी सार्वजनिक नहीं किया. प्रशांत भूषण द्वारा कश्मीर पर दिए गए बयान के बाद टीम अन्ना की कोर कमेटी ने क्या फैसला लिया और कैसे लिया, इस पर भी भ्रम बना रहा.

चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए पी वी राजगोपाल ने कहा था कि अन्ना के आंदोलन से पहले जब वह दिल्ली में 5 हजार लोगों के साथ आए थे, तब और उसके बाद भी अन्ना ने कहा था कि जन लोकपाल के बाद वह हमारे मुद्दे (जल, जंगल और जमीन) पर आंदोलन करेंगे. पी वी राजगोपाल कहते हैं कि इसके बाद ये लोग जन लोकपाल को लेकर व्यस्त हो गए और नवंबर तक इनके पास समय नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने इंतजार करने के बजाय जन संवाद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया. जाहिर है, पी वी राजगोपाल की ये बातें साफ करती हैं कि अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल के लिए टीम अन्ना के बाकी सदस्यों के मुद्दे या राय मायने नहीं रखते.

अन्ना के आंदोलन को भारी जन समर्थन इसलिए मिला, क्योंकि राजनीतिक दलों से बार-बार धोखा खा चुकी जनता को एक अराजनीतिक व्यक्ति अन्ना हजारे में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी. जनता को अन्ना हजारे पर यह भी भरोसा था कि उनकी टीम में आंतरिक लोकतंत्र है, जहां सबकी बात सुनी जाती है और सबकी राय से फैसले लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही यह आंदोलन रामलीला मैदान से बाहर निकला और उसके बाद टीम अन्ना ने जो भी निर्णय लिए, उनसे यह महसूस होने लगा कि अब टीम अन्ना के निर्णय, सामूहिक रूप से चर्चा करने के बजाय, किसी एक या दो व्यक्तियों द्वारा लिए जा रहे हैं. मसलन केंद्र सरकार को लोकपाल बिल पारित करने के लिए जब शीतकालीन सत्र तक का समय दिया गया था तो उससे पहले कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने का निर्णय लेते वक्त क्या सभी सदस्यों से चर्चा की गई या फिर उत्तर प्रदेश में दौरा करने की क्यों जरूरत है, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या इस बारे में कोर कमेटी के सदस्यों की राय ली गई? शायद नहीं.

यही वजह है कि टीम अन्ना के सदस्य एक-एक कर टीम से निकल रहे हैं. टीम अन्ना में आंतरिक लोकतंत्र के अभाव और कोर कमेटी की बैठक न होने का आरोप लगाते हुए दो सदस्यों ने टीम को गुड बॉय बोल दिया. टीम अन्ना के दो प्रमुख सदस्यों, पी वी राजगोपाल और राजेंद्र सिंह ने आंदोलन के राजनीतिक रूप लेने पर आपत्ति जाहिर की. उन्होंने कहा कि कोर कमेटी भ्रम का शिकार हो गई है. हिसार में कांग्रेस विरोधी अभियान शुरू करने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि यह कोर कमेटी का निर्णय नहीं था. पी वी राजगोपाल टीम अन्ना के एक अहम सदस्य थे. जल, जंगल और जमीन पर वंचितों के अधिकार के लिए वह वर्षों से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं. कुछ ही दिनों पहले चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए पी वी राजगोपाल ने कहा था कि अन्ना के आंदोलन से पहले जब वह दिल्ली में 5 हजार लोगों के साथ आए थे, तब और उसके बाद भी अन्ना ने कहा था कि जन लोकपाल के बाद वह हमारे मुद्दे (जल, जंगल और जमीन) पर आंदोलन करेंगे. पी वी राजगोपाल कहते हैं कि इसके बाद ये लोग जन लोकपाल को लेकर व्यस्त हो गए और नवंबर तक इनके पास समय नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने इंतजार करने के बजाय जन संवाद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया. जाहिर है, पी वी राजगोपाल की ये बातें साफ करती हैं कि अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल के लिए टीम अन्ना के बाकी सदस्यों के मुद्दे या राय मायने नहीं रखते. संतोष हेगड़े, जो टीम अन्ना के अहम सदस्य हैं, भी टीम अन्ना के कई बयानों के प्रति अपनी असहमति जता चुके हैं, खासकर आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप को लेकर. और फिर स्वामी अग्निवेश. टीम अन्ना से निकलने या कहें कि निकाले जाने (अब सवाल यह भी है कि टीम से उन्हें निकालने का फैसला कोर कमेटी के सारे सदस्यों ने मिलकर किया या यह किसी एक सदस्य का फैसला था) के बाद उन्होंने कई बार कहा कि टीम अन्ना में लोकतंत्र नहीं है और सारे फैसले बिना राय-मशविरे के ले लिए जाते हैं.

बहरहाल अभी भी वक्त है, अन्ना हजारे चाहें तो जनता के उस विश्वास की रक्षा कर सकते हैं, जो उसने उन पर किया था. जनता के भरोसे को किसी एक या दो सदस्यों की मनमानी की वजह से तोड़ने से वह बच सकते हैं. अन्ना चाहें तो नए या पुराने लोगों को मिलाकर अपनी टीम पुनर्गठित कर सकते हैं. एक ऐसी टीम, जहां हर सदस्य की राय सुनी जाए, जो इस देश के 120 करोड़ लोगों से जुड़ी समस्याओं, मुद्दों पर न केवल बातचीत कर सके, बल्कि उन समस्याओं के समाधान के लिए एक साफ नक्शा भी बना सके. अन्ना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक बार फिर उस जनता के हाथ सिर्फ़ निराशा ही लगेगी, जो पहले ही राजनीतिक दलों से धोखा खा चुकी है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

जानकार इसकी वजह शिवसेना के हिंदुत्व के एजेंडे को मान रहे हैं. इस घटना से सिर्फ़ रामदास अठावले ही परेशान नहीं हैं, उद्धव ठाकरे भी चिंतित हैं.

उत्तर प्रदेश

कांग्रेस को युवराज पर भरोसा नहीं

फ़िरदौस ख़ान

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति अपना स्वरूप लेने लगी है. राहुल गांधी शुरू से यह कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेली चुनाव लड़ेगी. राहुल ने भूमि अधिग्रहण और किसानों की समस्याओं को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में पदयात्रा भी की. मायावती और मुलायम सिंह के प्रभाव का असर यह है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कांग्रेस को अपने युवराज राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है और वह किसी तरह का जोख़िम नहीं लेना चाहती. इसलिए उसने उत्तर प्रदेश में चुनावी समर जीतने के लिए चौधरी अजित सिंह का सहारा लेना बेहतर समझा है. इसके अलावा पार्टी के रणनीतिकार राज्य के ग़ैर भाजपाई क्षेत्रीय दलों से भी समर्थन जुटाने की क़वायद में लगे हैं. अब तक राहुल गांधी यही कहते आए हैं कि प्रदेश में कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, लेकिन ताज़ा गठजोड़ ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में जीतना उसके लिए आसान नहीं है.

हाल में उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय लोकदल को क़रीब 40 सीटें दिए जाने पर सहमति बनी. राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह पहले 80 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने असहमति ज़ाहिर कर दी थी. बाद में अजित सिंह ने सीटों की संख्या 40 कर दी और साथ में केंद्र में मंत्री पद की मांग कर डाली, जिसे कांग्रेस ने मंज़ूर कर लिया. पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह के मुताबिक़, कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर तक़रीबन सभी सीटों पर सहमति बन गई है. इस बात को लेकर भी चर्चा जारी है कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी पहली सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के नाम वापस न लिए जाएं. अजित सिंह ने इस बाबत दिग्विजय सिंह से बात की थी, लेकिन पार्टी की प्रदेश इकाई के ऐतराज़ की वजह से कांग्रेस फ़िलहाल इसे मानने को तैयार नहीं है. दबी ज़ुबान में प्रदेश कांग्रेस के नेता अजित सिंह की मांग को ग़लत बता रहे हैं. उनका कहना है कि पार्टी ने मज़बूत सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. कई सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक हैं. ऐसे में हम अपनी सीटों को कैसे छोड़ सकते हैं. ऐसा करना किसी भी लिहाज़ से पार्टी हित में नहीं होगा. अतरौली और शामली विधानसभा सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है. इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. अतरौली से बृजेंद्र सिंह और शामली से पंकज मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है. अजित सिंह अपनी पार्टी की ओर से राजेश्वर बंसल को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं. हालांकि शुरुआत में अनुराधा चौधरी को चुनाव मैदान में उतारने की बात चल रही थी. वह मुज़फ्फ़रपुर संसदीय क्षेत्र से 2009 में लोकसभा चुनाव हार गई थीं. ग़ौरतलब है कि कांग्रेस ने दो सूचियां जारी की हैं, जिनमें उसने 403 में से 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. दूसरी सूची के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तक़रीबन 100 सीटों पर चर्चा की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन की क़वायद के कारण सिर्फ़ 62 सीटों पर ही उम्मीदवारों की घोषणा की गई. अब नाम वापस लेने पर पहले से घोषित उम्मीदवार बग़ावत कर सकते हैं, जिसका पार्टी को ख़ासा नुक़सान हो सकता है.

अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी सियासी दल चुनावी समर जीतने की क़वायद में जुटे हुए हैं. बहुजन समाज पार्टी को जहां अपनी सत्ता बरक़रार रखने की फ़िक्र है तो वहीं अन्य सियासी दल बसपा को बेदख़ल कर सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते. पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने इतिहास रच दिया था. उसने दिखा दिया था कि दलितों और शोषितों की पार्टी भी शासन कर सकती है. 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के सबसे बड़े सियासी दल के रूप में उभर कर सामने आई थी. उसे 206 सीटें मिली थीं. प्रदेश की सियासत में डेढ़ दशक बाद ऐसा हुआ था, जब किसी एक ही पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाने लायक़ सीटों पर क़ब्ज़ा किया था. किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि बसपा की सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति इतनी कामयाब साबित होगी. मायावती अपने दलित वोट बैंक को खोए बिना ब्राह्मणों और क्षत्रियों को भी अपने ख़ेमे में शामिल करने में कामयाब रही थीं. समाजवादी पार्टी को प्रखर हिंदुत्ववादी नेता कल्याण सिंह का ऐसा साथ मिला था कि उसका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक उससे दूर हो गया था. उसे केवल 97 सीटें मिली थीं और वह प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही. इस चुनाव में भाजपा का पुराना हिंदुत्व का एजेंडा भी काम न आया और उसे 51 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था. देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा. युवराज का रोड शो मतदाताओं को ज़रा भी लुभा नहीं पाया और पार्टी को महज़ 22 सीटें मिल पाई थीं. राष्ट्रीय लोकदल ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

राष्ट्रीय लोकदल अब चौधरी चरण सिंह वाला दल नहीं रह गया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाक़ों तक ही इसका जनाधार है और इसकी हैसियत क्षेत्रीय दल की है. पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था. जहां वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति त्याग कर जातीय समीकरणों के सामने झुकना पड़ा है, वहीं अजित सिंह के सामने भी इस समय दो चुनौतियां हैं. पहली राष्ट्रीय लोकदल को ज़िंदा रखना और दूसरी अपने बेटे जयंत चौधरी के लिए सियासी ज़मीन तैयार करना. इस बार 40 सीटें मिलने से जहां लोकदल की अहमियत बढ़ेगी, वहीं अच्छा प्रदर्शन करने पर अजित सिंह अगली प्रदेश सरकार बनाने में किसी के साथ भी गठजोड़ करने में सक्षम होंगे. अजित सिंह कभी विचारधारा की राजनीति नहीं करते. ऐसे में किसी भी सियासी दल के साथ गठबंधन करने में उन्हें कोई गुरेज़ नहीं है. पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ किया था. उस चुनाव में उनकी पार्टी बागपत, मथुरा, अमरोहा, हाथरस और बिजनौर लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी. इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि केंद्र की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की नीतियों के कारण इस इलाक़े में जहां जनाक्रोश व्याप्त है, वहीं किसान भी आंदोलित हैं. ऐसे में अजित सिंह को कांग्रेस पर होने वाले हमले भी झेलने होंगे और उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने में पसीने छूट जाएंगे. भूमि अधिग्रहण को लेकर राहुल गांधी ने पदयात्रा की, गांव–गांव जाकर लोगों से भावनात्मक रिश्ता क़ायम करने की कोशिश की, दलितों के घर भोजन किया, लेकिन जितना नुक़सान कांग्रेस को अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से हुआ, उतना ही नुक़सान राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने से भी होगा, क्योंकि इस गठबंधन के कारण दलित मतदाताओं पर कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर हो सकती है. हालांकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बाबत रणनीति तैयार करने में जुटा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण हुए नुक़सान की भरपाई कैसे की जाए. इसी क़वायद के तहत कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के दो और दलों के साथ गठबंधन करने जा रही है, क्योंकि वह इस बात को समझ चुकी है कि सिर्फ़ राहुल गांधी को सड़क पर उतार कर चुनाव नहीं जीत सकती.

firdaus@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र

शिव शक्ति-भीम शक्ति पर आशंका के बादल

प्रवीण महाजन

समूचे महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सम्मेलनों एवं सभाओं का आयोजन कर शिव शक्ति-भीम शक्ति की ताक़त का प्रदर्शन किया, राज्य की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तस्वीर बदलने की बातें कही गईं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन चिंतित हो उठा था, लेकिन दशहरे के बाद शिव शक्ति-भीम शक्ति को लेकर आशंका के बादल गहराने लगे हैं.

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की आहट देख सभी सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए घोषणाओं और वादों के पासे फेंके जा रहे हैं. हालांकि इस काम में विपक्षी गठबंधन दिग्भ्रमित नज़र आ रहा है. उसके नेता अपने ही सहयोगी दलों के राजनीतिक मुद्दों की हवा निकालने में लगे हैं. ऐसे में उसके मज़बूत होने के बजाय टूटने के कयास ज़्यादा लगाए जा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास अठावले को शिवसेना ने बड़े ही जोश से गले लगाया था. प्रदेश में इस गठबंधन को शिव शक्ति–भीम शक्ति के नाम से प्रचारित किया गया. समूचे महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सम्मेलनों एवं सभाओं का आयोजन कर शिव शक्ति–भीम शक्ति की ताक़त का प्रदर्शन किया, राज्य की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तस्वीर बदलने की बातें कही गईं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन चिंतित हो उठा था, लेकिन दशहरे के बाद शिव शक्ति–भीम शक्ति को लेकर आशंका के बादल गहराने लगे हैं. ख़ासकर शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं. ऐसे में उनके कार्यकर्ता जिज्ञासा भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहे हैं और भ्रम की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं.

दरअसल रिपब्लिकन पार्टी एवं शिवसेना के कार्यकर्ताओं में भ्रम की यह स्थिति पैदा हुई शिवाजी पार्क में आयोजित दशहरा समारोह से, जिसमें शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने दादर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर चैत्य भूमि रखने और इंदु मिल की ज़मीन अंबेडकर स्मारक के बजाय समाज सुधारक नाना शंकर सेठ स्मारक को देने की सलाह देकर रामदास अठावले की मुश्किल बढ़ा दी है. ख़ास बात यह है कि रामदास अठावले ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन सहित कई अन्य बातों को भुलाकर शिवसेना से हाथ मिलाने का फ़ैसला किया था. इस फ़ैसले का उनके और शिवसेना समर्थकों ने संकोच के साथ स्वागत किया था. राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस गठबंधन को बेमेल बताया था. वजह यह कि दोनों दलों का एजेंडा भिन्न है और विचारधारा में भी तालमेल नहीं बैठता. इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी के विभिन्न गुटों ने भी अठावले के केसरिया खेमे में जाने की कड़ी आलोचना की थी. कांग्रेस द्वारा बार–बार ठगे जाने के कारण शिव शक्ति–भीम शक्ति गठबंधन को एक नई शुरुआत मानकर, आशंकाओं के साथ ही सही, पर आशाभरी नज़रों से देखा जा रहा था. सोचा जा रहा था कि शायद हिंदुत्ववादी यानी शिवसेना की विचारधारा में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने यह भ्रम तोड़ दिया.

भ्रम तो रामदास अठावले का भी टूट गया है. बाला साहब ठाकरे के बयान पर रिपब्लिकन नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. अविनाश महातेकर ने कहा कि इंदु मिल की क़रीब साढ़े बारह एकड़ ज़मीन डॉ. अंबेडकर स्मारक के लिए आरक्षित होनी चाहिए, यह हमारी मांग है. समाज सुधारक नाना शंकर सेठ का हम भी सम्मान करते हैं. उनके स्मारक के लिए कहीं और जगह दी जा सकती है. ज़ाहिर है, इंदु मिल की जगह के प्रति शिवसेना प्रमुख के नए रुख से शिव शक्ति–भीम शक्ति में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक ने चुप्पी साध रखी है. उसके किसी नेता ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है. महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शिव शक्ति–भीम शक्ति गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की बात अभी प्रारंभिक चरण में है, जिसमें शिवसेना प्रमुख के बयान के चलते खलल पड़ गया है.

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गठबंधन के प्रारंभ से ही रामदास अठावले और उनके समर्थक एक साझा एजेंडा या कार्यक्रम तय करने की मांग करते आ रहे हैं, मगर शिवसेना उनकी इस मांग के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती. उसका रवैया रामदास अठावले को सीढ़ी बनाकर दलितों–पिछड़ों के वोट हथियाने के प्रयास जैसा लगता है. जब इस गठबंधन के प्रयास चल रहे थे, तब लोणवाला में हुई रिपब्लिकन नेताओं की एक बैठक में दलित पैंथर के नेता नामदेव ढसाल के नेतृत्व में आरपीआई का एजेंडा बनाने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया था. समिति ने मसौदा बनाकर रामदास अठावले को दिया था, जिसे उन्होंने शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सौंप दिया था. शिवसेना से अपेक्षा की गई थी कि मसौदे पर मिल–बैठकर चर्चा की जाए, लेकिन मसौदे पर कोई चर्चा हुई या नहीं, यह किसी को पता नहीं है. इसके अलावा रामदास अठावले ने जबसे शिव शक्ति–भीम शक्ति का नारा लगाना शुरू किया है, तभी से वह कहते रहे हैं कि यह गठबंधन स्थानीय निकाय या विधानसभा चुनाव तक सीमित न रहे, बल्कि लोकसभा चुनाव भी मिलकर लड़ा जाए, लेकिन अब तक शिव शक्ति–भीम शक्ति का साझा कार्यक्रम मसौदा नहीं बना है और न अब बनने के आसार हैं. जानकार इसकी वजह शिवसेना के हिंदुत्व के एजेंडे को मान रहे हैं. इस घटना से सिर्फ़ रामदास अठावले ही परेशान नहीं हैं, उद्धव ठाकरे भी चिंतित हैं. अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए शिवसेना जद्दोजहद कर रही है. जबसे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया है, तबसे शिवसेना कमज़ोर पड़ती जा रही है. इसीलिए उद्धव ने रामदास अठावले को अपने साथ लेकर आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में दलितों–पिछड़ों के वोट हासिल कर जीत की रणनीति बनाई थी. इसके अलावा यदि शिव शक्ति–भीम शक्ति गठबंधन अगले विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करता तो ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना भी संजो रखा था, लेकिन अब उन्हें यह गठबंधन क़ायम रखने की चिंता सता रही है.

उनकी दूसरी चिंता यह है कि भाजपा ने अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं. उसकी मनसे से बढ़ती नज़दीकियों को लेकर उद्धव आशंकित हैं. अपने पिता के बेबाकपन पर भी उनका कोई वश नहीं है, इसलिए इस गठबंधन के टिके रहने पर सवालिया निशान लग गया है. एक चीज और साफ हो गई है कि शिवसेना के पास आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बयानबाज़ी के अलावा कोई रणनीति नहीं है. शिव शक्ति–भीम शक्ति को लेकर राजनीतिक गलियारे में जो अटकलबाज़ी शुरू हुई है, उससे सत्तारूढ़ गठबंधन ख़ुश है. अन्ना के आंदोलन से चिंतित कांग्रेस और राकांपा के नेताओं ने अब विपक्षी गठबंधन की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है. विशेषकर कांग्रेस ने रामदास अठावले को छोड़कर अन्य रिपब्लिकन नेताओं को अपने साथ जोड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ने सबसे पहले इसी साल अप्रैल में (सरकार ने देश को बेच डाला-26 लाख करोड़ का महाघोटाला) भारत के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था.

कोयला महाघोटाला

सरकार और विपक्ष ख़ामोश क्यों है

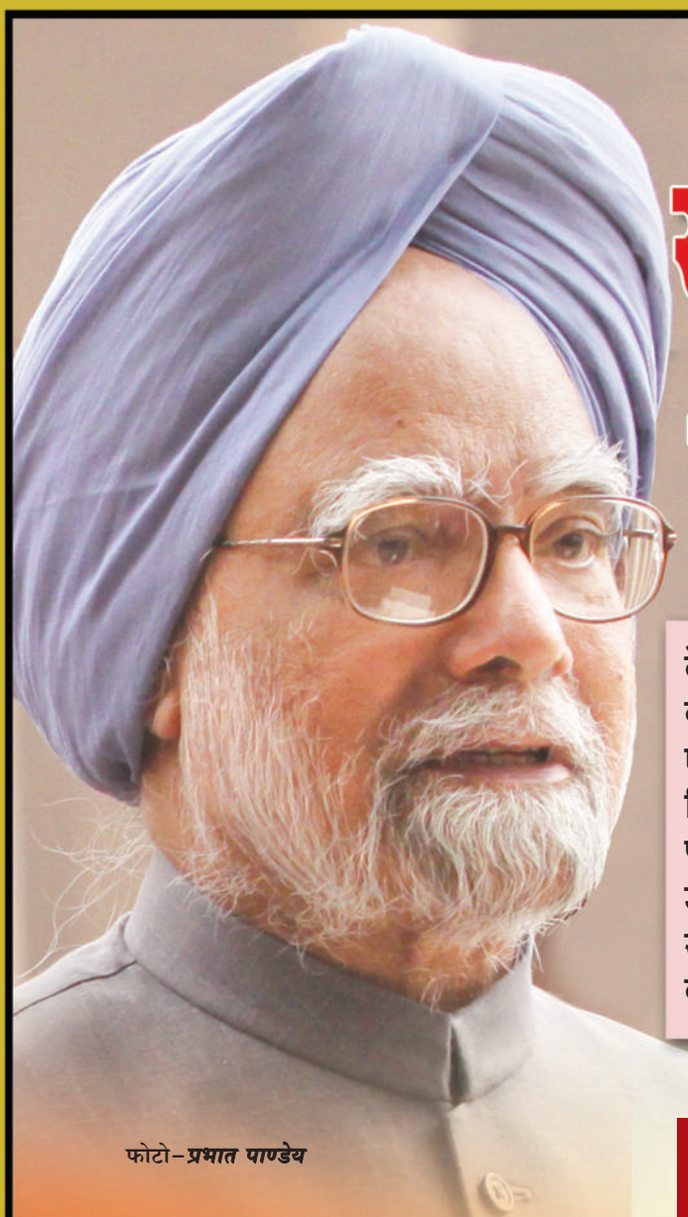

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

देश भर में कोयले की लूट मची है और कोयला कारोबार में 50 फ़ीसदी भ्रष्टाचार है. यह बात ख़ुद कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल मान रहे हैं. पिछले दिनों चौथी दुनिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने 26 लाख करोड़ रुपये के कोयला महाघोटाले का पर्दाफाश किया था, लेकिन जो मंत्री महोदय भ्रष्टाचार की बात कबूल कर रहे हैं, वह कार्रवाई के नाम पर ख़ामोश क्यों है? इस भ्रष्टाचार की वजह से बिजली उत्पादन बाधित हो रहा है. उद्योग-धंधों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, पर सरकार की पेशानी पर बल तक नहीं. सरकार 2-जी स्पेक्ट्रम की आंच में जल रही है. वह जानती है कि अगर कोयला घोटाले की चिंगारी फूटी तो यूपीए सरकार की बची-खुची साख भी जलकर राख हो जाएगी.

सीएजी चुप क्यों है?

1993 से लेकर 2010 तक कोयले के 208 ब्लॉक बांटे गए, यह 49.07 बिलियन टन कोयला था. इनमें से 113 ब्लॉक निजी क्षेत्र और 184 ब्लॉक निजी कंपनियों को दिए गए और यह 21.69 बिलियन टन कोयला था. अगर बाज़ार मूल्य पर इसका आकलन किया जाए तो 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस कोयले का मूल्य 5,382,830.50 करोड़ रुपये निकलता है. अगर इसमें से 1250 रुपये प्रति टन घटा दिया जाए, यह मानकर कि 850 रुपये उत्पादन की लागत है और 400 रुपये मुनाफ़ा, तो भी देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ. देश की खनिज संपदा, जिस पर 120 करोड़ भारतीयों का समान अधिकार है, को इस सरकार ने लगभग मुफ्त में बांट दिया. अगर इसे सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया अपना कर बांटा जाता तो देश को इस घोटाले से हुए 26 लाख करोड़ रुपये के राजस्व घाटे से बचाया जा सकता था और यह पैसा देशवासियों के हितों में ख़र्च किया जा सकता था. यह आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होने का गौरव भी इसे ही मिलेगा. तहक़ीक़ात के दौरान चौथी दुनिया को कुछ ऐसे दस्तावेज़ हाथ लगे, जो चौंकाने वाले ख़ुलासे कर रहे थे. इन दस्तावेज़ों से पता चलता है कि इस घोटाले की जानकारी सीएजी (कैग) को भी है. तो सवाल यह उठता है कि अब तक इस घोटाले पर सीएजी चुप क्यों है?

अभी हाल में कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी कोयले के कारोबार में 50 फ़ीसदी भ्रष्टाचार है. उन्होंने इस क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार को ऐतिहासिक बताया. वह कहते हैं कि देश में बिजली की कमी की सबसे बड़ी वजह कोयले की डिमांड, सप्लाई और क्वालिटी से जुड़ी है. वह यह भी मान रहे हैं कि कोल सेक्टर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों के बीच टकराव है और इस टकराव में निजी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर भारी पड़ रही हैं. दूसरी ओर कैग ने कोयला मंत्रालय को रिलायंस पावर लिमिटेड को 1 लाख 20 हज़ार करोड़ रुपये के कोयले का फ़ायदा पहुंचाने का दोषी पाया है. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक़, सरकार ने कोयला लाइसेंस के नियमों में बदलाव करके रिलायंस को यह अधिकार दे दिया कि वह अपने सरप्लस कोयले को अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर ले. बहरहाल, मंत्री महोदय यह सब कुछ मानते और जानते हुए भी कार्रवाई के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है या क्या करेगी के बजाय राज्यों से अपनी सोच बदलने की बात कहते हैं. कोयले जैसे महत्वपूर्ण संसाधन की लूट जिस तरह इस देश में हुई है और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला इस देश में हुआ है, उसके आगे 2-जी स्पेक्ट्रम जैसा घोटाला भी बौना साबित होगा, लेकिन कोयला मंत्री जांच कराने की जगह सिर्फ़ बयानबाज़ी कर रहे हैं. चौथी दुनिया ने सबसे पहले इसी साल अप्रैल में (सरकार ने देश को बेच डाला-26 लाख करोड़ का महाघोटाला) भारत के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था. इस घोटाले में कोल ब्लॉक आवंटन के नाम पर क़रीब 26 लाख करोड़ रुपये की लूट हुई. दिलचस्प रूप से यह आवंटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में और उस वक़्त हुआ, जब वह कोयला मंत्रालय भी देख रहे थे यानी कोयला मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास था. कोयले को काला सोना कहा जाता है, लेकिन सरकार ने इस काले सोने की बंदरबांट कर डाली और अपने प्रिय-चहेते पूंजीपतियों एवं दलालों को मुफ्त ही दे दिया था. नतीजतन देश को 26 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान उठाना पड़ा.

चौथी दुनिया ने सबसे पहले कोल ब्लॉक आवंटन में महाघोटाले का पर्दाफ़ाश किया था.
(सरकार ने देश को बेच डाला-26 लाख करोड़ का महाघोटाला)

जब 2-जी मामले में फंसी सरकार को यह लगा कि कोयला महाघोटाला उसके लिए एक और परेशानी का सबब बन सकता है, तब कोयला मंत्रालय ने दिखावे के लिए कुछ कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की. कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा था कि पिछले एक दशक में क़रीब 208 कोल ब्लॉक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को आवंटित किए गए थे, जिनमें से कई कंपनियों का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के तहत उनकी लीज निरस्त करने की बात भी थी, लेकिन कार्रवाई महज कुछ कंपनियों के ख़िलाफ़ हुई. एनटीपीसी को आवंटित 5 कोल ब्लॉक निरस्त कर दिए गए, लेकिन निजी क्षेत्र की डिफाल्टर कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से सरकार बचती रही. दूसरी ओर आज देश में जिस मात्रा में कोयले की मांग बढ़ी है, उस मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है. इसकी एक बड़ी वजह वे कंपनियां हैं, जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे, लेकिन जिन्होंने वहां उत्पादन शुरू नहीं किया, सरकार ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी नहीं की.

दरअसल, कोयले के ब्लॉक आवंटन में कुछ शर्तें भी होती हैं. मसलन, जिन खदानों में कोयले का खनन सतह के नीचे होना है, उनमें आवंटन के 36 माह बाद (और यदि खदान वन क्षेत्र में है तो यह अवधि छह महीने बढ़ा दी जाती है) खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए. यदि खदान ओपन कास्ट किस्म की है तो यह अवधि 48 माह की होती है (जिसमें वन क्षेत्र हो तो पहले की तरह ही छह महीने की छूट मिलती है). अगर इस अवधि में काम शुरू नहीं होता है तो खदान मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. समझने वाली बात यह है कि इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है, ताकि खदान और कोयले का उत्खनन बिचौलियों के हाथ न लगे, लेकिन सरकार ने ऐसी कई खदानों का लाइसेंस रद्द नहीं किया, जो इस अवधि के भीतर उत्पादन शुरू नहीं कर पाईं. ऐसा इसलिए, क्योंकि आवंटन के समय बिचौलियों को बहुत बड़ी संख्या में खदानें आवंटित की गई थीं, ताकि वे उन्हें आगे चलकर उद्योगपतियों को आसमान छूती क़ीमतों पर बेच सकें. इसके अलावा जब कोयले की क़ीमत बढ़ जाए, तब उत्पादन शुरू हो और मनमानी क़ीमतों पर कोयले की बिक्री की जा सके. ज़ाहिर है, यह सब गोरखधंधा सरकार की जानकारी में हुआ और हो रहा है, फिर भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसे क्या कहेंगे?

दरअसल, केंद्र सरकार ने माइंस और मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 में संशोधन करने की बात कही थी और इस बीच कोई भी कोयला खदान आवंटित न करने का वादा किया था. 2006 में यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया और माना गया कि जब तक दोनों सदन इसे मंजूरी नहीं देते और यह बिल पारित नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी, लेकिन यह बिल चार सालों तक लोकसभा में जानबूझ कर लंबित रखा गया और 2010 में ही यह क़ानून में तब्दील हो पाया. इस दरम्यान संसद में किए गए वादे से सरकार मुकर गई और कोयले के ब्लॉक बांटने का गोरखधंधा चलता रहा. 2006-07 की बात है, जब शिबू सोरेन जेल में थे और प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोयले के संशोधित क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में सबसे अधिक तेजी से बांटा गया. सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोयला खदानें सिर्फ़ 100 रुपये प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज़ में बांट दी गईं. ऐसा तब किया गया, जब कोयले का बाज़ार मूल्य 1800 से 2000 रुपये प्रति टन के ऊपर था. असल में इस विधेयक को लंबित रखने की राजनीति बहुत गहरी थी. इस विधेयक में साफ़-साफ़ लिखा था कि कोयले या किसी भी खनिज की खदानों के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अगर यह विधेयक लंबित न रहता तो सरकार अपने चहेतों को मुफ्त कोयला कैसे बांट पाती. इस समयावधि में लगभग 21.69 बिलियन टन कोयले के उत्पादन क्षमता वाली खदानें निजी क्षेत्र के दलालों और पूंजीपतियों को मुफ्त दे दी गईं. इस दरम्यान प्रधानमंत्री भी कोयला मंत्री रहे और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं के नीचे कोयले के सबसे अधिक ब्लॉक बांटे गए. ऐसा क्यों हुआ? इन चार सालों में लगभग 175 ब्लॉक आनन-फानन में पूंजीपतियों को दे दिए गए. चौथी दुनिया ने ही सबसे पहले इस घोटाले को सामने लाने का काम किया था और बताया था कि कैप्टिव ब्लॉक (कोयले का संशोधित क्षेत्र) के नाम पर कोयले को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की नीति से किस तरह इस देश के संसाधन और राजस्व को लूटने की छूट दे दी गई.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... भाजपा का संकट ...धीर

केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बुंदेलखंड में 4 लाख 42 हज़ार 299 हेक्टेयर मीटर भूमिगत पानी बचा है.

बुंदेलखंड

फटती धरती, कांपते लोग

सुरेंद्र अग्निहोत्री

बुंदेलखंड में बेतरतीब ढंग से खनन और भूजल दोहन के चलते ख़तरे की घंटी बज चुकी है. हमीरपुर में सबसे अधिक 41 हज़ार 779 हेक्टेयर मीटर प्रतिवर्ष भूजल दोहन हो रहा है. महोबा, ललितपुर एवं चित्रकूट में खनन माफ़िया नियम-क़ायदों को तिलांजलि देकर पहाड़ के पहाड़ समतल भूमि में बदल रहे हैं. ललितपुर में डायस्फोर, पैराप्लाइट, राक फास्फेट, ग्रेनाइट एवं इमारती पत्थरों के भंडार हैं. उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक के बावजूद वन क्षेत्र वाले जनपदों में इमारती पत्थरों का खनन जारी है. यमुना, बेतवा और केन में बालू माफ़ियाओं ने नदी के पेटे को चीर डाला है. खनन माफ़िया और नेता काले कारोबार से ख़ूब फल-फूल रहे हैं, जनता ने मजबूरन आत्महत्या को मुक्ति का पर्याय समझ लिया है. वर्ष 2010-11 में भारत सरकार के भूगर्भ निदेशालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 72 में से 40 ज़िले अति दोहित की श्रेणी में हैं. यहां पानी का भंडार घट रहा है. आंकड़ों के अनुसार, यहां प्रतिवर्ष एक लाख 92 हज़ार हेक्टेयर मीटर पानी का दोहन किया जा रहा है, जबकि भूगर्भ जल विकास दर दोहन की अपेक्षा अत्यंत कम है. बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर में भूगर्भ जल उपलब्धता 20 लाख 24 हज़ार 627 हेक्टेयर बताई गई है, जिसमें सबसे कम भूगर्भ जल हमीरपुर (महोबा सहित) में उपलब्ध है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमीरपुर के अलावा ललितपुर, झांसी और जालौन में जल संकट बरसात की कमी के कारण हुआ है. बुंदेलखंड पर गहरी नज़र रखने वाले शिव प्रसाद भारती बताते हैं कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 21 ज़िलों में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है. हमीरपुर यमुना और बेतवा के मध्य बसा है.

बुंदेलखंड अपनी वन संपदा, खनिज संपदा और शूरवीरता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है. पानी की कमी, ग़रीबी और भुखमरी यहां की मुख्य समस्याएं हैं. पिछले चार-पांच सालों से यहां धरती फटने की नई समस्या पैदा हो गई है, जिसने किसानों को संकट में डाल दिया है. बीते 14 जून को हमीरपुर के मदारपुर गांव में एक अजीब घटना हुई. रात में 700 मीटर लंबाई में धरती फट गई, जिसकी चौड़ाई ढाई मीटर और गहराई 8-10 फीट थी. इसके बाद भरुआ सुमेरपुर में ज़मीन फटने एवं तीन मकानों में दरार पड़ने और फिर एक जुलाई को भिलावा मेरापुर में धरती फटने की घटना हुई. इसके पहले 2007 एवं 2008 में भी धरती फटने की घटनाएं हो चुकी हैं. धरती फटने से कहीं धुआं निकला, कहीं पानी निकल पड़ा और कहीं जोरदार आवाज़ निकली, जिससे ग्रामीण भयभीत हुए. इन घटनाओं की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई गई तो घटनास्थलों पर लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. अगस्त 2007 में जब पहली बार जिगनी (हमीरपुर) में धरती फटने की घटना हुई तो वहां 350 फीट लंबी और एक फीट चौड़ी दरार पड़ गई थी. ज़्यादातर लोगों ने उसका वैज्ञानिक कारण जानने का प्रयास नहीं किया, बल्कि देवताओं के नाराज़ होने और बुंदेलखंड को श्राप देने जैसी बातें चर्चा में थीं. जब धरती फटने की लगातार हो रही घटनाओं के संबंध में ज़िला प्रशासन ने शासन को लिखा तो फरवरी 2008 में वैज्ञानिकों की एक टीम आई, जिसने घटनास्थलों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट तैयार की. वैज्ञानिकों का कहना था कि बुंदेलखंड में कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, जिससे भूजल की कमी हो गई है, जबकि जल का दोहन बराबर किया जा रहा है और उससे ज़मीन के अंदर गैप बन गया है. इसीलिए तनाव पैदा हुआ और धरती फट गई. वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि हो सकता है, जिस जगह धरती फटी, उसके नीचे बह रही दो विशाल धाराओं में संभवत: प्रभावित क्षेत्रों का भूजल चला गया हो और उसकी वजह से गैप बन गया, जिसके कारण धरती फट गई. वैज्ञानिकों का आशय यह था कि बुंदेलखंड में पानी की कमी ही इसका मुख्य कारण है.

केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बुंदेलखंड में 4 लाख 42 हज़ार 299 हेक्टेयर मीटर भूमिगत पानी बचा है. एक लाख 92 हज़ार 549 हेक्टेयर मीटर हर वर्ष जल दोहन हो रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्षिक दोहन के मामले में बुंदेलखंड में हमीरपुर सबसे आगे है (1995 से पहले महोबा हमीरपुर में शामिल था). हमीरपुर का वार्षिक भूजल दोहन 41 हज़ार 779 हेक्टेयर मीटर बताया गया. संभवत: इसी कारण यहां धरती फटने की घटनाएं अधिक हो रही हैं. सबसे कम भूजल दोहन 10 हज़ार 642 हेक्टेयर मीटर चित्रकूट में हो रहा है. केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय का कहना है कि आने वाले समय में खेतों और लोगों के जीवनयापन के लिए पानी का संकट बढ़ सकता है. भूगर्भ विज्ञानी सईद उल हक़ कहते हैं कि पानी की समस्या हमारी ख़ुद की पैदा की हुई है. यहां बारिश के पानी के संचयन और जल प्रबंधन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया गया. बुंदेलखंड में दिल्ली के बराबर बारिश होती है, किंतु यहां की मिट्टी में ग्रेनाइट होने के कारण जल संचयन में कठिनाई है. फिर भी यदि ईमानदारी से जल प्रबंधन होता तो यह समस्या नहीं पैदा होती. पानी की कमी के कारण चित्रकूट मंडल की सबसे कम कृषि उत्पादन वाली सर्वाधिक 18 न्याय पंचायतें हमीरपुर की हैं. जन प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नदियों और पहाड़ों में रात-दिन अंधाधुंध खनन हो रहा है, बड़ी-बड़ी मशीनों से धरती छलनी की जा रही है. नदियों से निरंतर रेत और मौरंग निकाली जा रही है, पहाड़ों पर विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे भूगर्भ जल निकल रहा है, इसलिए तत्काल खनिज दोहन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. जल की उपलब्धता और भूगर्भ जलस्तर बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड राहत पैकेज में तालाब, चेकडैम और नहरों के निर्माण की योजनाएं बनाई गईं, लेकिन उनके कार्यान्वयन में कोताही का आलम यह है कि करोड़ों रुपये ख़र्च होने के बाद भी समस्या जस की तस है.

फरवरी 2008 में वैज्ञानिकों द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने पर शासन ने काफी गंभीरता दिखाई थी. तत्कालीन मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने कहा था कि जिन स्थानों पर धरती फटी है, वहां भूमि संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, किंतु तीन वर्षों के बाद भी स्थिति जस की तस है. ललितपुर में जहां पत्थर माफ़िया अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं, वहीं खदानों में कार्यरत मज़दूरों को सिल्कोसिस नामक जानलेवा बीमारी मज़दूरी शुरू करने के सात सप्ताह बाद ही जकड़ लेती है. खांसी, जुकाम और बुखार से शुरू होने वाली सिल्कोसिस एक वर्ष पूरा होते-होते मज़दूरों की मौत पक्की कर देती है. इस दौरान सीने में दर्द और मुंह से ख़ून गिरने की शिकायत होने लगती है. यह बीमारी सिलिका नामक धूल की वजह से पैदा होती है, जो पत्थर काटते समय श्वांस लेने पर फेफड़ों में जमा हो जाती है और उन्हें कमज़ोर कर देती है. इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है, इसलिए प्रतिवर्ष सैकड़ों मज़दूर मौत के मुंह में जा रहे हैं. 1986 में सिल्कोसिस से पीड़ित 16 मज़दूरों की एक साथ मौत होने पर तत्कालीन सांसद शरद यादव ने राज्यसभा का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा था, तब केंद्र सरकार ने इस रोग की पहचान एवं उपचार के लिए डॉ. एच एन सैय्यद के नेतृत्व में राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के एक विशेषज्ञ दल को सर्वेक्षण हेतु ललितपुर भेजा था. उक्त दल ने इस क्षेत्र के 500 से अधिक मज़दूरों में सिल्कोसिस के लक्षण पाए थे. वर्तमान में ग्राम नाराहट, डोगराकला, पाली, जाखलौन, धौर्रा, कपासी, मादोन, बंट, पटना, पारोट, राजघाट, भरपतुरा, मदनपुर एवं सौरई आदि के पास स्थित पत्थर खदानों में काम करने वाले खनिक इस बीमारी के शिकार हैं.

बुंदेलखंड अपनी वन संपदा, खनिज संपदा और शूरवीरता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है. पानी की कमी, ग़रीबी और भुखमरी यहां की मुख्य समस्याएं हैं. पिछले चार-पांच सालों से यहां धरती फटने की नई समस्या पैदा हो गई है, जिसने किसानों को संकट में डाल दिया है. बीते 14 जून को हमीरपुर के मदारपुर गांव में एक अजीब घटना हुई. रात में 700 मीटर लंबाई में धरती फट गई, जिसकी चौड़ाई ढाई मीटर और गहराई 8-10 फीट थी.

बेतरतीब खनन के परिणामस्वरूप पर्यावरण को काफी नुक़सान हुआ. क्रशरों और बालू के अवैध खनन के चलते यहां की जीवनदायिनी नदी बेतवा के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है. बीते पांच वर्षों में आजीविका पर बढ़ते संकट के कारण 267 लोगों ने आत्महत्या करके इसे अभागा क्षेत्र बना दिया. बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधनों की लूट-खसोट रोकने के लिए जब तक सार्थक पहल नहीं होती, तब तक कभी भूकंप का डर तो कभी सूखे की मार जैसी आपदाएं इस इलाक़े के भाग्य पर मंडराती रहेंगी. नरैनी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है. यहां कुल 250 हेक्टेयर भूमि अनुमानित तौर पर लीज के दायरे में आती है. महोबा में कुल 330 खदानें हैं, जिनमें 2500 हेक्टेयर भूमि प्रभावित है. चित्रकूट में 272 खदानों में पत्थर तोड़ने का कार्य किया जाता है, यहां लगभग 2200-2400 हेक्टेयर भूमि खनन क्षेत्र में है. बुंदेलखंड को लेकर सियासी हमले करके जनता की अदालत में केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगी मायावती सरकार का असली चेहरा यहीं देखने को मिलता है. पूरे बुंदेलखंड में खनिज व्यापारी, क्रशर मालिक और ठेकेदार गुंडा टैक्स के कारण हड़ताल करने को विवश हो गए हैं. अवैध उगाही का यह काम कभी सपा मुखिया की आंखों के तारे रहे पोंटी चड्ढा के आदमी कर रहे हैं, जो इन दिनों मायावती सरकार के चहेते हैं. बांदा, चित्रकूट, महोबा और झांसी में तक़रीबन साढ़े पांच सौ क्रशर प्लांटों में उत्पादन पूरी तरह ठप है, हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं. क्रशर मालिकों का कहना है कि उनसे जबरन गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है. गिट्टी में सरकारी रॉयल्टी 68 रुपये प्रति घन मीटर और 15 प्रतिशत बिक्री कर चुकाना पड़ता है. दस टायर ट्रकों में 10 घन मीटर और छह टायर ट्रकों में छह घन मीटर गिट्टी भरी जाती है. इस तरह दस टायर ट्रक में तक़रीबन 800 रुपये का सरकारी टैक्स चुकाना पड़ता है. 50 ट्रकों के लिए रॉयल्टी शुल्क 34 हज़ार, सेल टैक्स 6 हज़ार यानी कुल 40 हज़ार रुपये राजस्व बुक जारी कराते समय चुका दिए जाते हैं. गुंडा टैक्स राजस्व बुक यानी एमएम-11 जारी कराते समय ही खनिज विभाग के बाहर मौजूद गुंडे वसूलते हैं. यह प्रति ट्रक 1500 यानी 50 ट्रकों पर 75 हज़ार रुपये तत्काल देने पड़ते हैं. बांदा के सदर विधायक विवेक कुमार सिंह का कहना है कि खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर गुंडा टैक्स की वसूली कराई जा रही है. बबेरू विधायक विशंभर सिंह यादव का कहना है कि जबरिया वसूली नहीं होनी चाहिए. तिंदवारी विधायक विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा कि सिंडीकेट सिस्टम से वसूली पर अधिकारी चुप हैं, सरकार मौन है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवता द्विजेंद्र त्रिपाठी ने बसपा नेताओं के अवैध खनन, आबकारी और भूमि घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. त्रिपाठी बताते हैं कि सत्ता में बैठे प्रभावशाली लोगों ने अवैध तरीक़े से पत्थर और बालू खनन के ठेके अपने चहेतों के पक्ष में करा लिए. सरकारी संरक्षण में नदियों से अनाधिकृत तरीक़े से बालू का अंधाधुंध खनन कराया जा रहा है. क्रशर यूनियन अध्यक्ष ध्यान सिंह, महामंत्री मिथलेश गर्ग, स्टोन मिल मालिक संजय सिंह, पंकज माहेश्वरी, सुनील बाहरी, संतोष पटेल एवं शुभलाल सिंह ने कहा कि चाहे जो हो जाए, अब वे गुंडा टैक्स नहीं देंगे.

feedback@chauthiduniya.com

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह निजी संपत्ति की रक्षा करे, जो ज़मीनों में या पूंजी में निहित है. हमला करने वालों को पुलिस या सैनिकों द्वारा दंडित करे.

कांग्रेस एक तरह से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व करती है और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में प्रतियोगितावादी विचारधारा का.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

व्यक्तिगत और निजी संपत्ति

समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा से पहले इसे ठीक से समझना होगा. जब तक इसके विपरीत पक्ष पूंजीवाद को हम सही मायनों में समझ नहीं लेते, तब तक समाजवाद का तात्विक अर्थ समझना कठिन है. राष्ट्र में समाजवाद लागू करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जिसे मिटाकर समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने की हम सोच रहे हैं. समाजवाद का अर्थ पूंजी को नष्ट कर डालना या मिटा देना कदापि नहीं है. जो लोग समाजवाद का यह मंतव्य बताते हैं, वे ग़लती करते हैं. असल में पूंजीवादी लोग यह प्रचार करते हैं कि समाजवादी तो देश की पूंजी नष्ट करने पर तुले हुए हैं. व्यक्तिगत संपत्ति का समाजवादी अर्थव्यवस्था में उतना ही स्थान है, जितना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है.

व्यक्तिगत संपत्ति और निजी संपत्ति में बड़ा अंतर है. उदाहरण यों समझिए, आपके पास एक छाता है, यह आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है. आपके सामने जो भोजन परोसा गया है या जो कपड़ा आप पहने हुए हैं, ये सब आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है. पर जिस खेत में अनाज पैदा होता है, वह खेत आपके पुरखों से आपके परिवार में चला आता है, उसकी लगान चाहे रुपयों में, चाहे अनाज के रूप में आप जोतने वाले किसान से हर साल पाते रहे हैं, वह आपकी निजी संपत्ति है. जो मकान आपने किराए पर दे रखा है, आपने अपने रुपये ख़र्च करके उसे बनाया था, हर माह उसका किराया आप वसूल करते हैं, वह आपकी निजी संपत्ति है. जिस कारखाने को आपने लगाया, अपने रुपये ख़र्च करके मशीनरी लगाई, उस मशीनरी को चलाने के लिए अपने मज़दूर–नौकर रखे तो वह मिल या फैक्ट्री आपकी निजी संपत्ति है. आपने 10 लाख रुपये इसी तरह व्यवसायों से कमाकर कई लोगों को उधार दे दिए, उनसे आपने हुंडियां या प्रोनोट लिखवा रखे हैं या उनकी ज़मीन–जायदाद रेहन रख रखी है, वे रुपये आपकी निजी संपत्ति हैं.

चालू भाषा में व्यक्तिगत संपत्ति या निजी संपत्ति में बहुत ही कम फ़र्क़ मालूम पड़ रहा है, पर असल में यही तो सारे उपद्रव की जड़ है. यहीं तो समाजवाद और पूंजीवाद का पृथक्करण होता है. इसलिए कुछ उदाहरणों से आपको बताया है कि किसे व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं और किसे निजी संपत्ति कहते हैं. इसलिए संक्षेप में पूंजीवाद का यह अर्थ समझिए कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा देश की सारी ज़मीन कुछ व्यक्तियों के अधिकार में चली जाए, राष्ट्र के अधिकार में नहीं और वे उसका उपयोग स्वेच्छा से करें. आपको उस पर रहने की अनुमति वे सिर्फ़ अपनी शर्तों पर ही दें. ऐसे व्यक्तियों को हम ज़मींदार, जागीरदार, मालिक, ठाकुर, लैंडलॉर्ड इत्यादि अनेक नामों से संबोधित किया जाता है.

क़ानूनवेत्ता कहते हैं कि ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष की कभी नहीं होती, सारी ज़मीन राज्य की है. कोई भी राज्य चलाने वाला हो, उसे कभी भी उसे लेने का, अपने क़ब्ज़े में कर लेने का हमेशा अधिकार है. शायद यही क़ानूनी स्थिति है और सही है. राज्य या राज्यकर्ता वस्तुतः लेते नहीं हैं और इसलिए यह ज़मीन लोगों की निजी संपत्ति बनी रहती है, बनी हुई है. उस ज़मीन से जो पैदावार उन व्यक्तियों के पास संग्रह होती रहती है. यह पैदावार जो पूंजी की निजी संपत्ति बन जाती है. फलस्वरूप जितने भी उद्योग या कारखाने हैं, जिनको स्थापित करने के लिए ज़मीन और पूंजी दोनों ही अपेक्षित हैं, वे सब निजी संपत्ति बन जाते हैं. अब चूंकि फैक्ट्री–कारख़ाना बिना मज़दूरों के चल नहीं सकते, ये मालिक लोग उन आदमियों को रोजी देते हैं, जो मज़दूर कहलाते हैं और जो

मालिक नहीं हैं. वे उनको इतना ही वेतन देते हैं, जिससे वे जिंदा रहें और काम करें. बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और वे मज़दूर बनते रहते हैं, ताकि उनकी फैक्ट्रियां या कारखाने हमेशा चालू रहें. इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर वे मालिक लोग अपना कर्तव्य समझते हैं कि कम से कम वेतन उन मज़दूरों को दिया जाए और उनसे शारीरिक श्रम इतना लिया जाए कि क्षीण होकर वे काल के गाल में चले जाएं. यह सब ही जानकर लोग स्वीकार करेंगे कि इस तरह वित्त की असमानता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है. वह मज़दूर या सेवक दिनोंदिन ज़्यादा से ज़्यादा ग़रीब बनता जाता है और वह मालिक उसी अनुपात से दिनोंदिन धनिक बनता जाता है. नितांत स्वार्थपरता का अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि असंतोष, दु:ख, दारिद्र्य, जरायम पेशा और भयंकर रोग फैलते हैं और अंततोगत्वा भयानक विद्रोह फूट निकलता है. इस विद्रोह को दबाने या कुचल डालने के लिए सरकार को पुलिस, हथियारबंद सिपाही या सैनिक रखने पड़ते हैं, जो शांति को बनाए रखें. इसी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं. इसमें सरकार का यह कर्तव्य है कि वह निजी संपत्ति की रक्षा करे, जो ज़मीनों में या पूंजी में निहित है. हमला करने वालों को पुलिस या सैनिकों द्वारा दंडित करे. अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ जो करारनामे हुए हैं, सरकार उनका उचित संरक्षण करती है.

उसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था का उद्घोष है कि सरकार का पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि सबको समान वित्त का अधिकार मिले, किसी को भी निजी संपत्ति रखने का अधिकार न हो. हर करारनामा राष्ट्र का करारनामा समझा जाए, कोई भी व्यक्ति ऐसे करारनामे बर्दाश्त न करे, जिनके प्रभाव स्वरूप एक व्यक्ति तो दिन–रात काम करके हीनता अनुभव करता हुआ समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए और दूसरा व्यक्ति आलस्य से दूसरों के श्रम पर घोर निद्रा में सोता रहे और फिजूलखर्च करता रहे. यह ही है कि समाजवाद निजी संपत्ति का या मनमाने करारनामों का मूलोच्छेद कर देगा और अगर आपने लक्ष्य किया है तो इन 10–20 वर्षों में ही कुछ प्रगति इस दिशा में हो भी गई है. यही पूंजीवाद और समाजवाद का संघर्ष भारत में क़रीब एक शताब्दी से चल रहा है, जिसका बड़ा धक्का स्वतंत्रता के बाद ही मालूम पड़ रहा है. जनता के आक्रोश से यह पूंजीवाद धीरे–धीरे नरम पड़ रहा है और बहुत सी समाजवादी व्यवस्थाएं उसे अब सह्य भी हो गई हैं और क्रमशः प्रत्येक खुराक इसके गले से उतर रही है. जैसे पहले कह चुका हूं, व्यक्तिगत संपत्ति और निजी संपत्ति में बहुत फ़र्क़ है. इन दोनों को पर्यायवाची शब्द समझने की भूल नहीं होनी चाहिए. जो उदाहरण दिया गया है, उसी का विश्लेषण इस तरह से है–छाता आपका है, आप उसका चाहे जैसे उपयोग कीजिए, पर उसका यह उपयोग आप नहीं कर सकते कि उठाकर उसको किसी के सिर पर दे मारें (शायद छातों का यह भी कई जगह आवश्यक उपयोग है). आप अपने मकान में से किसी किराएदार को वर्षा, आतप, शीत का विचार किए बिना उसके स्त्री–बच्चों सहित बाहर सड़क पर फिंकवा सकते हैं. पर आपके मकान के बाहर जो चबूतरा है, वह सड़क के यातायात में बाधा पहुंचा रहा है, उसको तोड़ देने से मार्ग सरल और सुगम हो सकता है, पर चूंकि आपके कुत्ते उस चबूतरे पर दोपहर में बैठे रहते हैं या आपको यह दृश्य पसंद है तो आप उसे नहीं तोड़ने देना चाहते. भले ही उससे सड़क पर चलने वाली गाड़ी, मोटर या पैदल चलने वालों को कितना ही कष्ट क्यों न हो या कितनी ही दुर्घटनाएं उसके कारण क्यों न हों. आपको अपने चबूतरे का तोड़ा जाना पसंद नहीं. ग़ौर करने लायक़ बात है कि सिर पर छाते से मार देने की अपेक्षा यह काम अपेक्षाकृत ज़्यादा जघन्य है. पर निजी संपत्ति का संरक्षण पूंजीवादी सरकार में निहित है. इसलिए आपको यह सब या इनसे भी ज़्यादा जघन्य कर्म करने का अधिकार है, पर व्यक्तिगत संपत्ति को चाहे जैसे उपयोग करने का अधिकार नहीं है. इसलिए अगर समाजवादी यह कहें कि जितनी जल्दी निजी संपत्ति को मिटाया जाए, उतनी जल्दी मिटा डालना चाहिए. तो, उनका यह कहना ठीक ही है.

पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही पक्ष यह दावा करते हैं कि मानव जाति के हित में वे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं. दोनों ही अपने–अपने पक्ष की दलीलें पेश करते हैं. भारत में स्वतंत्रता मिलने के पहले तक तो पूंजीवाद का बोलबाला था. अंग्रेजों की छत्रछाया में मज़दूर वर्ग या निर्धन वर्ग आवाज़ उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था. जबसे अखिल भारतीय कांग्रेस ने विदेशियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, साथ ही साथ जनता को उनकी दुर्दशा का ज्ञान कराया, तबसे जनता के दिमाग़ में पूंजीवाद ज़हर है, यह बात जंच गई. अतएव भारत के प्रधान पूंजीवादी भी या पूंजीवाद का समर्थन करने वाले नेता भी आज खुलेआम यह नहीं कह सकते कि हम पूंजीवादी हैं. यह शब्द अब गाली के रूप में लिया जाने लगा है. इसका दूसरा स्वरूप जो शेष रह गया है, वह है दक्षिणपक्षीय और वामपक्षीय. दक्षिणपक्षीय लोग समझते हैं और कहते हैं कि उनकी व्यवस्था ज़्यादा कल्याणप्रद है. वामपक्षीय दल कहता है कि उसकी व्यवस्था अधिक संतोषप्रद है. दोनों ही दल अपने–अपने पक्ष का समर्थन करते हुए कहते हैं कि असल मायने में समाजवादी व्यवस्था हमारी ही है. जो भी हो, कौन सी समाजवादी व्यवस्था किस तरह बढ़िया है, यही परीक्षण तो हमारा उद्देश्य है. इसके लिए पहले हम पूंजीवाद का परीक्षण कर लें.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

समतावादी समाज के लिए विस्तृत लोकतंत्र की ज़रूरत

वर्तमान समय में देश का ध्यान समाज के कुछ तबकों के बीच की विषमता और उनके गुस्से को कम करने की ओर होना चाहिए. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहां लोकतंत्र का मतलब केवल प्रत्येक पांच सालों के बाद होने वाला चुनाव रह गया है, जिसमें मतदाता भाग लेते हैं और अपना मत डालते हैं. उसे निष्पक्ष चुनाव कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि और मतदाता के बीच बामुश्किल ही कोई संपर्क रह पाता है. पहले के सांसद और विधायक अपने क्षेत्र का दौरा आज के सांसदों और विधायकों की अपेक्षा कहीं अधिक करते थे. एक सही लोकतंत्र उसे ही कहा जा सकता है, जिसमें सक्रिय नागरिक समाज हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो और एक सतर्क प्रेस–मीडिया हो, जो नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत रहे, जिससे इन अधिकारों की रक्षा की जाए. उस लोकतंत्र का क्या उपयोग है, जिसमें एक बांध बनाने के लिए लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, उन्हें दर–दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जाता है.

ऐसी अधिकांश घटनाएं देश के आदिवासी इलाक़ों में घटती हैं. इनके साथ संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती. हाल में घटी कुछ ऐसी ही घटनाओं ने माओवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया है. इसी प्रकार की एक घटना अभी देखने को मिल रही है. कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र के लिए वहां के लोगों की ज़मीन ली जा सकती है और उनकी प्रतिक्रिया का भी अनुमान लगाया जा सकता है. रत्नगिरि के निकट जैतापुर में बन रहे नाभिकीय संयंत्र को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या 9 फ़ीसदी आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ठीकठाक विदेशी मुद्रा भंडार के साथ हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था की बात कर सकते हैं, जबकि लाखों भारतीयों का जीवन स्तर निम्न है, साथ ही जो हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि वे उस घर और ज़मीन से कभी भी वंचित हो सकते हैं, जिन पर सैकड़ों वर्षों से उनका अधिकार रहा है. लेकिन जब वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध करते हैं तो शासन–प्रशासन बड़ी निर्दयता से उनका दमन कर देता है.

इसे हम अपने लोकतंत्र का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे. जब तक ऐसे लोगों को विकास में सहभागी नहीं बनाया जाता, तब तक उसे वास्तविक विकास कहा भी नहीं जा सकता. सभी सरकारें, यहां तक की सशस्त्र बल, सुरक्षाबल, प्रशासन और ज़िलाधिकारी आदि भी इस तरह प्रशिक्षित किए जाते हैं कि सभी प्रकार के विरोध को ये लोग क़ानून व्यवस्था की समस्या समझें. ये लोग समस्याओं की वजह जानने की कोशिश ही नहीं करते और उनके प्रति उदासीन रहते हैं. यह समस्या काफी गंभीर है. सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और सामाजिक–स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बातचीत करनी चाहिए, ताकि असंतुष्ट लोगों को समझाया जा सके तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करके देश में शांति क़ायम की जा सके. उन लोगों को अभी तक इंसाफ़ नहीं मिला है, अब और अधिक समय तक ऐसा करना देश के हित में कदापि नहीं होगा.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

कांग्रेस सबक़ ले

कांग्रेस को हिसार उपचुनाव के नतीजे से सबक़ लेना चाहिए. अगर उसने इस हार की समीक्षा करते हुए समय रहते अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो उसे उत्तर प्रदेश में भी इसी स्थिति से दो–चार होना पड़ सकता है. ख़ास बात यह है कि जनता ने भाजपा के भ्रष्टाचारों की अनदेखी करते हुए उसके गठबंधन के प्रत्याशी को चुना है. इसलिए इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनता का विरोध कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अन्य सियासी दलों के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

–चांदनी ख़ान, *हिसार, हरियाणा.*

आईआईटी की गरिमा बहाल हो

आईआईटी देश का अग्रणीय शिक्षण संस्थान है. इस पर देश के होनहार युवा छात्रों का भविष्य टिका है, पर हाल में इसकी गुणवत्ता पर जो सवाल उठे हैं, वे वाक़ई चिंतनीय हैं. ख़ासकर उन छात्रों के लिए, जो इसके माध्यम से कुछ कर गुज़रना चाहते हैं. सरकार चाहे तो इस संस्थान की गरिमा पहले जैसी बनी रह सकती है. बशर्ते उसे इसके अंदर चल रहा नौकरशाही का खेल ख़त्म करना होगा. साथ ही सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ख़र्च करने की ज़रूरत है.

–विजय कुमार, *बेगूसराय, बिहार.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

जनता जागरूक हो

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संसद पहुंचते हैं. ये प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता की अनदेखी करते हैं. होना तो यह चाहिए कि ये जनसमस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें. आएदिन नए–नए घोटाले सामने आते रहते हैं. जनता को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक उसकी हालत सुधरने वाली नहीं है.

–विनय कुमार मिश्रा, *फ़र्रुख़ाबाद, उत्तर प्रदेश.*

चौथी दुनिया को बधाई

मैं चौथी दुनिया का पाठक हूं. पत्रकारिता की जो ज़िम्मेदारी आप निभा रहे हैं, वह शायद ही कोई दूसरा निभा रहा हो. रुद्रपुर और भरतपुर का फ़साद हो या गुजरात और संजीव जैसे अधिकारी का मामला, हिंदी से अंग्रेजी तक इन ख़बरों ने सुर्ख़ियों में जगह नहीं बनाई. क्या पत्रकारिता का भी विभाजन हो गया है? भगवान और तांत्रिकों को आधार बनाकर टीआरपी से खेलने वाले न्यूज चैनल भी ख़ामोश रहे, लेकिन आपने पहले ही दिन से जिम्मेदार भूमिका निभाई और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ अलख जगाई. इसलिए चौथी दुनिया को बधाई देना ज़रूरी समझता हूं.

–मुशर्रफ़ आलम ज़ौक़ी, *दिल्ली.*

अत्याचार मिटाने वाला चाहिए

मिटती है सब रार, मिटाने वाला चाहिए
मिटता है अत्याचार, मिटाने वाला चाहिए
जादू की जब छड़ी चलाए, जनता अपने दम पर
दूध छठी का याद दिलाए, जनमत अपने दम पर
पानी भरते बड़े–बड़े हैं, अनशन वाला चाहिए
मिटती है सब रार, मिटाने वाला चाहिए
लोकतंत्र की मर्यादा को, तार–तार फिर करते क्यों
शैतानों की बनी जेल में, जनसेवक को भरते क्यों
क्यों ऐसी गुस्ताख़ी कर दी, बताने वाला चाहिए
गधे पंजीरी न खा पाएं, कुछ ऐसा करना चाहिए
मिटती है सब रार, मिटाने वाला चाहिए.

–रामदीन, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

मीडिया की भेड़ चाल

इन दिनों गांधी के नाम पर सभी गांधीगिरी करने लगे हैं. रैलियों, धरनों और अनशनों को मीडिया जिस तरह उठाता है, उससे देश का भला होने वाला नहीं है. जिसे कोई काम नहीं मिलता, वह ठेकेदारी, नेतागिरी, वकालत और पत्रकारिता करने लगता है. हालांकि पत्रकारिता कोई आसान काम नहीं है, मगर पिछले काफ़ी समय से मीडिया भेड़ चाल का शिकार हो गया है. टीवी चैनलों पर राहुल महाजन की शादी, राखी सावंत का स्वयंवर और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं. मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए.

–डॉ. अनुपम, *नैनीताल, उत्तराखंड.*

आलेख पसंद आया

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख–शरद और सुप्रिया का शाहिद से रिश्ता पढ़ा. ऐसे अन्वेषात्मक और तथ्यपरक आलेख के लिए साधुवाद. यह रिपोर्ट काफ़ी मेहनत से तैयार की गई और यथार्थ को प्रस्तुत करने में कोई समझौता नहीं किया गया, इसके लिए बधाई.

–जी मंजू साईंनाथ, *बंगलुरू, कर्नाटक.*

केंद्र की भेदभावपूर्ण नीति

केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की लगातार अनदेखी कर रही है. पिछले दिनों प्रणब मुखर्जी ने कहा कि केंद्र पश्चिम बंगाल की हरसंभव मदद करेगा. बिहार में बाढ़ से काफ़ी नुक़सान हुआ, इसके बावजूद केंद्र ने बिहार पर ख़ास ध्यान नहीं दिया. केंद्र का यह व्यवहार उचित नहीं है. राजनेताओं को क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर काम करना चाहिए.

–प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अब बदलाव की नई कहानी का इंतज़ार है

देश की जनता को क्या इस बार भी निराश होना पड़ेगा और अगर निराश होना पड़ेगा तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी ख़बर नहीं मानी जानी चाहिए. अन्ना हजारे ने जब रामलीला मैदान में आंदोलन किया, तब उनके साथ लोग बड़े विश्वास के साथ सारे देश में खड़े हो गए. बहुत दिनों के बाद यह पहला ऐसा आंदोलन था, जिसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम यानी देश के हर हिस्से में कुछ न कुछ हुआ. ग़रीब, अमीर, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग सभी ने अपनी राय बनाई और कम से कम यह कहा कि देश की समस्याओं का हल होना चाहिए तथा सरकार को ज़्यादा जवाबदेह होना चाहिए. लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. सवाल यह है कि क्या अन्ना हजारे और उनकी टीम उस विश्वास की रक्षा कर पाएंगे, जो देश के लोगों ने उन पर किया है? यह सवाल इसलिए है, क्योंकि देश की सारी समस्याओं की जड़ कहीं न कहीं हमारे राजनीतिक तंत्र में है. आदर्श राजनीतिक तंत्र लोगों की समस्याओं को हल करता है, लोगों के मन में विश्वास जगाता है और कल्याणकारी राज्य के आधार पर देश के ग़रीबों को रहने व खाने की गारंटी देता है, लेकिन हमारे यहां यह नहीं हो पा रहा है. बहुत दिनों से यह प्रक्रिया बंद हो चुकी है. हमारा राजनीतिक तंत्र जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है. जनता की इच्छाएं, आकांक्षाएं, सपने और ख्वाहिशें इस राजनीतिक तंत्र के लिए कोई मायने नहीं रखतीं.

राजनीतिक तंत्र का मतलब राजनीतिक दलों से है. जो सरकार में हैं उनसे और जो सरकार में नहीं हैं उनसे भी. सरकार में रहने वाले लोग जब जनता की बात नहीं सुनते तो विपक्षी दलों का कर्तव्य होता है कि वे लोगों को जागृत कर आंदोलन करें और सरकार के कानों में वह बात पहुंचाएं, जिसका रिश्ता लोगों की परेशानियों और समस्याओं से है. इस बात को अब पूरा तंत्र भुला चुका है. इसीलिए लोगों की नाराज़गी इस पूरे तंत्र से है. पिछले 15 सालों में कोई भी बड़ा आंदोलन जनता की समस्याओं को लेकर विरोधी दलों ने नहीं किया. कांग्रेस के भीतर पहले एक परंपरा थी कि जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस कार्य समिति में आवाज़ें उठती रहती थीं, जिनसे सरकार पर आंतरिक दबाव पड़ता था और वह उन समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर हो जाती थी, पर पिछले 15, बल्कि 20 सालों से यह सब बंद हो चुका है. शायद चंद्रशेखर जी की सरकार आख़िरी सरकार थी, जहां पर थोड़ा–बहुत आंतरिक लोकतंत्र नज़र आता था. उसके बाद सत्ता अपना कर्तव्य भूल गई और विरोधी पक्ष भी अपना कर्तव्य भूल गया.

राजनीतिक तंत्र से मिली इसी निराशा ने देश की जनता को खड़ा कर दिया. लोगों ने अपने आप अपना नेता गढ़ लिया. उन्होंने मान लिया कि उनकी समस्याओं के हल के लिए अन्ना हजारे जैसा आदमी बिल्कुल सटीक नेता है, जिसका चरित्र साफ है, जो देखने में उनके बुज़ुर्ग जैसा लगता है और जिसकी भाषा में धमकी नहीं है. लोगों के दबाव से केंद्र सरकार डरी, अन्ना हजारे का अनशन टूटा, पर अनशन टूटने के बाद क्या हुआ? अन्ना हजारे को चाहिए था कि वह अनशन के बाद सारे देश में घूमते, लोगों से संवाद करते और उन्हें सच्चे लोकतंत्र के प्रति जागृत रहने के लिए कहते, क्योंकि जिस लोकतंत्र में जनता सोती है, वह लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है. अन्ना हजारे ने बार–बार लोगों के बीच जाने की बात कही, लेकिन वह लोगों के बीच नहीं गए. उनकी तारीख़ें उनके अनशन से पहले और उनके अनशन के बाद टलती रहीं. वह तारीखें तय करते रहे, लेकिन तय की हुई तारीख़ें कभी सामने नहीं आईं. इससे यह लगा कि अन्ना हजारे लोगों के पास जाने से कहीं न कहीं मन में डर रहे हैं. अन्ना हजारे के साथियों को देश के हर सवाल पर जवाब देने का साहस नहीं हुआ. शायद उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं, क्योंकि वे किसी राजनीतिक प्रक्रिया से निकल कर बाहर नहीं आए.

लोकनायक जय प्रकाश नारायण वैचारिक नेता थे और उनके सामने भविष्य के समाज का स्पष्ट चित्र था, डॉ. लोहिया के सामने स्पष्ट चित्र था, वैसे ही, जैसे कि गांधी जी के सामने स्पष्ट चित्र था. इन सबने देश के लोगों को समय–समय पर जगाया और उन्हें इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार किया. अपेक्षा थी कि अन्ना हजारे भी इस रास्ते का अनुकरण करेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता ज़िम्मेदार लोकतंत्र के निर्माण का रास्ता है. अन्ना हजारे और उनके साथियों ने न जनता का सामना किया और न जनता के सामने बुनियादी सवालों पर अपनी राय रखी. नतीजा यह निकला कि अन्ना हजारे पर कांग्रेस ने हमला किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी.

> **सरकार में रहने वाले लोग जब जनता की बात नहीं सुनते तो विपक्षी दलों का कर्तव्य होता है कि वे लोगों को जागृत कर आंदोलन करें और सरकार के कानों में वह बात पहुंचाएं, जिसका रिश्ता लोगों की परेशानियों और समस्याओं से है. इस बात को अब पूरा तंत्र भुला चुका है. इसीलिए लोगों की नाराज़गी इस पूरे तंत्र से है. पिछले 15 सालों में कोई भी बड़ा आंदोलन जनता की समस्याओं को लेकर विरोधी दलों ने नहीं किया. कांग्रेस के भीतर पहले एक परंपरा थी कि जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस कार्य समिति में आवाज़ें उठती रहती थीं, जिनसे सरकार पर आंतरिक दबाव पड़ता था और वह उन समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर हो जाती थी, पर पिछले 15, बल्कि 20 सालों से यह सब बंद हो चुका है.**

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मालूम है कि अन्ना हजारे और उनके साथियों के पास इस देश की समस्याओं के हल का कोई नक्शा शायद नहीं है. इसीलिए वे एक जन लोकपाल का मामला लेकर खड़े हो गए हैं. बिल्कुल वैसे ही, जैसे कोई कहे कि सिर्फ़ नमक खा लो या मिर्च खा लो, उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा. आदमी को संपूर्ण भोजन चाहिए. थाली में नमक और मिर्च के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं. उसे महंगाई, बेरोज़गारी, बीमारी, अशिक्षा और कुपोषण से होने वाली मौतों का इलाज चाहिए. पड़ोसियों से संबंधों के बल पर एक मज़बूत हिंदुस्तान चाहिए. वह हिंदुस्तान, जो अपनी समस्याओं से अपने आप लड़ता हुआ दिखाई दे, समस्याओं के आगे झुका हुआ या पैरालाइज्ड हिंदुस्तान नहीं चाहिए. इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता के पास जाकर एक संपूर्ण वैचारिक चित्र प्रस्तुत करना है, पर वह काम अन्ना हजारे और उनके साथियों ने नहीं किया.

क्या हम यह मानें कि अन्ना हजारे और उनके साथियों के पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं. अगर इन सवालों के जवाब अन्ना हजारे और उनके साथियों के पास नहीं हैं तो मुझे यह कहने में कोई दु:ख नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि फिर इन सवालों के जवाब जनता के सामने नक्सलवादी लेकर आएंगे. अगर इस देश में अहिंसक आंदोलन नहीं होगा तो हिंसक आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता. अगर इस देश में अहिंसा की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हिंसा की आवाज़ सुननी पड़ेगी. सरकार अहिंसा की आवाज़ नहीं सुनती, सरकार ग़रीबों की समस्याओं के प्रति ग़ौर नहीं करती और उन्हें प्राथमिकता नहीं देती. अगर मैं सरकार कहता हूं तो सरकार का मतलब पूरे राजनीतिक तंत्र से है, जिसमें विपक्षी दल भी शामिल हैं. यहीं मुझे डर पैदा होता है कि अन्ना हजारे के पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो निश्चित रूप से इस देश की जनता को एक और धोखे का सामना करना पड़ सकता है. पर जनता धोखे खाती है, उसने बहुत धोखे खाए. गांधी जी ने जब आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान की कल्पना हिंद स्वराज में की थी, जनता ने उस पर भरोसा किया, लेकिन जो सत्ता में रहे, उन्होंने हिंद स्वराज्य की जगह हिंदुस्तान को एक नई तरह की गुलामी में फेंक दिया. डॉ. लोहिया और लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आंदोलनों से बहुत आशाएं पैदा हुईं, लेकिन वे आशाएं भी टूटीं, क्योंकि डॉ. लोहिया और जय प्रकाश नारायण के शिष्यों ने ही उनके आदर्शों की हत्या की और उनके बनाए हुए रास्ते पर चलने से इंकार कर दिया. इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता ग़लत था, बल्कि यह कहेंगे कि रास्ते पर चलने वाले ग़लत थे. अन्ना हजारे से अगर लोगों को निराशा मिलती है तो इसमें कोई अचरच नहीं है, निराश होने की भी कोई बात नहीं है. फिर कोई आएगा, जो जनता को उसकी समस्याओं से निकलने का रास्ता बताएगा. जब वह रास्ता बताएगा, वह रास्ता समग्र होगा और रास्ते पर चलने का विचार समग्र होगा, तब शायद इस देश में बदलाव की एक नई कहानी शुरू होगी. वह कहानी कब शुरू होती है, अब तो इसी का इंतज़ार है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

यह पुनर्चिंतन का समय है

बारह साल तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के बाद पंडित नेहरू जब सत्तर वर्ष के हो गए तो उन्होंने सेवानिवृत्त होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया और उन्हें अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा. कार्यकाल के अंतिम पांच सालों में उनकी प्रतिष्ठा को पूर्व के वर्षों की अपेक्षा अधिक नुक़सान हुआ. अपने अंतिम समय में उन्होंने राबर्ट फ्रोस्ट के उस कथन को दोहराया कि मेरे पास कई वायदे हैं, जिनका मुझे पालन करना है और मृत्यु से पहले इन्हें मीलों तक ले जाना है. सोनिया गांधी अपनी बीमारी का इलाज कराकर भारत लौट आई हैं. उनके लौटने के साथ ही नेहरू द्वारा कही गई वे बातें याद आ जाती हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं है. अगर इस बात पर विश्वास किया जाए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन्हें कम से कम एक साल का अवकाश लेना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगी. उन्हें पंडित नेहरू की तरह अपने स्वास्थ्य का बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके सहयोगियों का कहना है कि वे उनके मार्गदर्शन के बग़ैर काम करने में असमर्थ हैं. इस कारण सोनिया गांधी को पिछले कुछ महीनों से भारत में हो रहे प्रशासनिक ह्रास के

> **कांग्रेस एक तरह से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व करती है और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में प्रतियोगितावादी विचारधारा का. दोनों को लोगों के हित में मिला दिया जाना चाहिए. जो राजस्व प्राप्त होता है, उसे सही लोगों के विकास और सही योजनाओं में लगाने की आवश्यकता है.**

लिए कुछ करना है. सोनिया गांधी को अपना काम करने में इतिहास के दो उदाहरणों से कुछ सहायता मिल सकती है. पहला उदाहरण है पंडित नेहरू का. उन्होंने अपने सहयोगी मंत्रियों से त्यागपत्र देकर पार्टी के लिए काम करने को कहा था. इसके लिए कामराज योजना लाई गई थी. उस समय के. कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे. इस योजना के बारे में कहा जाए तो यह एक तरह से लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू का उत्तराधिकारी बनाने का रास्ता साफ करने के लिए थी, ताकि मोरार जी देसाई को उनके रास्ते से हटाया जा सके. हालांकि स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह बहुत अस्पष्ट भी नहीं था. इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि सोनिया गांधी किसे, यहां तक कि कितने लोगों को हटाना चाह सकती हैं.

दूसरा उदाहरण हैराल्ड मैकमिलन का है. 1959 में बड़े बहुमत के साथ उन्हें चुना गया, लेकिन दो वर्षों के अंदर ही उन्हें महसूस हुआ कि सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है. इसलिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल किया और कई वरिष्ठ मंत्रियों, यहां तक कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर को भी हटाया, लेकिन इससे क्या होगा. यहां पुनर्विचार करने या कहें कि पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है. सोनिया गांधी कांग्रेस की पहली ऐसी नेता हैं, जिन्होंने 1998 और 2003 में चिंतन शिविर का आयोजन किया. 2003 में ऐसा अनुभव किया गया कि कांग्रेस अकेले सत्ता में नहीं आ सकती है, इसलिए सत्ता में आने के लिए एक ही रास्ता बचा है और वह है गठबंधन स्वीकार करना. क्या ऐसा ही विचार 1989 में राजीव गांधी को आया था. इस समय कांग्रेस को अपने नेतृत्व की संरचना और अपनी नीति के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है. सोनिया गांधी ने 2004 में पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच काम का बंटवारा किया, जो काफी सराहनीय था, लेकिन इसका परिणाम हमारे सामने है. अब एक रास्ता है कि मनमोहन सिंह को गठबंधन का नेता, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए. इसके अलावा एक अन्य समाधान है कि राहुल और सोनिया दोनों को प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष की दोहरी भूमिका मिल जाए. हालांकि पहले कभी प्रधानमंत्री का पद साझेदारी में नहीं रहा है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है. डॉ. मनमोहन सिंह गठबंधन के नेता रह सकते हैं और वह राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री पद की साझेदारी कर सकते हैं, जिसमें घरेलू नीतियों को राहुल देखें और मनमोहन सिंह अंतरराष्ट्रीय मामलों को. इसके अलावा कुछ नए विचार भी हैं.

कांग्रेस एक तरह से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व करती है और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में प्रतियोगितावादी विचारधारा का. दोनों को लोगों के हित में मिला दिया जाना चाहिए. जो राजस्व प्राप्त होता है, उसे सही लोगों के विकास और सही योजनाओं में लगाने की आवश्यकता है. इसके साथ–साथ पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में सुधार करना होगा. इस व्यवस्था के तहत होने वाली 41 फ़ीसदी बर्बादी को अनदेखा नहीं किया जा सकता. खाद्य सुरक्षा कानून के कारण पीडीएस की मांग और बढ़ गई है. अगर पीडीएस में सुधार नहीं किया गया तो फिर खाद्य सुरक्षा की बात सोचना बेमानी होगी. अत: अर्थशास्त्रियों को चिंतन की आवश्यकता है. 32 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले को बीपीएल में न रखे जाने वाला मुद्दा तकनीकी है और ज़्यादा दिनों तक इसे चलाया नहीं जा सकता. इसने भारतीय नागरिकों को मिलने वाले न्याय पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है. इसलिए किसी भी नागरिक की आय कम करके उसे बीपीएल के बाहर करना सही क़दम नहीं है, बल्कि उसकी आवश्यकता के अनुकूल उसकी आय बढ़ाया जाना या उसका निर्धारण करना ही उचित होगा. इस पर भी फिर से चिंतन करने की आवश्यकता है.

feedback@chauthiduniya.com

अहमदाबाद (गुजरात) निवासी राहुल अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अजोस्पर्मिया नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसमें स्पर्म नहीं बनता.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 31 अक्टूबर–06 नवंबर 2011

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सूचना आयोग ज़रूर जाएं

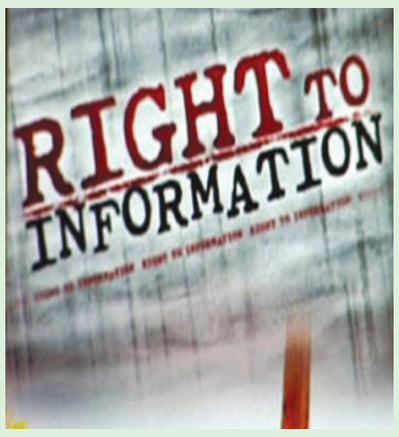

आरटीआई अधिनियम के तहत सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार है, लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना न देने के हज़ार बहाने बनाते हैं. ऐसे में आख़िरी रास्ता बचता है सूचना आयोग का. ऐसी हालत में आवेदक केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग में अपील या शिकायत कर सकता है. अपील और शिकायत में थोड़ा अंतर है. आपके आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा गया है, उसका जवाब अगर ग़लत दे दिया जाता है और आपको विश्वास है कि जो जवाब दिया गया है वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है तो आप आयोग में अपील कर सकते हैं. जब आप किसी सरकारी महकमे में आरटीआई आवेदन जमा करने जाते हैं और पता चलता है कि वहां तो लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया है या फिर आपसे ग़लत शुल्क वसूला जाता है तो ऐसे मामलों में आप सीधे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं. ऐसे मामलों में अपील की जगह शिकायत ही समाधान है. सूचना अधिकार क़ानून की धारा 18 (1) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और पूछताछ करे. इसके अलावा यदि किसी आवेदक को तय समय के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो पहले उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास प्रथम अपील करनी चाहिए. अगर वहां से भी सूचना न मिले तो वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास द्वितीय अपील कर सकता है. इसके साथ ही यह ज़रूरी है कि सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा ऐसे क़दम उठाए जाने चाहिए, ताकि आरटीआई क़ानून के प्रावधानों का सही मायनों में पालन हो सके. मसलन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति अवश्य की जानी चाहिए. रिकॉर्ड्स के रखरखाव और उसके प्रबंधन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. संबंधित अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए. यही नहीं, वे इस क़ानून की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) का पालन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रदान करें.

सूचना अधिकार क़ानून की धारा 18 (1) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और पूछताछ करे. इसके अलावा यदि किसी आवेदक को तय समय के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो पहले उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास प्रथम अपील करनी चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(सड़क मरम्मत का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
नीचे सड़कों की एक सूची दी गई है :-
(यहां सड़कों का विवरण दें)
उपरोक्त सड़कों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

1. दिनांक.....से.....के बीच उपरोक्त प्रत्येक सड़क की मरम्मत (थोड़ी, बहुत या बड़े पैमाने पर) कितनी बार हुई?
2. यदि कार्य विभाग द्वारा कराया गया तो प्रत्येक ऐसे कार्य केसंबंध में निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-
क. इस कार्य से संबंधित स्टॉक रजिस्टर की प्रति
ख. कार्य से संबंधित लेबर रजिस्टर की प्रति
ग. उन जगहों की वास्तविक स्थिति, जहां कार्य किया गया
घ. कार्य कब हुआ?
ड. कार्य के लिए प्रयोग की गई सामग्री के मिश्रण का अनुपात क्या था?
3. यदि कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया तो उससे संबंधित निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-
क. मेजरमेंट बुक की प्रति (एबस्ट्रेक्ट व रिकॉर्ड: दोनों ही प्रविष्टियों का विवरण)
ख. स्केच की प्रति
ग. ख़र्च के आकलन के विवरण की प्रति
घ. यदि कांट्रेक्ट में किसी प्रकार की गारंटी की व्यवस्था थी तो उसके विवरण की प्रति उपलब्ध कराएं और उन स्थितियों का विवरण दें, जिनमें उपरोक्त गारंटी व्यवस्था प्रभावी होती है.
ड. उन सहायक एवं कार्यपालक अभियंताओं के नाम बताएं, जिन्होंने इन प्रत्येक कार्यों का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी. उनके द्वारा कार्य के किस भाग का निरीक्षण किया गया?
च. क्या अब तक कभी गारंटी व्यवस्था का प्रयोग किया गया?
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जे) केतहत मैं इन सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूं. नमूना मेरे द्वारा चयनित स्थान से मेरी उपस्थिति में एकत्र किया जाए और यह सीलबंद हो तथा विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए कि सीलबंद नमूना कार्य में प्रयुक्त सामग्री का असली नमूना है. कृपया मुझे दिन, समय और स्थान की सूचना दें, जब मैं नमूना लेने के लिए आ सकूं.
5. अब इन सड़कों की मरम्मत कब होगी?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फ़ोन नं.....
संलग्नक.....

ज़रा हट के

अपने पोते का पिता

अहमदाबाद में रिश्तों का एक अजीब मामला सामने आया है. एक ख़बर के मुताबिक़, पिता बनने की आस में एक व्यक्ति ने अपने ही पिता का स्पर्म इस्तेमाल अपनी पत्नी को गर्भवती करने में किया है. अहमदाबाद (गुजरात) निवासी राहुल अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अजोस्पर्मिया नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसमें स्पर्म नहीं बनता. राहुल ने पिता बनने के लिए अपने पिता का स्पर्म इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया. विज्ञान के मुताबिक़, अब राहुल के पिता अपने पोते के पिता होंगे. गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश पटेल का कहना है कि इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के ही स्पर्म का इस्तेमाल करते हैं. परिवार के सभी सदस्यों की रजामंदी से स्पर्म दान किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, जिनमें महिलाएं अपने एग दान करती हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का ट्रेंड बढ़ने का कारण यह भी है कि लोग कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए परिवार के सदस्यों से ही स्पर्म लेने या देने का फैसला करते हैं. लोगों की यह सोच होती है कि परिवार के सदस्यों का स्पर्म इस्तेमाल करने से उनकी आने वाली संतान का बौद्धिक विकास सही ढंग से होगा.

कोमा का क्वेश्चन मार्क

19 साल तक कोमा में रहने के बाद रेलवे कर्मचारी ग्रेजबस्की जब होश में आए तो दुनिया देखकर उन्हें चक्कर आने लगे. 1988 में एक रेल हादसे में गंभीर रूप से घायल ग्रेजबस्की कोमा में चले गए थे. उस समय पोलैंड में कम्युनिस्ट सरकार थी. ग्रेजबस्की ने पोलैंड टीवी को बताया कि आज लोग एक यंत्र कान में लगाकर घूम रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं. ऐसी दुकानें खुल गई हैं, जिनमें हर तरह का सामान है. यह सब देखकर मेरा दिमाग़ घूमने लगा है. मैं जो देख रहा हूं, क्या वह सच है. 19 साल में दुनिया इतनी बदल गई कि वह हैरत में पड़ गए. उस समय खाद्यान्न समेत सारी चीजें राशन में मिलती थीं. दुकानों में सिर्फ़ चाय और विनेगर बेचने की अनुमति थी. जनता को बोलने की छूट नहीं थी. ग्रेजबस्की कहते हैं, मैं जब कोमा में गया था, उस समय लाल झंडे पूरे शहर में लहरा रहे थे. आज लाल झंडा कहीं नहीं दिखता. वह अपने परिवारीजनों से पूछते हैं कि कहां चले गए ये लाल झंडे वाले. पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है. ग्रेजबस्की लोकतंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं. वह कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे. घरवाले बमुश्किल उन्हें हाल के वर्षों में हुए बदलावों के बारे में समझा पा रहे हैं. उन्हें इस बात की बेहद ख़ुशी है कि अब हम जितना चाहें उतना मीट ख़रीद कर खा सकते हैं. उस समय मीट सिर्फ़ राशन की दुकानों से मिलता था. ग्रेजबस्की के होश में आने की संभावना बहुत कम थी. इसके बावजूद डॉक्टर 19 साल से उनका इलाज कर रहे थे. पेट्रोल पंप देखकर वह हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अब तो पेट्रोल पंप जाओ और तेल ले लो. कोमा से पहले हालात ऐसे थे कि तीन-चार घंटे बाद ही पेट्रोल मिलता था. मोबाइल फोन देखकर वह बेहद प्रभावित हैं. ग्रेजबस्की कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग बात करते समय टहलते क्यों हैं, एक जगह खड़े होकर बात क्यों नहीं करते.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष
21 मार्च से 20 अप्रैल

ज्ञान-विज्ञान की जानकारी हासिल करने से ही नई योजनाएं कारगर होंगी. फ़िलहाल आपका समय अच्छा गुजरेगा. यदि आप सरकार या किसी महत्वपूर्ण संस्था से जुड़े हैं तो सप्ताह मध्य तक आपका नाम किसी ज़िम्मेदारी वाले कार्य के लिए लिया जा सकता है.

वृष
21 अप्रैल से 20

अभिभावकों एवं स्वजनों के प्रति उत्तरदायित्व पूर्ण करने की व्यग्रता रहेगी. कारोबार में अस्थिरता रहेगी. मंदी के कारण कोई काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे. कुछ ऐसे अवसर हाथ से निकल जाने का खेद रहेगा, जो फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे.

मिथुन
21 मई से 20 जून

आर्थिक प्रयास सफल रहेंगे, लेकिन प्राप्ति में विलंब होगा. कोई गहरी चिंता ख़त्म होगी. यदि आप किसी विवाद-समस्या में उलझे हैं तो उसका समाधान सप्ताह मध्य तक निकल आएगा. बनते हुए काम में जो रुकावट आ रही थी, वह खत्म हो जाएगी.

कर्क
21 जून से 20 जुलाई

कामकाज में प्रगति के बावजूद मन में अस्थिरता रहेगी. जिस ख़ास मित्र पर आप भरोसा करते हैं, उसके व्यवहार में बदलाव से आपकी मनोदशा डांवाडोल हो सकती है. आपके अंदर यह ख़ूबी है कि आप जल्द ही खुद को नियंत्रित कर सहज स्थिति में आ जाएंगे.

सिंह
21 जुलाई से 20 अगस्त

कोई महत्वपूर्ण काम बिगड़ जाने से मनोबल कमज़ोर पड़ सकता है. आपकी निजी और पारिवारिक जीवनशैली में जो बदलाव आ रहा है, उसके लिए भरपूर धन कमाने की ज़रूरत है. यदि संशय और आलस्य करेंगे तो दूसरों के मुक़ाबले पीछे रह जाएंगे.

कन्या
21 अगस्त से 20 सितंबर

नियम और क़ानून की अवहेलना करना नुक़सानदायक रहेगा. पारिवारिक मामलों में किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद रहेगी. अच्छे निवेश या धन लगाने की योजना बन सकती है. कठिन परिश्रम से किया काम अच्छा लाभ दे सकता है.

तुला
21 सितंबर से 20 अक्टूबर

किसी अच्छे समाचार या धन लाभ के चलते मन की चिंता कुछ हद तक कम होगी. क़रीबी और परिवारीजन आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे. कार्य विशेष की सफलता और कारोबार की प्रगति के चलते आपका कार्यक्रम कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता भरा हो सकता है.

वृश्चिक
21 अक्टूबर से 20 नवंबर

घर-परिवार के लोगों से प्रेम बढ़ेगा. उत्साह बढ़ेगा. जीवनसाथी के भाग्योदय होने के संकेत मिलेंगे. कारोबार और रोज़गार में मनोवांछित सफलता मिलने से धन लाभ हो सकता है. नई योजनाओं और साझेदारी का विचार बन सकता है.

धनु
21 नवंबर से 20 दिसंबर

व्यर्थ की उलझनों में समय व्यतीत होगा. उम्मीद से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है. किसी दूसरे की आधी-अधूरी कार्यशैली आपको पसंद नहीं आएगी. अधिकारी आपको अहम ज़िम्मेदारी सौंप सकते हैं.

मकर
21 दिसंबर से 20 जनवरी

नवीन प्रकार के कामकाज का आयोजन होगा. चिंताओं के बावजूद आपका मन कामकाज में तल्लीन रहेगा. भरसक प्रयासों से किसी अच्छे लाभ या समाचार की आशा रहेगी. स्वास्थ्य के मामले में अभी कुछ और उपचार की स्थिति आ सकती है.

कुंभ
21 जनवरी से 20 फरवरी

परिवार में बेचैनी अनुभव करेंगे. निकट भविष्य में स्थान परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं. फिजूलख़र्ची और अनावश्यक आर्थिक दबाव बना रहेगा. कोई पुराना क़र्ज़ चुकाने में आपकी साख और प्रतिष्ठा पर लोग उंगली उठा सकते हैं.

मीन
21 फरवरी से 20 मार्च

उत्साह और प्रेरणा से सभी कार्य बनते जाएंगे. भाषा पर संयम रखें. अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है. आपके द्वारा किया गया काम लोगों की नज़र में आ रहा है. अपने परिश्रम के बल पर आप प्रशंसा बटोरने में सफल होंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

भारत के लिए इस संगठन की काफी अहमियत है. तेजी से बढ़ती इन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ बेहतर संबंध भारत के हित में हैं.

पाकिस्तान और अमेरिका
बनते-बिगड़ते संबंध

हक्कानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान के संबंधों पर अमेरिकी सैन्य अधिकारी एडमिरल माइक मुलेन की टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. दोनों देशों के अधिकारियों एवं राजनीतिक नेतृत्व ने एक-दूसरे के विरुद्ध बयानबाज़ी की थी, लेकिन दोनों के बीच संबंधों में कब कौन सा मोड़ आ जाए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है. एक तरफ़ दोनों देश संबंध सुधारने के लिए प्रयास करते नज़र आते हैं तो दूसरे ही पल दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. जब अफ़ग़ानिस्तान मुद्दे पर अमेरिका के विशेष दूत मार्क ग्रॉस्मेन ने पाकिस्तानी नेताओं से मुलाक़ात की तो ऐसा लगने लगा कि दोनों देशों के रिश्ते फिर से सुधर जाएंगे. ग्रॉस्मेन ने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों की वकालत की. उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी, प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी, विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के अलावा सेनाध्यक्ष जनरल अशफाक परवेज कयानी से भी मुलाक़ात की. इन्हीं लोगों ने अमेरिका के इस आरोप का कड़े शब्दों में खंडन किया था कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क की अमेरिका विरोधी कार्रवाइयों में उसकी सहायता करता है. इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में कुछ दिनों के लिए दरार पड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन विशेष दूत की पाकिस्तानी नेताओं और सेनाध्यक्ष से मुलाक़ात ने स्थिति सामान्य होने की आशा जगा दी. अमेरिका के विशेष दूत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता की और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत मज़बूत हैं. आतंकवाद के ख़िलाफ़ चल रहे युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों का महत्व अधिक बढ़ गया है. हिना रब्बानी खार ने भी अमेरिकी प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनका देश इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए रचनात्मक

भूमिका अदा करता रहेगा.

इन प्रयासों से लग रहा था कि अमेरिका-पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे और पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ अमेरिका को सहायता देगा, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी के एक बयान ने बाधा पैदा कर दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अमेरिका उसे अफ़ग़ानिस्तान या इराक समझने की भूल न करे. पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाक़ों में शांति बहाल करने की ज़िम्मेदारी हमारी है, अमेरिका की नहीं. वजीरिस्तान में सैनिक कार्रवाई करने का फ़ैसला भी पाकिस्तान लेगा, अमेरिका नहीं. उनके इस बयान पर पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है. कयानी के बयान के बाद चीन ने भी अपने पत्ते खोल दिए. उसने कहा कि वह पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देगा. भारत अभी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और 2012 में उसका टर्म पूरा हो रहा है. चीन के इस बयान से दूसरे टर्म के लिए भारत की सदस्यता पर असर पड़ेगा. उधर नाटो ने भी कहा है कि पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाक़ा जो आतंकवादियों की शरणस्थली है, उसकी जद से बाहर नहीं है. इस बयानबाज़ी से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच फिर कड़वाहट पैदा हो गई है. दोनों के बीच संबंधों में सुधार आतंकवाद विरोधी लड़ाई के लिए आवश्यक है. अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है कि हक्कानी नेटवर्क की जड़ें काटने के लिए उसे पाकिस्तान के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी. इससे पहले अमेरिका ने तालिबान के विरुद्ध अफ़ग़ानिस्तान में और सद्दाम हुसैन के विरुद्ध इराक में सैनिक कार्रवाई की थी. दोनों कार्रवाइयों में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही थी और आगे भी अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता पड़ेगी. अमेरिका को हक्कानी नेटवर्क का सफाया करना है. वह जानता है कि जब तक पाकिस्तान को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक ऐसा करना मुश्किल है. पाकिस्तान चाहे माने या न माने, यह तो साफ है कि हक्कानी नेटवर्क को आईएसआई का संरक्षण हासिल है. पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान का एक मतलब यह भी हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान फिर से सैनिक शासन की दहलीज पर तो नहीं खड़ा है, कयानी कहीं अपनी महत्ता तो नहीं बढ़ा रहे. पाकिस्तान में सैनिक शासन कोई नई बात नहीं है और जब भी सेना प्रमुख ताक़तवर होता है तो यह आशंका और बढ़ जाती है. कयानी आजकल जैसे बयान दे रहे हैं, उनसे तो यही लगता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले बयान देना सेना का नहीं, राजनीतिक नेतृत्व का काम है. अगर ऐसा हुआ तो भारत को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सैनिक शासन हमेशा उसके प्रतिकूल रहा है.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

इब्सा सम्मेलन
विकास के लिए आपसी सहयोग ज़रूरी

राजीव कुमार

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए गठित इब्सा (आईबीएसए) की पांचवीं बैठक बीते 18 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में संपन्न हुई. बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा एवं ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ ने हिस्सा लिया. तीनों देशों के प्रमुखों ने कई मुद्दों पर आपसी सहमति जताई. बैठक को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि यूरोप और विकसित देशों को अपने यहां मंदी रोकने के लिए जल्द ही प्रभावी क़दम उठाने चाहिए. विकसित देशों में आई मंदी का ख़ामियाज़ा विकासशील देशों को भुगतना पड़ता है. उन्होंने कहा कि यूरोप में सरकारी क़र्ज़ संकट तो चिंता का विषय है ही, इसके अलावा अमेरिका, यूरोप और जापान जैसी परंपरागत रूप से मज़बूत अर्थव्यवस्थाओं के मंदी की चपेट में आने से वैश्विक वित्तीय और पूंजी बाज़ारों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा. अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की इन बातों पर विचार किया गया और इन्हें अन्य दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने भी स्वीकार किया. तीनों नेताओं ने कहा कि नई आर्थिक मंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने और उसे मज़बूत आधार प्रदान करने के लिए जी-20 देशों के बीच नीतिगत समन्वय की आवश्यकता है. तीनों देशों ने एक-दूसरे के सहयोग से अपनी अर्थव्यवस्था मज़बूत करने की भी बात कही.

अर्थव्यवस्था के अलावा जिन मुद्दों को बैठक में शामिल किया गया, उनमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों में होने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने, सुरक्षा परिषद का विस्तार, दोहा वार्ता को सफल बनाने के प्रयास और पर्यावरण सुरक्षा आदि प्रमुख थे. मनमोहन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों में होने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने की बात जोर-शोर से उठाते हुए कहा कि इन संस्थाओं में नियुक्ति करते समय योग्यता का ध्यान रखा जाए, न कि किसी देश विशेष का. उनका उद्देश्य मुख्य रूप से विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख पद पर कुछ विकसित देशों के दबदबे की ओर अन्य देशों का ध्यान आकर्षित करना था. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा एवं ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ ने भी अपने विचार व्यक्त किए. जुमा ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था असंतुलन को दर्शाती है. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का झुकाव विकसित देशों की ओर है, इसीलिए विकासशील देशों के साथ न्याय नहीं हो पाता है. सुरक्षा परिषद में विस्तार का मुद्दा भी इस बैठक में प्रमुखता से उठाया गया. भारतीय प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा परिषद को वास्तव में अपनी भूमिका निभानी है तो उसे विश्व व्यवस्था में हो रहे नए परिवर्तनों को स्वीकार कर ख़ुद का विस्तार करना होगा.

ग़ौरतलब है कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ देशों को भारत का स्थायी सदस्य बनना मंजूर नहीं है, इसलिए अब तक ऐसा नहीं हो सका. हालांकि भारत अकेले सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की बात नहीं करता, बल्कि उसका विस्तार चाहता है. इसके लिए भारत, ब्राजील, जापान एवं जर्मनी ने जी-4 नामक संगठन भी बनाया है. अफ्रीका के प्रतिनिधि के रूप में यदि दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो भारत का पक्ष मज़बूत होगा. यह एक अच्छा संयोग है कि इस समय भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका तीनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं. इसके अलावा तीनों देशों के नेताओं ने कई अन्य अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर भी अपनी बात रखी. भारतीय प्रधानमंत्री ने दोहा वार्ता सफल बनाने का आह्वान किया. सीरिया और लीबिया के मुद्दों पर भी चर्चा की गई. ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ ने कहा कि सीरिया में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने लीबिया में नाटो की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि अफ्रीका में शांति बहाली के लिए नाटो द्वारा किया गया सैन्य हस्तक्षेप उचित नहीं है. जैकब जुमा ने समुद्री लुटेरों के बढ़ते आतंक पर चिंता जताई और हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर में बढ़ रहे ख़तरों के प्रति सावधान करते हुए इस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास की बात कही.

बैठक में हिस्सा लेने के बाद मनमोहन सिंह ने दोनों देशों के प्रमुखों से अलग-अलग वार्ता की. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए साझा प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया. दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोत्तरी हो रही है. पिछले साल जब जैकब जुमा भारत की यात्रा पर आए थे तो 2012 तक दोनों देशों के बीच 10 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे इस साल के मार्च महीने में ही पूरा कर लिया गया. यूं तो यह उत्साहवर्द्धक है, लेकिन भारत के लिए इसे बढ़ाने की कोशिश करना ज़रूरी है. भारत को यह बात याद रखनी चाहिए कि अभी भी दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार चीन है. भारत को यदि इस देश के साथ संबंध बेहतर करने हैं तो इसके साथ आर्थिक संबंध और बढ़ाने होंगे. चीन से जुड़े आर्थिक हितों के कारण ही दक्षिण अफ्रीका ने दलाई लामा को वीजा नहीं दिया. भारत ने दक्षिण अफ्रीका से यूरेनियम उपलब्ध कराने की भी अपील की है. अगर दक्षिण अफ्रीका हमें यूरेनियम देता है तो यह लंबे समय के लिए हमारे देश के हित में होगा. दक्षिण अफ्रीका परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य है और एनएसजी ने भारत को छूट भी दी है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्राजील की राष्ट्रपति के साथ भी वार्ता की और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीक़ों पर विचार-विमर्श किया. भारतीय प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रमुखों को अगले साल दिल्ली में होने वाले ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और अगला इब्सा सम्मेलन भारत में कराने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया.

भारत के लिए इस संगठन की काफी अहमियत है. तेजी से बढ़ती इन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ बेहतर संबंध भारत के हित में हैं. इन दोनों देशों को बड़े स्तर पर निवेश की आवश्यकता है और भारतीय कंपनियां अब विदेशों में निवेश करने के लिए तैयार भी हैं. यदि भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी है तो यह ज़रूरी है कि वह दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध मज़बूत करें. भारत पर इन देशों को चीन से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन केवल भरोसे से काम नहीं चलता. चीन इन देशों में निवेश करता है. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों जैसे आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और सुरक्षा परिषद आदि में सुधार के लिए भी भारत को इन देशों के सहयोग की आवश्यकता होगी और इन्हें भारत की. सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि विकासशील देशों के ऐसे संगठन अपने उद्देश्य में कामयाब होते हैं तो विकसित देशों पर इनकी निर्भरता कम होगी. दक्षिण-दक्षिण सहयोग से ही विकासशील देशों का विकास होगा, अन्यथा विकसित देश हमेशा अपने लाभ के लिए इनका उपयोग करते रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

साई बाबा सच्चे संत थे

वह हिंदू-मुस्लिम एकता चाहते थे, इसलिए मुसलमानों के त्योहार ईद आदि भी मनाते थे. दीपावली के दिन उनका निवास स्थान दीपमालिका से जगमगा उठता था. बाबा का निवास स्थान मस्जिद में था. तुलसीदास जी के इस कथन, मांगि के खैबो, मजीद में सोइबो के साई बाबा मूर्तिमान स्वरूप थे.

कई भक्तों द्वारा काफी आग्रह करने पर एक बार बाबा ने बताया था कि वह नौरंगाबाद से आए हैं. वह अपने मामा, जिनका नाम नासत्या था, के घर रहते थे. लोग उन्हें साई कहते थे. वेंकुश उनके गुरु थे. उनका धर्म कबीर था और परवरदिगार (परमात्मा) उनकी जाति थी. वह अपने गुरु के समाधि स्थल की खोज में शिरडी आए थे. साई बाबा शरीरधारी होते हुए भी विशुद्ध आत्मा थे. आत्मा की कोई जाति नहीं होती. इसलिए वास्तव में आत्म ज्योति स्वरूप साई बाबा न हिंदू थे, न मुसलमान. संत और सूफ़ी जाति के झमेले से ऊपर और निर्लिप्त होते हैं, किंतु सभी आत्म दृष्टि वाले नहीं होते और जब तक आत्मा शरीर में निवास करती हुई व्यक्त रूप में रहती है, तब तक सांसारिक लोगों का मन जाति और धर्म पर ही अटका रहता है. साई बाबा के जीवनकाल में ही यह प्रश्न उठता था कि बाबा हिंदू संत हैं या मुसलमान फ़क़ीर? आज भी अज्ञानी लोग उन्हें कुछ का कुछ समझते हैं. जाति और धर्म संबंधी प्रश्न उठते ही रहते हैं. मक्का में गुरु नानक जब मस्जिद की ओर पैर करके सोए थे, तब वहां के निवासियों ने कुपित होकर उनसे पूछा था कि वह कौन हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया था:-

हिंदू कहौं तो मारिए, मुसलमान हूं नाहिं,
पांच तत्व का पुतला, नानक मेरा नाम.

जाति तो पांच तत्व से निर्मित नश्वर देह की होती है, न कि ज्ञान स्वरूप आत्मा की. इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा है:-

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान.

फिर भी साई बाबा के संबंध में प्रमाणपूर्वक निश्चयात्मक रूप से सिद्ध करके बताया जा सकता है कि वह हिंदू ही थे और वह भी ब्राह्मण. शिरडी के साई बाबा का कर्ण छेदन संस्कार हुआ था. उनके कान छिदे हुए थे. कर्ण छेदन हिंदुओं के सोलह संस्कारों में से एक है. बाबा मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे. स्वयं में पंढरपुर के विट्ठल भगवान का दर्शन करा देना इसका प्रमाण है. जिन भक्तों के राम, कृष्ण या शिव यानी जो भी इष्ट थे, साई बाबा उन्हें उसी रूप में दिखते थे. साई बाबा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी के साकार स्वरूप थे. साई बाबा हिंदुओं के त्योहार मनाते थे, जिनमें कृष्णाष्टमी और राम नवमी मुख्य थे. वह हिंदू-मुस्लिम एकता चाहते थे, इसलिए मुसलमानों के त्योहार ईद आदि भी मनाते थे. दीपावली के दिन उनका निवास स्थान दीपमालिका से जगमगा उठता था.

बाबा का निवास स्थान मस्जिद में था. तुलसीदास जी के इस कथन, मांगि के खैबो, मजीद में सोइबो के साई बाबा मूर्तिमान स्वरूप थे. साई बाबा को भगवान श्रीकृष्ण के निवास स्थान द्वारिकापुरी से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने निवास स्थान का नाम द्वारका माई मस्जिद रख लिया था. वह द्वारका माई में रात-दिन लगातार धूनी जलाते थे. आज भी शिरडी में उनके समाधि स्थल पर धूनी जलती रहती है. धूनी तो हिंदू संत ही जलाते हैं. यह काम अग्निहोत्र कहलाता है, जिसे अग्निहोत्री ब्राह्मण करते हैं. बाबा के निवास स्थान पर उनकी प्रात:, मध्यान्ह और संध्या समय आरती की जाती थी और शंख एवं घंटे बजाए जाते थे. वहां लोग उनके दर्शन करते थे. नाम सप्ताह, कीर्तन और सत्संग किए जाते थे. उस मस्जिद अथवा साई बाबा के मंदिर के ऊपर हिंदुओं के झंडे लहराते थे. साई बाबा के भक्त उन्हें साष्टांग दंडवत करते थे और साई बाबा सर्व रोगनाशक धूनी की पवित्र भस्म लोगों को वितरित करते थे. शिरडी के साई बाबा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे. उन्हें वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत, विष्णु सहस्र नाम जैसे ग्रंथों में पूर्ण आस्था थी. भक्तजन साई बाबा को चंदन लगाते थे.

साई बाबा योगी और वेदांती थे. वह स्वयं एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखते थे और सबका मालिक एक उनका सिद्धांत था. उन्हें नवधा भक्ति पर पूर्ण विश्वास था. शिरडी के साई बाबा के लिए खंड योग, धौति, नेति और समाधि अत्यंत सामान्य कर्म थे. शिरडी में म्हालसापति साई बाबा के अनन्य भक्त थे. वह उनके साथ द्वारका माई मस्जिद और चावड़ी में सोते थे. उनके आग्रह पर साई बाबा ने उन्हें बताया था कि वह ब्राह्मण हैं और पथरी उनका गांव है. एक बार जब पथरी से कुछ लोग आए थे तो बाबा ने उनसे वहां के कुछ व्यक्तियों के बारे में पूछा था. काशीबाई कानेटकर जब मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ रही थीं, तब उनकी शंका का निवारण करने के लिए बाबा बोले थे कि मैं ब्राह्मण हूं, शुद्ध ब्राह्मण. यह ब्राह्मण (साई बाबा) लाखों लोगों को धर्म के मार्ग पर चला सकता है और उन्हें मुक्त कर सकता है.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

सद्गुरु और परब्रह्म

शिरडी के साई बाबा सद्गुरु थे. साई बाबा को साई नाथ भी कहते हैं. सबसे पहले सद्गुरु के लक्षणों और विशेषताओं को जानना आवश्यक है. सद्गुरु का प्रमुख लक्षण है कि वह शांति का अक्षय भंडार होता है. उसके समीप जाते ही मन को असीम शांति मिलती है. सद्गुरु जीव को उसके स्वभाव अथवा आत्मा में स्थित कर देता है. वह अपने उपदेश से इहलोक और परलोक से विरक्ति उत्पन्न कर मन को आत्मदर्शन में लीन कर देता है. इसी आधार पर भगवान श्रीकृष्ण संसार के सद्गुरु हैं. इसी प्रकार शिरडी के साई बाबा भी सद्गुरु हैं. वह सदैव आत्मरत रहते थे और बाहर से अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं करते थे. साई बाबा में अलौकिक आकर्षण था. जो भी उनके दर्शन करता था, वह मुग्ध हो जाता था. अपनी महासमाधि के बाद आज भी वह अपने निर्गुण रूप में उन लोगों का कल्याण करते हैं, जो उनके चरणों में निष्कपट होकर श्रद्धा और विश्वासपूर्वक झुक जाते हैं. साई बाबा महान संत थे.

संत पंचायतन

संत वे जीवनमुक्त आत्माएं होते हैं, जो युग-युग में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं. कई संत एक साथ संसार में आते हैं और अधर्म का निवारण तथा धर्म का प्रचार करते हैं. कहा जाता है कि कुछ शताब्दी पूर्व महाराष्ट्र में दास पंचायतन था, जिसमें (1) समर्थ स्वामी रामदास (2) जयराम स्वामी (3) रंगनाथ स्वामी, (4) केशव स्वामी और (5) आनंदमूर्ति सम्मिलित थे. इसी प्रकार साई बाबा के समय नाथ पंचायतन था, जिसमें (1) माधव नाथ (2) श्री सद्गुरु साई नाथ (साई बाबा) (3) ढुंढिराज पलुसी (4) शेगांव के गजानन महाराज और (5) नासिक के गोपाल दास (नरसिंह महाराज) थे. ये सब एक साथ, पर अपने ढंग से काम करते थे. नाथ पंचायतन में साई बाबा का बड़ा सम्मान था. साई बाबा को माधव नाथ कोहिनूर और त्रिलोकीनाथ कहा करते थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संपादकीय विवेक पर सवाल

अनंत विजय

बात कई साल पुरानी है. प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली से आलोचक देवेंद्र चौबे की किताब समकालीन कहानी का समाजशास्त्र प्रकाशित हुई थी. मैंने कथादेश के संपादक हरि नारायण जी से उक्त किताब पर समीक्षा लिखने की अनुमति मांगी. हरि नारायण जी ने कृपापूर्वक उक्त पुस्तक की समीक्षा लिखने की अनुमति दे दी. मैंने श्रमपूर्वक किताब की समीक्षा लिखकर कथादेश को तय समय सीमा में प्रेषित कर दी. कथादेश के अंक में जब अगले अंक का विज्ञापन छपा तो उसमें यह घोषणा की गई कि मेरी समीक्षा आगामी अंक में प्रकाशित होगी. मुझे संतोष हुआ कि चलो संपादक को समीक्षा पसंद आई. महीने भर की प्रतीक्षा के बाद जब कथादेश का अगला अंक प्रकाशित हुआ तो मैंने हुलस कर पूरी पत्रिका देख डाली, लेकिन उसमें समीक्षा नहीं दिखी. निराशा में मैंने संपादक हरि नारायण को फोन किया तो उन्होंने बताया कि मेरी समीक्षा विध्वंसात्मक (सही शब्द अब याद नहीं है, लेकिन आशय यही था) है, इस वजह से वह उसे प्रकाशित नहीं कर पाएंगे. मैंने उनसे कहा कि आपने तो विज्ञापित कर दिया था, लेकिन बाद में हृदय परिवर्तन कैसे हुआ. उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था. मैंने समीक्षा वापस मांग ली, जो मेरे पास डाक से आ गई. मेरी लिखी समीक्षा में कांट–छांट की गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह प्रकाशित नहीं हुई. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फिर कई साल बीत गए. अभी हाल में मेरी फाइलों में मुझे वह समीक्षा मिल गई तो पूरा वाक़या एक बार फिर से ताज़ा हो गया. मैंने सोचा कि उस वाक़ए और समीक्षा को पाठकों के सामने रखा जाए.

बहुत पहले इटली के मार्क्सवादी चिंतक अंतोनियो ग्राम्शी ने सबाल्टर्न शब्द समाज के उत्पीड़ित, दलित, गौण एवं महत्वहीन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया था. इसके आधार पर बाद में भारतीय इतिहास का भी अध्ययन किया गया. समाजशास्त्र के लिए न सिर्फ़ इतिहास, बल्कि साहित्य भी एक आधार और स्रोत होता है. साहित्य की एक विधा कहानी में सबाल्टर्न समाज के गौण या महत्वहीन व्यक्तियों के आधार पर देवेंद्र चौबे ने समकालीन कहानी का समाजशास्त्र तैयार किया है, परंतु उन्होंने ग्राम्शी के सबाल्टर्न के स्थान पर अमेरिकी समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित किए गए मार्जिनल मैन, जिसका अनुवाद लेखक ने सीमांत आदमी किया है, की अवधारणा को भारतीय समाज के संदर्भ में एक बड़े दायरे में समेटने का प्रयास करने का दावा किया है. अमेरिका में रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत आदमी के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीमांत आदमी मिश्रित ख़ून का आदमी होता है.

देवेंद्र चौबे की इस शोधपरक पुस्तक लिखने की योजना एकदम फिल्मी अंदाज़ में बनती है. लेखक किसी गोष्ठी से लौटते समय बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रहा होता है. साथ में आलोचक मैनेजर पांडे भी होते हैं. अचानक लेखक के मन में बात आती है और पांडे जी की प्रेरणा से इस पुस्तक की योजना बनती है. इस पुस्तक के शीर्षक में समकालीन शब्द है. यह शब्द बहुत ही गंभीर और विशद विवेचना की अपेक्षा रखता है, परंतु लेखक ने पुस्तक में कहीं भी समकालीनता को परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं किया है. सिर्फ़ भूमिका में एक जगह संकेत है कि 1970 के बाद की कहानियों को उन्होंने अपनी सोच का आधार बनाया है. सैद्धांतिक रूप से कहानी ख़ासकर समकालीन हिंदी कहानी की उस केंद्रीय प्रवृत्ति और दृष्टि को पकड़ने की कोशिश अब तक नहीं की गई, जिसकी ज़रूरत थी और जिसके माध्यम से 1970 के बाद की हिंदी कहानी समाज विज्ञान की अन्य विधाओं से जुड़कर अपनी एक स्वतंत्र छवि बनाती है. यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या 1970 के पहले की कहानियों में हाशिए के लोग मौजूद नहीं थे या उसके पहले के कहानीकार समकालीन नहीं थे या इस शोध ग्रंथ में कहानी एवं कहानीकारों का चयन किसी अदृश्य आधार पर किया गया है.

इस पुस्तक में लगभग तीन दर्जन से अधिक व्यक्तियों का आभार प्रकट किया गया है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लेखक की जनसंपर्क शास्त्र में कितनी

रुचि है. अब अगर हम इस पुस्तक पर बात करें तो पाते हैं कि अति विकसित, विकसित और अविकसित यानी सभी समाज में मुख्य धारा से बाहर और मुख्य धारा के भीतर ऐसे हाशिए का समाज होता है और अर्से से हाशिए के लोग अपने समय के कहानीकारों की कहानियों का विषय भी बनते रहे हैं. भारतीय समाज के संदर्भ में हम पाते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से एक बड़ा वर्ग हाशिए पर चला जाता है. देवेंद्र चौबे ने अपनी इस पुस्तक में हाशिए पर चले जाने के कारणों की, कहानी में वर्णित पात्रों के आधार पर पड़ताल करने का प्रयास किया है, परंतु अगर समाजशास्त्रीय व्याख्या करनी है तो हमें भारतीय समाज की संरचना और आज़ादी के बाद जो सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया चली, उसे श्यामाचरण दुबे (प्रसिद्ध समाजशास्त्री) की तरह समझने की ज़रूरत है, लेकिन लेखक ने गहराई में न जाकर शॉर्टकट अपनाया है.

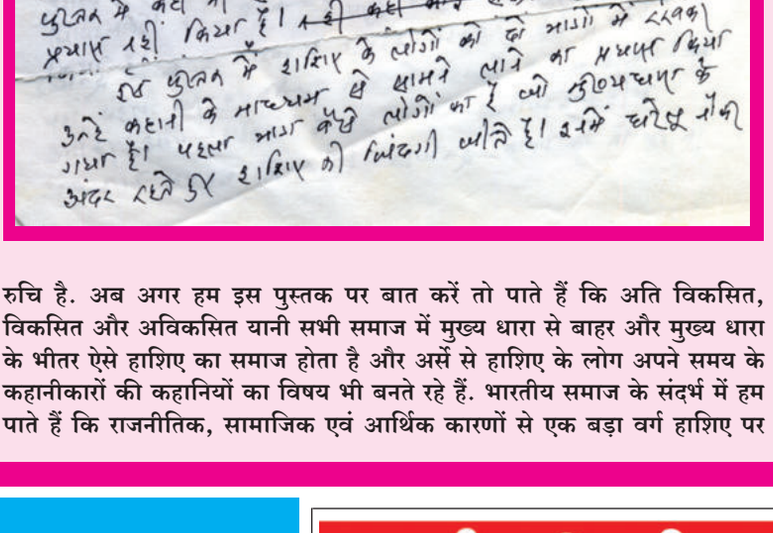

इस पुस्तक में हाशिए के लोगों को दो भागों में रखकर उन्हें कहानी के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया गया है. पहला भाग वैसे लोगों का है, जो मुख्य धारा के अंदर रहते हुए हाशिए की ज़िंदगी जीते हैं. इनमें घरेलू नौकर, स्वरोज़गार में लगे लोग, बेबस स्त्रियां, खेतिहर और दिहाड़ी मज़दूर हैं. मुख्य धारा से बाहर के लोगों में उन्होंने सिर्फ़ आदिवासियों को रखा है. बेबस स्त्रियां और समकालीन हिंदी कहानी लिखते हुए लेखक का मानना है कि दरअसल स्त्रियों के साथ सबसे बड़ी त्रासदी उनका स्त्री होना ही है. वेश्याओं और कॉलगर्ल को भी उन्होंने हाशिए का आदमी माना है, जबकि सामान्यतय: कॉलगर्ल किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इस व्यवसाय को अपनाती है. सामाजिक संरचना इसके लिए कहां से ज़िम्मेदार है. स्त्रियों की स्थिति में भी काफ़ी बदलाव आया है और अब वह ज़माना नहीं रहा कि सामंती मानसिकता वाले उच्चवर्गीय परिवार के पुरुष दलित और निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ कुछ भी करना अपना अधिकार समझते हों. ये सब बीते ज़माने की बातें हैं और अब निम्नवर्गीय समाज में इतनी चेतना तो आ ही गई है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उसका अन्नदाता या पालनहार ही क्यों न हो, उसकी देह के साथ उसकी मर्ज़ी के बग़ैर खेल नहीं सकता.

इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लगा कि लेखक समकालीन कहानी के बारे में स्पष्ट नहीं हैं और जिन कहानीकारों की कहानियों को उन्होंने उद्धृत किया है, उनमें पीढ़ियों के अंतराल और कहानी के विकास का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है. इसके अलावा कहानियों के मार्फ़त बात कहने में विस्तार और दोहराव ज़्यादा है. लेखक ने अपनी पसंद के कहानीकारों को स्थान देकर अपना जनसंपर्क शास्त्र मज़बूत किया है. शिव प्रसाद सिंह ने ऐसी कई कहानियां लिखीं, जिनमें भिखारी, मज़दूर आदि का वर्णन है, परंतु देवेंद्र चौबे ने उन्हें छोड़ दिया है. बावजूद इसके इस पुस्तक का स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए कि इसने इस विषय पर एक बहस की शुरुआत तो की है और इस विषय पर भी आलोचकों का ध्यान दिलाया. इस पुस्तक का ब्लर्ब राजेंद्र यादव ने लिखा है, जिनके अनुसार, देवेंद्र चौबे ने यहां पहली बार व्यवस्थित रूप से हिंदी कहानी में बार–बार उभर कर आए हाशिए के लोगों का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है. राजेंद्र यादव का तो यह भी कहना है कि दलित और साहित्य विमर्श की पृष्ठभूमि जानने के लिए यह पुस्तक निश्चय ही एक वैज्ञानिक आधार ग्रंथ है, परंतु मुझे लगता है कि यादव जी के इस आधार ग्रंथ का आधार बहुत मज़बूत नहीं है. वैसे भी हिंदी में ब्लर्ब लेखन की जो परंपरा है, उसके हिसाब से राजेंद्र यादव ने जो लिखा है, वह झूठ नहीं है.

मेरे पास यह समीक्षा लिखे जाने की तारीख़ उपलब्ध नहीं है. ख़ुद के लिखे कई शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं. इस वजह से हो सकता है कि मूल समीक्षा से दो–चार शब्द अलग हों, लेकिन मैंने पूरी समीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया. यह सब लिखने के पीछे मेरा आशय केवल इतना है कि कैसे हिंदी साहित्य की शीर्ष पत्रिकाओं में शुमार कथादेश में स्वीकृत और विज्ञापित समीक्षा भी नहीं छपती है. मेरा कहना उस वक़्त भी यही था और अब भी यही है कि स्वीकृत और विज्ञापित करने से पहले एक बार रचना को पढ़ तो लेना ही चाहिए. लेकिन हरि नारायण जी का इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने मेरी हाथ से लिखी समीक्षा वापस कर दी. कंप्यूटर के चलन के बाद मेरे पास हस्तलिखित यह एकमात्र रचना है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

नवांकुरों का साहस भरा प्रयास

नहीं जाती कहीं भी/वह रहती है सदा
अपने स्थान पर/बिना किसी शिकायत के
मैं ही चलता हूं/बिना रुके बिना थके
मंजिल की चाह में/भटकता रहता हूं
यहां से वहां.

महेंद्र अवधेश

यह कौशल तिवारी की उस कविता की शुरुआती पंक्तियां हैं, जिसमें उन्होंने सड़क को आधार बनाते हुए व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पर रोशनी डालने का प्रयास किया है और जो एक ऐसी साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित हुई है, जिसने अभी–अभी जन्म लिया है. दरअसल बीते दिनों दिल्ली पुस्तक मेले में राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पर एक लड़की मिली, जिसने यह जानकर कि हम मेला कवर करने के लिए आए हैं, हमें एक साहित्यिक पत्रिका दी, जिसका नाम है समसामयिक सृजन और उस लड़की का नाम है साक्षी. साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति जैसे विस्तृत और अति गंभीर विषयों पर कलम भांजने की यह कोशिश दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हंसराज कॉलेज और जानकी देवी कॉलेज से पास आउट करके निकले दो होनहार युवा कर रहे हैं यानी साक्षी और महेंद्र प्रजापति. अपने जीवन अनुभवों के सहारे उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. प्रभात कुमार एवं डॉ. रमा. इस त्रैमासिक पत्रिका का यह दूसरा अंक

(सितंबर–नवंबर) है. नौ आलेखों, छह कविताओं, व्यंग्य और समीक्षा से सजा पत्रिका का यह अंक कई सवाल उठाता है, चिंता व्यक्त करता है. नारी शक्ति को समर्पित इस अंक में महिला सशक्तिकरण को लेकर लेखकों ने व्यापक विचार मंथन किया है. प्रथम पांच आलेख इसी विषय पर केंद्रित हैं.

पूजा प्रजापति ने अपनी कविता में दर्द की मौजूदगी को व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है, उन्होंने बताने की कोशिश की कि दर्द कब, कहां और किस रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकता है. जैसे–

रेशम के धागे को/बांधा जिस कलाई पर
उन्हीं हाथों ने जब/बेच दिया किसी को
तो पूछता है हर धागा/दर्द कहां है?

इसके अलावा चंद्रभूषण कनौजिया और अंकिता चौहान की कविताएं भी प्रभावित करती हैं. लोक गीतों में दांपत्य प्रेम की अभिव्यक्ति शीर्षक से प्रकाशित आलेख में विजय कुमार सिंह ने विषय के साथ यथासंभव न्याय किया है. मेरा मानना है कि अगर किसी में कुछ अच्छा करने का हौसला दिखे तो उसकी तमाम ग़लतियां क्षम्य मानी जानी चाहिए, लेकिन उस ओर इशारा करना ज़रूरी है. इस लिहाज़ से कहना यह है कि पत्रिका में संपादन और प्रूफ रीडिंग में बीच–बीच कुछ ढीलापन दिखता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि साहित्यिक पत्रिका का पाठक इन बातों पर पैनी नज़र रखता है. साहित्यिक पत्रिका निकालना आज के समय में स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे जूझने का जज़्बा रखने वाले और वे भी, जो ऐसे लोगों का उत्साहवर्द्धन कर रहे हैं, निस्संदेह बधाई के पात्र हैं.

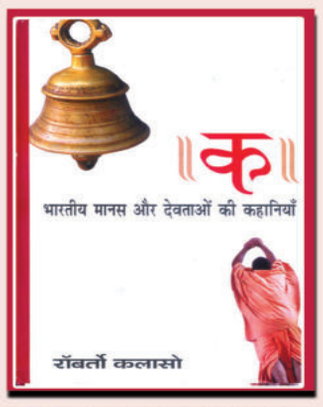

m_awdhesh@chauthiduniya.com

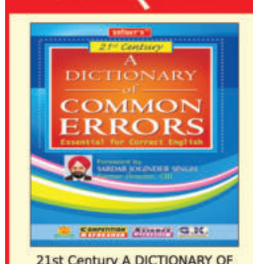

किताब मिली

पुस्तक का नाम: क — भारतीय मानस और देवताओं की कहानियां

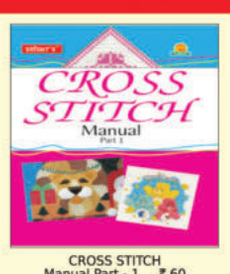

लेखक: रॉबर्तो कलासो

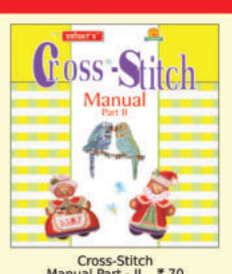

प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

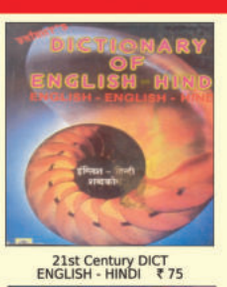

मूल्य: 450 रुपये

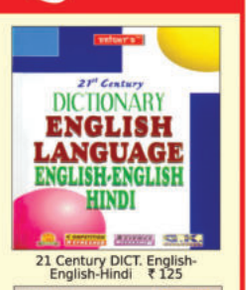

यह किताब भारतीय मानव और देवताओं की कहानियों का एक अद्भुत संग्रह है.

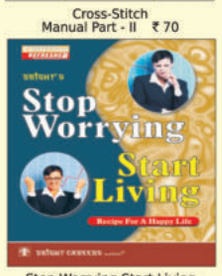

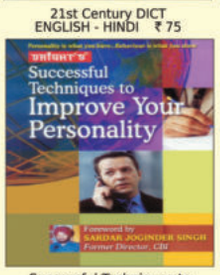

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्राईट® की सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

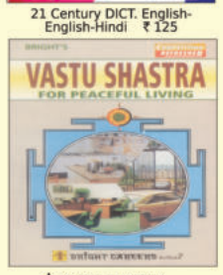

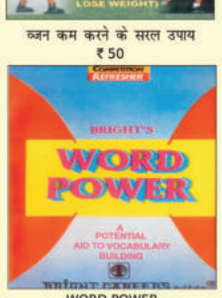

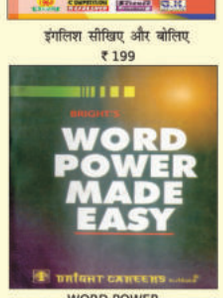

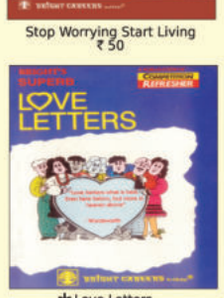

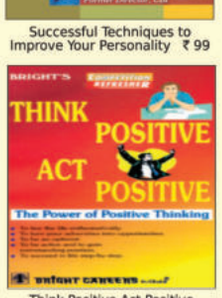

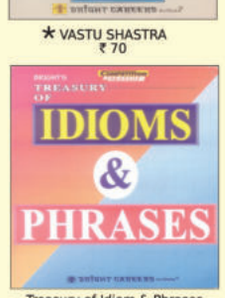

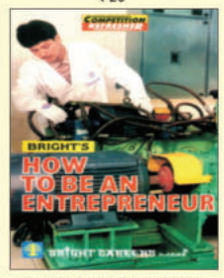

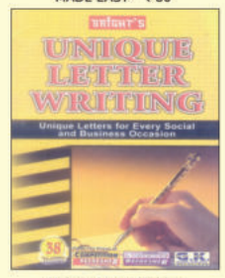

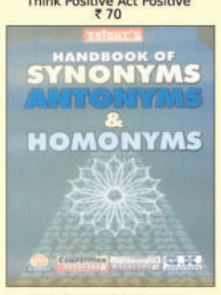

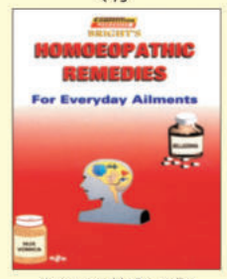

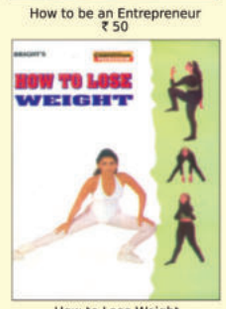

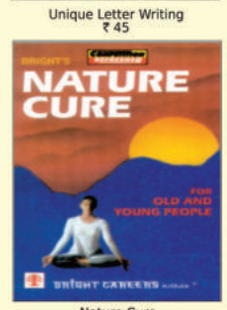

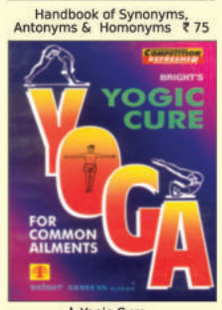

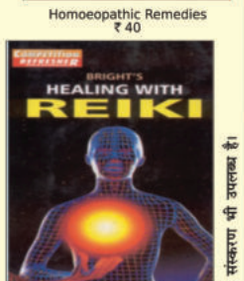

FROM THE HOUSE OF : BRIGHT® Career's® BOOKS   COMPETITION REFRESHER   SCIENCE REFRESHER   G.K. GENERAL KNOWLEDGE REFRESHER

BRIGHT PUBLICATIONS®
Publishers of INDIA'S LARGEST SELLING Competition & School Books
2767, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India) —— (ESTD. 1968)
Ph.: 011-64632226 & 3226, 23282226 & 3226 Fax: 011-23269227 Telefax: 64633226
E-mail: sales@brightpublications.com Web Site: http://www.brightpublications.com

FOR VPP ORDERS, SEND ₹ 25/- AS ADVANCE & FOR FREE CATALOGUE WRITE TO US

पुरस्कार हासिल करने के बाद हरिओम सिंह ने इसे पूरे कंपनी की उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार हरिओम कंस्ट्रक्शन को नई प्रेरणा देगा.

हुवाई का क्वर्टी की-पैड फोन

हुवाई ने कम क़ीमत के फोन पसंद करने वाले यूज़रों को ध्यान में रखते मेट्रो पीसीज केअंतर्गत पिनैकल नामक एक शानदार फोन बाज़ार में उतारा है. स्मार्ट फोन के बाद हुवाई अब बाज़ार में ऐसे फोन पेश करने पर विचार कर रही हैं, जिनमें यूजर की ज़रूरत के हिसाब से फीचर मौजूद हों.

तकनीक का इस्तेमाल जीवन को सरल बनाने के लिए होना चाहिए, उलझाने के लिए नहीं. ज़्यादातर फोनों में ऐसे फीचर हैं, जिनका लोग प्रयोग नहीं करते, मगर उन फीचरों की वजह से फोन की क़ीमत ज़रूर बढ़ जाती है. हुवाई ने कम क़ीमत के फोन पसंद करने वाले यूजरों को ध्यान में रखते मेट्रो पीसीज के अंतर्गत पिनैकल नामक एक शानदार फोन बाज़ार में उतारा है. स्मार्ट फोन के बाद हुवाई अब बाज़ार में ऐसे फोन पेश करने पर विचार कर रही है, जिनमें यूजर की ज़रूरत के हिसाब से फीचर मौजूद हों. हुवाई पिनैकल में सीमित फीचर हैं, जिनका लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं. पिनैकल में सीडीएम नेटवर्क की सुविधा के साथ 2.4 इंच की क्यूवीजीए स्क्रीन है. फोन का लुक देखने में ब्लैकबेरी स्मार्ट फोन की तरह है. कैंडी बार शेप डिज़ाइन के साथ फोन में अच्छा कलर कांबिनेशन है. कम क़ीमत के बावजूद पिनैकल में ब्लूटूथ, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, जीपीएस और 1.3 मेगा पिक्सल कैमरा मौजूद है. इसके अलावा फोन में मेन मीनू का स्टाइल बदलने, कैमरे द्वारा खींची गई फोटो को नया लुक देने और वेब ब्राउजिंग के शानदार फीचर मौजूद हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट के बढ़ते क्रेज को देखते हुए पिनैकल में नेट कनेक्टिविटी द्वारा सभी सोशल साइटें एक्सेस की जा सकती हैं. मैसेजिंग और ईमेल टाइपिंग में टच से ज़्यादा बेहतर क्वर्टी की–पैड होता है, इसलिए पिनैकल में ब्लैकबेरी लुक का शानदार क्वर्टी की–पैड दिया गया है. इसमें 16 जीबी मेमोरी के साथ 3.5 एमएम जैक है. इस ख़ास फोन की क़ीमत सिर्फ़ 1960 रुपये है.

एसर का ट्रैवलमेट लैपटॉप

लंबे समय तक काम करने के बावजूद इस लैपटॉप में हीटिंग की समस्या नहीं आती. बाज़ार में मौजूद अधिकतर लैपटॉप 3-4 घंटे बाद गर्म होने लगते हैं, जिससे प्रोसेसर ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है. इस लैपटॉप का भार 1.6 किलो है, जो अन्य किसी लैपटॉप के मुक़ाबले कम है और इसे आप आराम से कैरी कर सकते हैं.

एसर ने ट्रैवलमेट 8481–जी नामक एक नया लैपटॉप लांच किया है, जिसमें कई यूजर फ्रैंडली फीचरों के साथ–साथ सुरक्षा फीचर भी है. नए ट्रैवलमेट की डिज़ाइन काफी आकर्षक है. टैवलमेट में 14 इंच की स्क्रीन है, जो 1366/768 पिक्सल रेज्योलूशन को सपोर्ट करती है. लैपटॉप का बॉडी पैनल पूरी तरह सनलाइट प्रोटेक्टेड है. मेट में स्लिम बॉडी के साथ कई नए रंगों का विकल्प दिया गया है. लंबे समय तक काम करने के बावजूद इस लैपटॉप में हीटिंग की समस्या नहीं आती.

बाज़ार में मौजूद अधिकतर लैपटॉप 3–4 घंटे बाद गर्म होने लगते हैं, जिससे प्रोसेसर ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है. इस लैपटॉप का भार 1.6 किलो है, जो अन्य किसी लैपटॉप के मुक़ाबले कम है और इसे आप आराम से कैरी कर सकते हैं. 4 जीबी रैम के साथ इसमें 120 जीबी की सॉलिड स्टेट ड्राइव है. इस लैपटॉप में फिंगर प्रिंट रीडर भी है, जिसकी मदद से केवल यूजर ही अपने लैपटॉप का प्रयोग कर सकेगा. एसर ट्रैवलमेट 8481–जी में चार यूएसबी पोर्ट के अलावा एचडीएमआई पोर्ट के विकल्प मौजूद हैं. अगर आप लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए वाईफाई और ब्लूटूथ की सुविधा मौजूद है. इसके अलावा इसमें वेबकैम, ईथरनेट, हेडफोन और माइक्रोफोन पोर्ट आदि फीचर भी हैं. 44 वॉट की बैट्री इनबिल्ड है, जो 4 घंटे का दमदार बैकअप देती है. ट्रैवलमेट 8481–जी की क़ीमत केवल 90,000 रुपये है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ह्योसंग की नई सुपर बाइक

दक्षिण कोरिया की बाइक निर्माता कंपनी ह्योसंग ने भारतीय बाज़ार में अपनी तीसरी सुपर बाइक पेश की है. रफ्तार के दीवानों के लिए पेश की गई इस नई सुपर बाइक का नाम जीटी–650 एन है. इसके पूर्व कंपनी ने अपनी सुपर बाइक जीटी–650 आर पेश की थी. भारतीय बाज़ार में इस नई बाइक की क़ीमत लगभग 4.39 लाख रुपये है. इसमें 650 सीसी की क्षमता का दमदार इंजन प्रयोग किया गया है. इसकी शानदार हेडलाइट आपको यामहा की एफजी याद दिलाएगी. इसका नेक्ड लुक इसकी दमदार क्षमता को दर्शाता है. 6 स्पीड की बेहतरीन गेयर क्षमता से लैस यह बाइक शानदार गति प्रदान करती है. भारतीय बाज़ार में ह्योसंग की जीटी–650 आर भी मौजूद है, जिसकी क़ीमत लगभग पौने पांच लाख रुपये है. ह्योसंग ने भारत में अपनी 250 सीसी की बाइक के साथ क़दम रखा था. कंपनी को उम्मीद है कि भारतीय युवाओं को नई सुपर बाइक बेहद पसंद आएगी.

भारतीय बाज़ार में इस नई बाइक की क़ीमत लगभग 4.39 लाख रुपये है. इसमें 650 सीसी की क्षमता का दमदार इंजन प्रयोग किया गया है. इसकी शानदार हेडलाइट आपको यामहा की एफजी याद दिलाएगी.

हरिओम को स्वर्ण पदक

बिहार–झारखंड के जाने–माने बिल्डर और हरिओम कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम सिंह को आईईडीआरए ने अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया है. पुरस्कार हासिल करने के बाद हरिओम सिंह ने इसे पूरे कंपनी की उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार हरिओम कंस्ट्रक्शन को नई प्रेरणा देगा. उन्होंने बताया कि कंपनी दो नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है.

हरिओम सनसिटी एनएच–30 पर होटल नील कमल के नज़दीक है, जबकि दूसरा हरिओम नगर प्रस्तावित बीआईटी स्टेशन मोड़ के पास है. उन्होंने बताया कि तीन बहुप्रतिष्ठित प्रोजेक्ट भी पहले से ही हरिओम कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं. श्री सिंह ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य हर आय वर्ग के लोगों को बसाना है. कंपनी काम की गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करेगी और ग्राहकों से किया गया हर वादा हर हाल में पूरा करेगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मोटोरोला के वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट

मोटोरोला ने हेडफोन की मांग को देखते हुए दो ब्लूटूथ हेडसेट लांच किए हैं. मोटोरोला इलाइट सिल्वर और मोटोरोला इलाइट फ्लिप नामक इन दोनों हेडफोन में नियर फील्ड और हाई डेफिनेशन ऑडियो प्लस तकनीक दी गई है, जो साउंड की क्वालिटी को बेहतर बनाती है. इन नए हेडफोन में 300 फीट की दूरी से भी कनेक्टिविटी बनी रहती है. दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर है. मोटोरोला फ्लिप और सिल्वर में मॉय मोटो स्पीक का भी फीचर है, जो इनकमिंग मैसेज को बोलकर बताता है. आप चाहें तो केवल बोलकर यानी बिना फोन को हुए मैसेज भेज सकते हैं. इलाइट फ्लिप में एक ऐसा फीचर है, जो इलाइट सिल्वर को अलग करता है. इलाइट फ्लिप में रेपिड कनेक्ट तकनीक है, जिसकी मदद से फ्लिप खोलते ही हेडफोन काम करना शुरू कर देगा और फ्लिप बंद करते ही हेडफोन बंद हो जाएगा, इससे देर तक चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. इलाइट फ्लिप 6 घंटे का टॉकटाइम एवं 12 दिनों का स्टैंडबॉय टाइम और इलाइट सिल्वर 15 घंटे का टॉक टाइम प्रोवाइड करता है. दोनों हेडसेटों का भार बाज़ार में मौजूद अन्य हेडसेटों के मुक़ाबले काफी कम है. इलाइट सिल्वर 5900 और इलाइट फ्लिप 4000 रुपये में उपलब्ध है.

मोटोरोला फ्लिप और सिल्वर में मॉय मोटो स्पीक का भी फीचर है, जो इनकमिंग मैसेज को बोलकर बताता है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

पहले ऐसी ख़बरें थीं कि फ़ुटबॉल की यह अंतरराष्ट्रीय संस्था तैयारियों की धीमी रफ्तार को लेकर चिंतित है.

बड़े आयोजनों का बड़ा फ़र्क़

राजेश एस कुमार

फ़ॉर्मूला वन रेस के आयोजन से कुछ ही दिनों पहले चौथी दुनिया ने इस आयोजन में आने वाली अड़चनों पर चर्चा की थी. इस रेस में कहीं ब्रेकर तो नहीं शीर्षक से प्रकाशित उस ख़बर में कई बिंदुओं पर आशंका जताई गई थी, मसलन निर्माण कार्य में देरी, मेहमाननवाज़ी और पैसे–ग्लैमर के कॉकटेल को लेकर पैदा होने वाले विवाद आदि. इसके कुछ ही दिनों के बाद फॉर्मूला वन रेस के ट्रैक में एक के बाद एक ब्रेकर आने लगे. पहला ब्रेकर है, यहां की निर्माण और देखरेख व्यवस्था का. उद्घाटन वाले दिन ही यानी 18 अक्टूबर तक सड़क से लेकर स्टॉल तक का कार्य पूरा नहीं हुआ था. हालांकि उस दिन इस तरह की अव्यवस्थाओं को पोस्टरों और बैनरों की आड़ में छिपा दिया गया था. दूसरा ब्रेकर सुप्रीम कोर्ट का वह नोटिस, जिसमें फॉर्मूला वन रेस के आयोजन को करमुक्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया. जस्टिस डी के जैन की खंडपीठ ने सरकार के साथ–साथ फॉर्मूला वन रेस को आयोजित करने वाले जेपी ग्रुप को भी नोटिस भेजा. इस नोटिस में कोर्ट ने सवाल उठाया कि इवेंट को मनोरंजन कर से छूट क्यों दी गई. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की. इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से फॉर्मूला वन रेस के आयोजन को मनोरंजन कर से छूट को चुनौती दी गई थी. हालांकि जवाब में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने यह ज़रूर कहा कि किसी भी कंपनी को अलग से कोई विशेष छूट अथवा सुविधा नहीं दी गई है. उन्होंने कई और आरोपों का भी खंडन किया. अब असलियत चाहे जो भी हो, लेकिन अगर किसी ने इस प्रकार की याचिका डाली है तो इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ दिनों बाद राज्य सरकार और जेपी ग्रुप अपने–अपने हिसाब से जवाब देकर अपना दामन बचा लेंगे.

ताज्जुब की बात यह है कि जिस फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक के उद्घाटन के दौरान इतनी सारी अनियमितताएं पाई गईं, उसके एफ–1 सर्किट में लगभग 400 मिलियन डॉलर की लागत आई. इसके अलावा इसमें बड़े–बड़े औद्योगिक घरानों का भी पैसा लगा हुआ है. पता नहीं क्यों, भारत में जब भी कोई खेल आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं. चाहे वह कॉमनवेल्थ का मामला हो या फिर फॉर्मूला रेस का. ऐसा भी नहीं है कि आयोजन समिति को सभी कार्य पूरा करने का पर्याप्त वक़्त नहीं मिलता. यह तो बहुत पहले ही तय हो गया था कि ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में इस रेस का आयोजन होना है. इस बात से सभी वाक़िफ़ थे कि इस आयोजन में विदेशी दर्शकों की तादाद ज़्यादा होगी. ऐसे में विदेशियों के सामने यह भारत की छवि का भी प्रश्न था, लेकिन पता नहीं, भारत ऐसे आयोजनों में हमेशा इस तरह की विषम परिस्थितियों में क्यों घिर जाता है. रेस तो जैसे–तैसे ख़त्म हो गई, लेकिन आयोजन की मेजबानी को लेकर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई.

एक बेहतरीन उदाहरण देखिए. फीफा वर्ल्डकप का आयोजन इस बार ब्राजील में होना है. फुटबॉल का यह विशाल आयोजन हमेशा दुनिया भर की निगाहों में रहता है, लेकिन वर्ल्डकप के इस आयोजन को लेकर ब्राजील बिल्कुल चिंतित नहीं है. ब्राजील को भी भारत के एफ-1 की तरह 2014 का फुटबॉल वर्ल्डकप कराने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन इसके बावजूद पर्याप्त समय का पूरा फ़ायदा उठाते हुए तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

एक बेहतरीन उदाहरण देखिए. फीफा वर्ल्डकप का आयोजन इस बार ब्राजील में होना है. फुटबॉल का यह विशाल आयोजन हमेशा दुनिया भर की निगाहों में रहता है, लेकिन वर्ल्डकप के इस आयोजन को लेकर ब्राजील बिल्कुल चिंतित नहीं है. ब्राजील को भी भारत के एफ–1 की तरह 2014 का फुटबॉल वर्ल्डकप कराने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन इसके बावजूद पर्याप्त समय का पूरा फ़ायदा उठाते हुए तैयारियां पूरी की जा रही हैं. पहले ऐसी ख़बरें थीं कि फुटबॉल की यह अंतरराष्ट्रीय संस्था तैयारियों की धीमी रफ्तार को लेकर चिंतित है. ख़ास तौर पर स्टेडियमों में सुधार और नए भवनों के निर्माण को लेकर फिक्र जताई गई थी, लेकिन बाद में जब फीफा अध्यक्ष जोसेफ ब्लाटर ने तैयारियों का जायज़ा लिया तो वह पूरी तरह संतुष्ट दिखे. आपको बता दें कि 2014 में होने वाले फीफा वर्ल्डकप के दौरान 12 अलग–अलग शहरों में मैच होंगे. ब्राजील में पिछला वर्ल्डकप 1950 में हुआ था. उसके लिए यह टूर्नामेंट एक और बड़े आयोजन की तैयारियों में फ़ायदेमंद साबित होगा. 2016 में रियो डे जनेरो में ओलंपिक होना है. फ़िलहाल रियो के माराकाना स्टेडियम में निर्माण कार्य चल रहा है. इसके अलावा साओ पाउलो में इताक्वेराओ एरीना बनाया जा रहा है, इस आयोजन का उद्घाटन समारोह हो सकता है. हालांकि वर्ल्डकप से पहले 2013 में कॉन्फेडरेशन कप होना है, जिसे वर्ल्डकप की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखा जाता है. इससे एक फ़ायदा यह होता है कि जो थोड़ी–बहुत कमियां रह जाती हैं, वे समय रहते ठीक कर ली जाती हैं. 12 जून से 13 जुलाई 2014 तक होने वाला वर्ल्डकप 20वां फीफा वर्ल्डकप होगा. 1950 के बाद ब्राजील को दूसरी बार वर्ल्डकप के आयोजन का अवसर मिला है. ब्राजील समेत पांच ही देश हैं, जिन्होंने एक से ज़्यादा बार वर्ल्डकप का आयोजन किया है. इससे पहले मेक्सिको, इटली, फ्रांस और जर्मनी ऐसा कर चुके हैं. यह टूर्नामेंट दक्षिण अमेरिका के लिए भी एक बड़ी बात है. 1978 में अर्जेंटीना वर्ल्डकप के बाद पहली बार यह टूर्नामेंट महाद्वीप में हो रहा है. साथ ही ऐसा पहली बार होगा कि वर्ल्डकप लगातार दो बार यूरोप से बाहर हुआ, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा पूरी दुनिया आश्वस्त रहती है कि फुटबॉल वर्ल्डकप का आयोजन बहुत धूमधाम से होगा. क्या दुनिया भारत के संदर्भ में भी इसी तरह आश्वस्त रहती है? शायद नहीं. अब यहां पर दो तस्वीरें हैं, एक ब्राजील की और दूसरी भारत की. दोनों ही देश बड़े आयोजनों की मेजबानी की तैयारियों को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों में कितना फ़र्क़ है!

rajeshy@chauthiduniya.com

उद्घाटन वाले दिन ही यानी 18 अक्टूबर तक सड़क से लेकर स्टॉल तक का कार्य पूरा नहीं हुआ था. हालांकि उस दिन इस तरह की अव्यवस्थाओं को पोस्टरों और बैनरों की आड़ में छिपा दिया गया था. दूसरा ब्रेकर सुप्रीम कोर्ट का वह नोटिस, जिसमें फॉर्मूला वन रेस के आयोजन को करमुक्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया. जस्टिस डी के जैन की खंडपीठ ने सरकार के साथ-साथ फॉर्मूला वन रेस को आयोजित करने वाले जेपी ग्रुप को भी नोटिस भेजा.

एक्सट्रा शॉट्स

अलविदा टेनिस

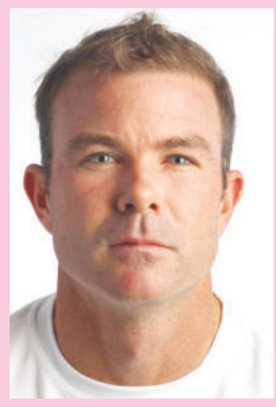

आस्ट्रेलिया के युगल विशेषज्ञ टेनिस खिलाड़ी एश्ले फिशर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है. हाल में संपन्न चीन मास्टर्स टूर्नामेंट के पहले दौर से बाहर होने के बाद 36 वर्षीय फिशर ने संन्यास लेने का निर्णय किया. फिशर 2009 के मध्य में चोट की वजह से कई महीनों तक टेनिस कोर्ट से दूर रहे. चौथी बार घुटने की सर्जरी कराने के बाद फिशर 2010 में कोर्ट पर नहीं उतर सके. उन्होंने चोट से उबर कर 2011 में वापसी की थी. वह मौजूदा सत्र में अपने जोड़ीदार स्टीफन हस के साथ फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम के पुरुष युगल वर्ग के तीसरे दौर में प्रवेश करने में सफल रहे थे. फिशर ने कुल चार युगल खिताब अपने नाम किए. इसके अलावा युगल वर्ग में उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 19 रही.

कांबली की चिंता

विनोद कांबली का मानना है कि आईपीएल युवा क्रिकेटरों को बर्बाद कर रहा है. नए खिलाड़ी टेस्ट नहीं, टी-20 खेलना चाहते हैं, इससे टेस्ट क्रिकेटरों का अभाव हो जाएगा. कांबली कहते हैं कि वह आईपीएल के ख़िलाफ़ नहीं हैं. यह मनोरंजन के लिए अच्छा है, लेकिन अधिक खेले जाने के कारण यह एक दिन सास, बहू और साजिश सीरियलों की तरह हो जाएगा, जो लंबे खींचे जाने से उबाऊ हो जाते हैं. कांबली पिछले दिनों एक अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने आए थे. उनके मुताबिक़ , अत्यधिक क्रिकेट के कारण मैदान पर दर्शकों की संख्या घट रही है. भारत-इंग्लैंड के बीच खेले गए दो वन डे मैच इसके गवाह हैं. जब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उस समय इस तरह के क्रिकेट को मंजूर नहीं किया जाता था. आज हर युवा क्रिकेटर आईपीएल में खेलने के बारे में सोचता है. एक रणजी मैच खेलने के बाद ही खिलाड़ी को आईपीएल के लिए चुन लिया जाता है. युवाओं को चाहिए कि वह जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में इसे महत्व न दें और अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करें, जिसने महान क्रिकेटर दिए हैं. युवाओं को भारतीय टीम से खेलने का सपना देखना चाहिए. पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया कहते हैं कि सबकी अपनी सोच है.

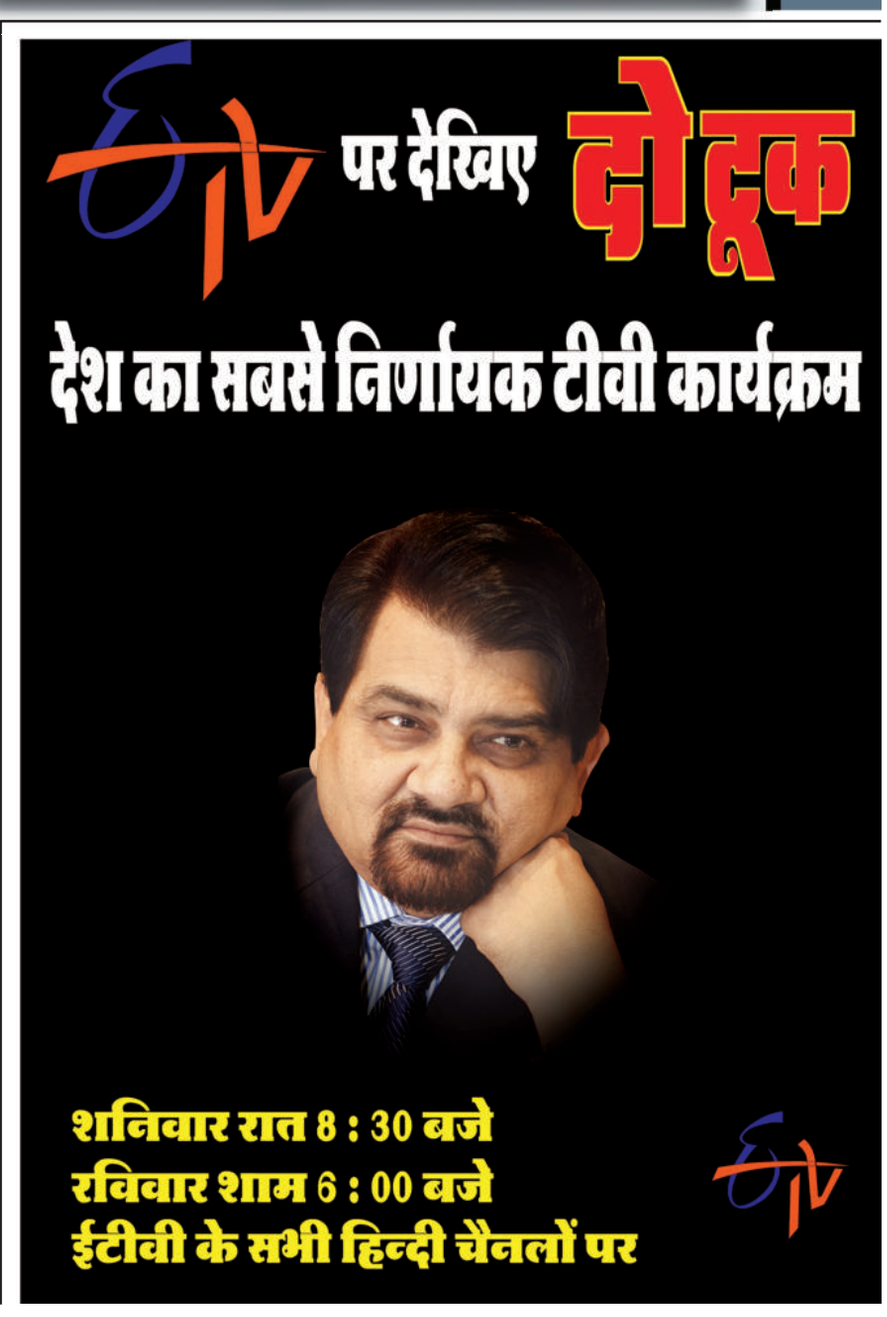

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 31 अक्टूबर-06 नवंबर 2011

फिल्म को लेकर ईशा से ज़्यादा हेमा उत्साहित हैं और फिल्म की यूएसपी भी ईशा नहीं, बल्कि उनकी मां हेमा है, जिनका जादू आज भी बरक़रार है.

ईशा से जुड़े मां के सपने

हेमा मालिनी काफी दिनों से अपनी बेटी ईशा को लेकर व्यस्त हैं, वजह है फिल्मों में उन्हें री-लांच करना. इसलिए हेमा ने ईशा के लिए फिल्म बनाई है टेल मी ओ ख़ुदा. फिल्म को लेकर ईशा से ज़्यादा हेमा उत्साहित हैं और फिल्म की यूएसपी भी ईशा नहीं, बल्कि उनकी मां हेमा है, जिनका जादू आज भी बरक़रार है. फेसबुक पर एक प्रशंसक ने लिखा कि हेमा जी आज भी अपनी बेटी ईशा से ज़्यादा जवान दिखती हैं. जितनी भीड़ उन्हें देखने के लिए लगती है, उसकी आधी भी ईशा को देखने के लिए नहीं लगती. 63वें साल में क़दम रख चुकीं हेमा मालिनी की सुंदरता के आज भी लोग प्रशंसक हैं. वह जहां भी जाती हैं, वहां लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखते हैं. ख़ैर, यह देखना दिलचस्प होगा कि हेमा जी की कोशिश और मेहनत ईशा के लिए कितनी कारगर होगी.

एक नई मां का सफ़र

जीवन में एक प्रतिष्ठित मुक़ाम हासिल करने के बाद हर औरत का नया सफर शुरू होता है मां बनकर. सेलिब्रिटिज के लिए भी ख़ास है मां बनना. पेज थ्री, खोसला का घोंसला और मस्ती जैसी फिल्मों में काम करने वाली तारा शर्मा ने कुछ दिनों बाद शादी रचा ली और उनके करियर को ब्रेक लग गया. मां बनने के बाद तो वह सिल्वर स्क्रीन से बिल्कुल ग़ायब हो गई थीं. ख़बर है कि वह जल्द ही प्रशंसकों के बीच होंगी और इसके लिए उन्होंने लिया है टेलीविज़न का सहारा. वह एक टीवी शो होस्ट कर रही हैं, जिसका नाम है द तारा शर्मा शो-एक नई मां का सफर. इस शो में वह मां बनने के बेहतरीन अनुभवों पर बात करेंगी. किसी भी सेलिब्रिटी के जीवन में इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि वह काम करते हुए अपने परिवार के साथ वक़्त बिताए. यह ख़ास मौक़ा मिला है तारा शर्मा को. मां बनने के बाद बच्चों के साथ बिताए गए पलों को समेट कर इस शो में पेश किया गया है. शो के ज़रिए आम लोगों को एक सेलिब्रिटी मॉम का जीवन क़रीब से देखने का मौक़ा मिलेगा. शो के दौरान तारा शर्मा इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ नई नवेली सेलिब्रिटी मॉम के अनुभव पर्दे पर लाएंगी, जैसे कोंकणा सेन शर्मा, मलाइका ख़ान, नंदिता दास आदि. शो के लिए तारा ने बहुत मेहनत की. शो का आइडिया आने के बाद उन्होंने ख़ुद इसकी स्क्रिप्टिंग की, ख़ुद होस्ट कर रही हैं और को-प्रोड्यूसर भी हैं. तारा अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं हैं. वह आशावादी हैं और मानती हैं कि जीवन का हर फेज कुछ न कुछ सिखाता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉरपोरेट वर्ल्ड में की, फिर रुख़ कर लिया मॉडलिंग की तरफ़ और फिर एक्ट्रेस बन गईं. लगभग 18 फिल्मों में छोटी-बड़ी भूमिकाएं निभाने वाली तारा अपने टेलीविज़न शो और आने वाली फिल्मों को लेकर काफी उत्साहित हैं. उनकी आने वाली फिल्म 10 एमएल लव शरत कटारिया द्वारा निर्देशित है. इस फिल्म में वह रजत कपूर, पूरब कोहली और टिस्का चोपड़ा के साथ नज़र आएंगी. इसके अलावा मुंबई कटिंग और अमावस भी जल्द रिलीज होने वाली हैं.

सेलिना को जुड़वा बच्चे!

अचानक शादी कर लेने की वजह से सुर्ख़ियों में आई सेलिना जेटली मां बनने वाली हैं. उन्होंने ऑस्ट्रिया में अपने ब्वॉयफ्रेंड पीटर हैग के साथ शादी कर ली थी. हैग का होटल व्यवसाय है. जब इनकी शादी की ख़बर मीडिया में आई, तब यह बात भी सामने आई कि सेलिना प्रेगनेंट हैं, लेकिन तब उन्होंने इससे इंकार करते हुए कहा था कि पीटर की दादी की अचानक तबीयत ख़राब होने के कारण उन्हें शादी करनी पड़ी. फिर ख़बर आई कि वह अप्रैल 2012 में अपने बच्चे को जन्म देंगी, लेकिन कुछ दिनों पहले फूड प्वाइजनिंग के कारण जब उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो सेलिना को ख़ुशख़बरी मिली कि वह एक नहीं, दो बच्चों की मां बनने वाली हैं. डॉक्टर ने बताया कि उनके गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं. इस वक़्त सेलिना दुबई में हैं. हम आपको बता दें कि सेलिना ने लगभग एक महीने पहले पीटर हैग से हुई अपनी शादी की ख़बर ट्विटर पर दी और सबको हैरत में डाल दिया. फिर प्रेगनेंट होने की ख़बर से वह मीडिया में छा गईं. अब एक और ख़बर आ रही है कि सेलिना प्रेगनेंट नहीं हैं और जबसे उन्हें इस अफवाह का पता चला है, वह अपसेट हो गई हैं.

हॉलीवुड से...

शिक्षा के क्षेत्र में शकीरा

कोई विख्यात शख़्स अगर समाजसेवा के क्षेत्र में उतर जाए तो उसका परिणाम सकारात्मक होना स्वाभाविक है. पॉप स्टार शकीरा ने समाजसेवा से जुड़ने की घोषणा की है. वह अब अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने शकीरा को शैक्षणिक उत्कृष्टता सलाहकार आयोग का सदस्य बनाया है. उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता एड्रियन पेज़ोजा और एरिजोना के स्कूल ज़िला अधीक्षक केंट पी स्क्रीबनर को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया है. ओबामा ने कहा, मैं आभारी हूं कि इन प्रभावशाली लोगों ने देश और जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हुए ख़ुद को इस काम के लिए समर्पित करना पसंद किया. अभी हाल में शकीरा ने संगीतकार रोजर वाटर्स के साथ मिलकर लगभग 1.6 करोड़ डॉलर में एक कैरिबियाई द्वीप ख़रीदा है. शकीरा और वाटर्स इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं. यहां वे ऐसे आरामदायक घरों का निर्माण करेंगे, ताकि लोग छुट्टियों में बेहिचक इस आईलैंड पर आ सकें. यहां समुद्र तट और होटल भी बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को विकल्प मिल सके. शकीरा हर स्तर पर अपने से जुड़ने वालों को काफी कंफर्ट महसूस कराती हैं, चाहे वह उनका निजी मामला हो या प्रोफेशनल. बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह ख़ान का कहना है कि उन्हें शकीरा के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं आती है.

बॉलीवुड सर्किट में शाहरुख

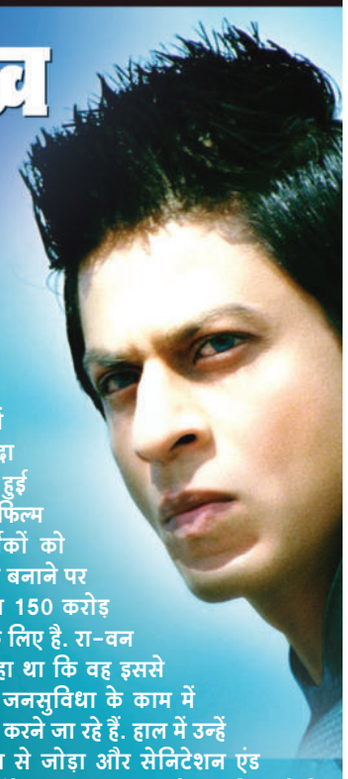

अपनी किसी भी उपलब्धि पर शाहरुख ख़ान को उतनी ख़ुशी नहीं होती, जितना दुःख इस बात का होता है कि उनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं. फैमिली वैल्यूज़ का हमेशा सम्मान करने वाले शाहरुख को इस बात का गम है कि उनके बच्चे अपनी मातृभाषा ठीक से नहीं सीख पाएंगे. उनका ख्याल है कि घर में बड़े-बुज़ुर्ग हों तो बच्चे आसानी से अपनी भाषा सीख लेते हैं और उनका चरित्र निर्माण भी बढ़िया होता है. बच्चों में अपने आप अच्छी आदतें आ जाती हैं और वे ज़्यादा सामाजिक हो जाते हैं. अभी हाल में रिलीज हुई उनकी फिल्म रा-वन बच्चों को सीख देने वाली फिल्म है. एक तरफ़ जहां बॉलीवुड में बाल दर्शकों को नज़रअंदाज कर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फिल्में बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं शाहरुख का 150 करोड़ रुपये का ड्रीम प्रोजेक्ट खासकर बच्चों के लिए है. रा-वन के प्रोमोशन के दौरान शाहरुख ने कहा था कि वह इससे मिलने वाले पैसों को महिलाओं की जनसुविधा के काम में लगाना चाहते हैं. अब वह कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं. हाल में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित अभियान से जोड़ा और सेनिटेशन एंड हाइजिन अभियान का ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. डायरिया जैसी बीमारी के कारण हर वर्ष दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं और इसकी रोकथाम का सटीक उपाय है हर घर में टॉयलेट का निर्माण. संयुक्त राष्ट्र संघ और उनका प्रयास है कि आधारभूत सफाई सुविधाओं के बग़ैर रहने वाले लोगों की संख्या 2015 तक आधी हो और डायरिया से बच्चों की रक्षा हो सके. शाहरुख का कहना है, सभी के लिए शौचालय की उपलब्धता से महिलाओं, लड़कियों और समाज के पिछड़े लोगों को काफी फ़ायदा होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

मिले ना मिले हम

काफी दिनों से ख़बर आ रही थी कि कंगना रानावत राजनेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ ज़्यादातर समय बिता रही हैं. बात यह है कि दोनों फिल्म मिले ना मिले हम में साथ काम कर रहे हैं. यह चिराग की बॉलीवुड में डेब्यू होगी. ख़बर है कि राजनेता पुत्र होने का पूरा फ़ायदा चिराग को मिल रहा है. फिल्म के प्रोड्यूसर-डायरेक्टर चिराग के नखरे ख़ूब उठा रहे हैं. फिल्म का टाइटल भी चिराग की पसंद का है. पहले इसका टाइटल वन एंड ओनली रखा गया था. प्रोड्यूसर अनुज सक्सेना ने बताया कि चिराग को पहले वाला टाइटल पसंद नहीं था, जब उन्होंने नया टाइटल सुझाया तो पूरी टीम को पसंद आया. चिराग को फिल्म में अपनी सह कलाकार कंगना का साथ भी बेहद पसंद आया. फिल्म में कंगना ने चिराग के साथ कई रोमांटिक सीन दिए हैं. कंगना का कहना है कि चिराग के साथ काम करते हुए कभी नहीं लगा कि वह न्यू कमर है. मिले ना मिले हम के संगीत लांच समारोह और दूसरे प्रोमोशनल अवसरों पर कंगना रानावत, सागरिका घटके और चिराग पासवान मौजूद थे. बॉलीवुड में आएदिन नए कलाकारों का आना लगा रहता है, लेकिन उनमें कुछ ही ऐसे होते हैं, जिन्हें मौक़ा मिलता है. फिल्म मिले ना मिले को निर्देशित किया है तनवीर ख़ान ने और सहायक निर्देशक हैं नीरज सोनी, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं. पिछले दिनों अंधेरी के फिस्टा स्टूडियो में इस फिल्म की डबिंग हुई. इस मौक़े पर रामविलास पासवान अपने बेटे का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जन्मदिन (4 नवंबर) पर विशेष

तुम जियो हजारों साल

बेमिसाल अभिनेत्री तब्बू

आम बॉलीवुड अभिनेत्रियों से अलग हैं तब्बू. उनके बारे में बहुत कम पढ़ने, देखने और सुनने को मिलता है. वह टेलीविजन पर कम आती हैं, मीडिया में इंटरव्यू भी कम देती हैं. सिल्वर स्क्रीन पर तब्बू को फिल्म तो बात पक्की में देखा गया, उसके बाद वह ख़बरों में आईं पद्मश्री मिलने पर. लोगों को शुक्रिया कहकर तब्बू जो पर्दे के पीछे गईं तो फिर नज़र नहीं आईं. स्वभाव से शांत और एकांत पसंद तब्बू की पहचान पिछले 28 सालों में हर तरह की भूमिकाएं निभाने की वजह से बन पाई. बॉलीवुड में जितने भी शेड के किरदार एक अभिनेत्री के लिए लिखे जाते हैं, तब्बू ने उन सभी किरदारों को बड़ी संजीदगी से निभाया. विजय पथ की दिलफेंक रुक-रुक गर्ल, साजन चले ससुराल में गोविंदा की दूसरी पत्नी, माचिस में सिख बग़ावत में फंसी परेशान पंजाबी लड़की से लेकर कई फिल्मों में संजीदा माशूका तक, हर किरदार उन्होंने इस तरह निभाया कि वह पर्दे पर जीवंत हो उठा. दरअसल यही तब्बू की पहचान बनाने में सहायक भी बना, क्योंकि उन्होंने उस समय इंडस्ट्री में क़दम रखा था, जब धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में थीं और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में थीं रवीना टंडन, जूही चावला और करिश्मा कपूर सरीखी अभिनेत्रियां.

उस वक्त भारतीय सिनेमा में नए प्रयोग हो रहे थे और सभी अभिनेत्रियां अपने लिए ज़मीन तलाश रही थीं, लेकिन तब्बू ने स्थिति को बख़ूबी सोचते-समझते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उनकी बहन फरहा और आंटी शबाना सिनेमा में स्थापित नाम बन चुके थे, लेकिन उनके नाम का फ़ायदा न उठाते हुए तब्बू ने म्यूज़िकल और हल्के-फुल्के मूड वाली फिल्में जैसे, पहला-पहला प्यार, विजय पथ, प्रेम, साजन की बांहों में, साजन चले ससुराल आदि कीं. तब्बू भी मीनाक्षी शेषाद्री और सोनाली बेंद्रे की तरह आई-गई हो जातीं, अगर उन्हें गुलजार की फिल्म माचिस नहीं मिलती, जिसने उन्हें पहला नेशनल अवॉर्ड दिलाया. फिर प्रियदर्शन ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी पीरियड फिल्म काला पानी में लिया. हालांकि पार्वती के रोल में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े-बड़े कलाकारों, जैसे मोहनलाल, नेडुमुडी वेनु और अमरीश पुरी के सामने खड़े होने की हिम्मत ने उन्हें ख़ूब प्रशंसा दिलाई. भारतीय सिनेमा में तब्बू के समय की शायद ही कोई अभिनेत्री होगी, जिसने अपने अभिनय के बल पर तब्बू जैसा समृद्ध और गौरवशाली इतिहास लिखा हो. तब्बू को शायद यह गुण विरासत में मिला. उनकी आंटी शबाना आजमी ऐसी ही भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, लेकिन तब्बू अपने फिल्मी सफर में शबाना जी के हस्तक्षेप से इंकार करती हैं. शबाना एक क्रिटिक की तरह हमेशा तब्बू की एक्टिंग में कोई न कोई कमी बताती रहीं, लेकिन इससे हतोत्साहित होने के बजाय उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया. दो नेशनल और पांच फिल्म फेयर अवॉर्ड ने उन्हें इंडस्ट्री की एक अलग छवि वाली अभिनेत्री बना दिया. वह ख़ुद को कभी करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ सरीखी अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा नहीं कर पाईं, लेकिन शबाना आजमी की तरह उन्होंने भी प्रतिष्ठित अदाकारा का सम्मान पाया. उनका सपना भी यही था.

चौथी दुनिया

दिल्ली, 31 अक्टूबर-06 नवंबर 2011

www.chauthiduniya.com

शिक्षातंत्र में भ्रष्टाचार

चालीस लाख फ़र्ज़ी छात्र मिले

महाराष्ट्र में अधिकांश स्कूल-महाविद्यालय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं. किसी भी निरपेक्ष सामाजिक संस्था अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए स्कूल और महाविद्यालय चलाना आसान नहीं है.

युधिष्ठिर जोशी

शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा उत्साही हैं. अपने अंतर्गत आने वाले शिक्षा मंत्रालय में कुछ भी नया करने का जज्बा रखते हैं. शिक्षा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद इस दिशा में दर्डा ने प्रयास शुरू कर दिया है. लिहाज़ा उन्होंने राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों की जांच के लिए अभियान चलाया. शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षा माफ़िया की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर चल रहा भ्रष्टाचार इस जांच-पड़ताल अभियान के परिणामस्वरूप उजागर हुआ है.

महाराष्ट्र में अधिकांश स्कूल-महाविद्यालय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं. किसी भी निरपेक्ष सामाजिक संस्था अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए स्कूल और महाविद्यालय चलाना आसान नहीं है. यदि किसी संस्था या शिक्षा विशेषज्ञ ने स्कूल शुरू करने की इच्छा प्रकट की तो उसके प्रस्ताव की फाइल मंत्रालय में धूल खाती रह जाएगी, यह तय है. वे मंत्रालय के चक्कर लगाते-लगाते थक जाएंगे, लेकिन स्कूल चलाने की अनुमति मिलना नामुमकिन है. वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसी सामान्य कार्यकर्ता ने भी स्कूल शुरू करना चाहा तो उसके प्रस्ताव को तुरंत मंज़ूरी मिल जाती है और स्कूल चलाने की अनुमति भी मिल जाती है. आज तक का यही अनुभव है कि जिस राजनीतिक दल की सत्ता रहेगी उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं को नया स्कूल चलाने की अनुमति मिलना तय ही है. इसीलिए पिछले तीस-पैंतीस सालों के स्कूली रिकॉर्ड को खंगालने पर यह सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है. इसी वजह से देखते-देखते राजनीतिक पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता शिक्षा संस्थाओं के संचालक बन गए और शिक्षा माफ़िया शिक्षा महर्षि कहलाने लगे हैं.

दरअसल मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि शिक्षण संस्थान इन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए मोटी कमाई वाली दुधारू गाय साबित हुए हैं. नए शिक्षकों की नियुक्ति करने पर उनसे मोटी रक़म वसूल की जाती है. पहले शिक्षकों के मासिक वेतन से जबरन वसूली करने की प्रथा थी. आज भी कई जगह शिक्षकों से क़िस्तों में वसूली करने की प्रथा चालू है. शिक्षकों से संस्था संचालकों द्वारा लूटमारी करने की ख़बरें जब बढ़ गईं तब सरकार की आंख खुली. इसके बाद सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों का वेतन बैंक द्वारा दिया जाने लगा. संस्था संचालकों के हाथों वेतन वितरण करने की प्रथा पर रोक लग गई. इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षक सुखी और संतुष्ट हैं. संस्था संचालक और शिक्षकों का वास्ता एक-दूसरे से दिन-रात पड़ता है. इसके परिणामस्वरूप नापसंद शिक्षकों को किसी न किसी प्रकार से संस्था संचालकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है. सभी शिक्षक अदालत में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, इस हक़ीक़त को नकारा नहीं जा सकता है. स्कूलों में छात्रों की संख्या की जांच-पड़ताल में बड़ी संख्या में बोगस विद्यार्थी मिलने का ख़ुलासा हुआ. राज्य में चले स्कूल जांच अभियान की संपूर्ण रिपोर्ट आनी फ़िलहाल बाक़ी है, परंतु अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, वे आश्चर्यचकित करने वाले हैं. मुंबई में 30,000, नागपुर में 81,000, पुणे में 1,93,735, कोल्हापुर में 1,00, 612, रायगढ़, 46,652 नांदेड़, 57,429 और जलगांव में 44,866 बोगस विद्यार्थियों के होने की बात प्रारंभिक चरण में उजागर हुई है. पुणे शहर को विद्या नगरी कहा जाता है. वहीं लगभग दो लाख बोगस विद्यार्थियों के होने की बात सामने आई है. इसी से पता चलता है कि अधिकारी और शिक्षा माफ़िया की मिलीभगत से भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक समाया हुआ है.

हक़ीक़त में देखा जाए तो वर्ष 2005-2006 में ही बोगस विद्यार्थियों के होने की बात उजागर हुई थी. उस वक़्त की जांच-पड़ताल में 12 लाख विद्यार्थियों के बोगस होने का अनुमान व्यक्त किया गया था. यदि वर्ष 2005-06 में ही इस मामले को गंभीरता से सरकार ने लिया होता और स्कूलों की जांच की गई होती तो आज जो स्कूलों में ग़ैर क़ानूनी धंधा चल रहा है, उस पर रोक लगाई जा सकती थी. सरकारी ख़ज़ाने से करोड़ों रुपयों की लूटमार भी रुक गई होती, लेकिन वर्ष 2006-2011 तक किसी भी शिक्षा मंत्री ने ऐसा साहसिक अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं समझी. इस दिशा में पिछले छह वर्षों से किसी भी मुख्यमंत्री का ध्यान इस तरफ़ नहीं जाना आश्चर्य की बात है. पिछले छह वर्षों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का लोकशाही गठबंधन सत्तारूढ़ है. सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिक्षण संस्थाएं तब भी थीं और पिछले छह सालों में कई और नई खुल गईं. ऐसे शिक्षा सम्राटों के अनुनय-विनय पर ही पिछले छह साल से बोगस छात्रों की जांच रुकी है. यदि स्कूलों में निर्धारित संख्या से छात्र कम हुए तो नियमानुसार उसको बंद करना पड़ता है. कक्षाएं बंद करनी पड़ती हैं. नई कक्षा शुरू करने की अनुमति शिक्षा विभाग से नहीं मिलती है. ज़िला परिषद के स्कूलों में हर साल शिक्षकों का तबादला होता रहता है. किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम रही तो वहां अतिरिक्त शिक्षक घोषित करना और उस अतिरिक्त शिक्षक का तबादला होने का क्रम चलता रहता है. ऐसे शिक्षकों का तबादला रोकने के लिए भी बोगस छात्रों की संख्या स्कूलों के दस्तावेज़ों में दर्शायी जाती है. ऐसा ग़ैर क़ानूनी कृत्य शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों की

(शेष पृष्ठ 18 पर)

चौथी दुनिया ने सवाल उठाया था

चौथी दुनिया ने अपने 3 से 9 अक्टूबर के अंक में शिक्षण संस्थाओं ने अनुदान लूटा शीर्षक से प्रकाशित लेख में बोगस छात्रों का मामला उठाया था, जिसमें अनुदान लूटने के अलावा बोगस छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप घोटाला, गणवेश घोटाले का ज़िक्र किया गया है. साथ ही यह भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यदि इन मामलों की जांच को लेकर संजीदा हैं तो उन्हें यह भी पता है कि इस जांच में कौन-कौन लोग बाधा डाल सकते हैं.

प.पू.सद्गुरु श्री प्रल्हाद महाराज (रामदासी)
साखरखेर्डा, जिला बुलढाना

पुण्यतिथि के पावन अवसर पर

।। शत् शत् कोटी प्रणाम।।

प्रवीण महाजन और

साप्ताहिक चौथी दुनिया परिवार

यदि कोई कागज़ी कमी रह जाती है तो संबंधित अधिकारी उसे पूरा करा लेगा, बस आपको उसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे. क़ानून-क़ायदे सब आपके पक्ष में स्वतः हो जाएंगे.

यदि सरकार अपनी विचाराधीन नीति को लागू करती है तो राज्य व देश में ग़रीबों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होने का अनुमान है.

ग़रीबों की संख्या बढ़ेगी

सरकार ग़रीबी की नई परिभाषा गढ़ रही है

एक ओर सरकार ग़रीबी को कम करने के लिए करोड़ों-अरबों रुपये का बजट हर साल बनाती है. साथ ही उनके कल्याण के लिए एक साथ कई योजनाएं संचालित की जाती हैं, ताकि उनके सामाजिक स्तर को सुधारा जा सके. देश की तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था पर धब्बे की तरह नज़र आने वाली ग़रीबी पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन अब सरकार अपनी नीति बदल रही है जिससे ग़रीबी को मापने का पैमाना भी बदल जाएगा. ग़रीबी मापने का पैमाना बदलते ही ग़रीबों की संख्या में तेज़ी से बदलाव आने की संभावना है. यदि सरकार अपनी विचाराधीन नीति को लागू करती है तो राज्य व देश में ग़रीबों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होने का अनुमान है. इसके साथ ही ग़रीबों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन आएगा. ग़ौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने 26 से 32 रुपये का ग़रीबी का आंकड़ा पेश कर सबको आश्चर्य में डाल दिया था. उसके बाद केंद्र सरकार आलोचना के घेरे में आ गई थी. इसके अलावा अब तक हर रोज़ 85 रुपये कमाने वाले परिवार को ग़रीब माना जाता था. इससे कम कमाने वाले को ग़रीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों में गिना जाता रहा है. उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा आवास योजना, रोज़गार गारंटी योजना और बीपीएल खाद्यान्न आपूर्ति योजना जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं. हालांकि अब सरकार अपनी ग़रीबी नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसके साथ ही अब चार सदस्यों के उस परिवार को जिसकी मासिक आय 10 हज़ार रुपये होगी उसे ही ग़रीब माना जाएगा. इस निर्धारण के लिए पूरे महाराष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित सर्वेक्षण किया जा रहा है. इस बात की तस्दीक राज्य के अन्न और नागरी आपूर्ति मंत्री अनिल देशमुख ने भी की है. इस बाबत पुणे में पत्रकारों से चर्चा के दौरान देशमुख ने बताया कि इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा घोषित गए 26 और 32 रुपये प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन खाद्यान्न पर किया जाने वाला ख़र्च है. केंद्र सरकार ने जो हल्फ़नामा सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल किया है उसी पर यह स्पष्टीकरण दिया गया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ग़रीबी रेखा को नए सिरे से तय करने पर विचार कर रही है. इसके तहत अब ग़रीबी रेखा के लिए दस हज़ार रुपये की आय वाले परिवार को ही ग़रीब माना जाएगा. इसके लिए सर्वेक्षण का काम भी शुरू हो चुका है. इस सर्वे में बेघर, निराधार परिवार, आदिम आदिवासी समाज और मज़दूरी करने वालों को ही ग़रीबी रेखा के नीचे समझा जाएगा. दस हज़ार से अधिक आय होने, वाहन, फोन, पक्का मकान, बाग़ीचा जैसी संपत्ति और सुविधाएं जिन परिवारों के पास हैं, उन्हें इससे अलग किया जाएगा. ऐसे में दस हज़ार से कम मासिक आय वाले लोग ही अब ग़रीबी रेखा के नीचे गिने जाएंगे. यहां सवाल यह उठता है कि 10 हज़ार रुपये की आय वाले परिवार राज्य में कितने हैं? बहरहाल इसका सटीक आंकड़ा फ़िलहाल सरकार के पास नहीं है. अगर देखा जाए तो राज्य की आबादी का अधिकांश भाग दस हज़ार रुपये से कम कमाने वाले लोगों का है. ये लोग नौकरी के लिए प्रतिदिन गांव से शहर आते हैं. गांव से शहर के बीच आपाधापी करने वाले लोगों में अधिकतर दो से दस हज़ार रुपये की नौकरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. इस लिहाज़ से देखा जाए तो राज्य में बीपीएल परिवारों संख्या को लेकर जो गोलमाल हुआ है, अब वे सारे मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे यानी बीपीएल परिवार की सूची में जो भी गड़बड़ियां थीं वे नई ग़रीबी रेखा में समाहित होकर विलुप्त हो जाएंगी. इससे संबंधित विभाग के दाग़ भी साफ़ हो जाएंगे और बीपीएल घोटाले के लिए ज़िम्मेदार लोगों को भी छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उन ग़रीबों का क्या होगा जो आज भी अति ग़रीब हैं? जिनकी मासिक आय बमुश्किल 1200-1500 रुपये हैं? लाखों परिवार आज भी 25-30 रुपये में पूरे दिन का गुज़ारा करते हैं? ऐसे परिवारों को सरकार किस वर्ग में रखेगी, क्योंकि इन्हीं लोगों को सबसे अधिक आर्थिक मदद की ज़रूरत है, लेकिन इनकी सबसे अधिक उपेक्षा शासन-प्रशासन और राजनीतिक दलों के नेता ही कर रहे हैं. वैसे सरकार ग़रीबी दूर करने के लिए योजना बनाती रही है, लेकिन इस नए परिवर्तन के साथ ही ग़रीबों की संख्या में वृद्धि होना तय माना जा रहा है. फ़िलवक़्त सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

दस हज़ारी होंगे ग़रीब

सरकार ग़रीबों की जो नई परिभाषा गढ़ रही है उसके तहत एक माह में 10 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग ग़रीब माने जाएंगे. उससे कम कमाने वाले ग़रीबी रेखा के नीचे गिने जाएंगे. केंद्र सरकार और देश का योजना आयोग ग़रीबी रेखा और ग़रीबी रेखा के नीचे वालों की सीमा तय करने में जुटा हुआ है. नई नीति के बनते ही मासिक दस हज़ार रुपये कमाने वाले भी ग़रीब हो जाएंगे. फ़िलहाल इस आय वर्ग वाले लोगों को मध्यम वर्ग में गिना जाता है.

चालीस लाख फ़र्ज़ी छात्र मिले

पृष्ठ 17 का शेष

मिलीभगत से होता है. लाखों की संख्या में बोगस छात्रों का यह फ़र्ज़ी कारोबार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सहभागिता से वर्षों से चला आ रहा है. सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रत्येक छात्र के पीछे कम से कम 100 रुपये शासन प्रतिमाह ख़र्च करता है. इस आधार 10 लाख छात्रों के पीछे 100 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. राज्य भर में बोगस छात्रों का यह आंकड़ा 40 लाख से भी अधिक होने की आशंका है. पिछले छह सालों में संस्था संचालकों ने कितने करोड़ रुपये का गोलमाल किया है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भी बड़ा हिस्सा हथियाया जाना तय माना जाता है. इसके अलावा अभी भी 10-15 प्रतिशत स्कूलों में छात्रों की गणना का काम नहीं हो सका है. इसका अर्थ यह है कि बोगस छात्रों का आंकड़ा और बढ़ सकता है. शिक्षा मंत्री ने एक ओर छात्र की संख्या की जांच के आदेश दिए, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई है. ग़ौरतलब है कि जनवरी-फरवरी में स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव पूरे राज्य में होने वाले हैं. वैसे भी आघाड़ी सरकार पहले से ही अड़चनों में है. सामान्य जनता के मन से सरकार की छवि निरंतर धूमिल हुई है. एक के बाद एक घोटाले के आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं. उसी समय राज्य में शिक्षा संचालकों, ज़िला परिषद अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की परस्पर मिलीभगत से किया गया बोगस छात्रों के घालमेल का मामला उजागर हुआ है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की नैया कैसे पार लगेगी. शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा ने छात्र संख्या जांच के लिए उचित समय चुना है. ऐसी चर्चाएं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच हो रही है. एक ख़ास बात यह हुई कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस बाबत ज़िलावार अदालत स्थापित कर भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र सुनवाई कर नतीजे तक पहुंचाने के फ़ैसला लिया गया है. इसके लिए शीघ्र गति से सुनवाई करने वाली अदालतों की स्थापना भी की जा चुकी है. अब स्कूलों में हो रही बोगस छात्र भर्ती और सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य की आघाड़ी सरकार कौन सी नई व्यवस्था पैदा करने वाली है? यह सवाल स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है.

मुख्यमंत्री के ज़िले में 126 स्कूल अनाधिकृत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के सातारा ज़िले में 126 स्कूल अनधिकृत रूप से संचालित किए जा रहे हैं. यह तथ्य राज्य में चलाए गए छात्र गणना अभियान के दौरान ज़िला परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा उजागर किया गया है. इसके अलावा 3 से 5 अक्टूबर तक चले अभियान के दौरान सातारा ज़िले के 3 हज़ार 842 स्कूलों में 27 हज़ार 70 विद्यार्थी अनुपस्थित पाए गए. मुख्यमंत्री जिस कराड तहसील के निवासी हैं, उसके येरवले गांव में स्थित ज़िला परिषद शाला क्रमांक-1 में बोगस विद्यार्थियों को बिठाने की बात भी सामने आई है. इसके लिए शाला के मुख्याध्यापक वसंतराव जाधव और शिक्षिका छबूताई यादव को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अनधिकृत रूप से संचालित 126 स्कूलों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब मुख्यमंत्री के ज़िले में हज़ारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अनधिकृत शालाएं खिलवाड़ कर सकती हैं तो राज्य के अन्य ज़िलों में शिक्षा विभाग कितना चुस्त होगा?

भयभीत मुख्याध्यापक की हार्ट अटैक से मौत

बोगस विद्यार्थियों की जांच मुहिम का डर स्कूलों के शिक्षकों में किस क़दर छाया हुआ था इसका एक उदाहरण नागपुर ज़िले के रामटेक तालुका के घोटी टोक गांव में स्थित ज़िला परिषद शाला में देखने को मिला. घोटी टोक में स्थित ज़िला परिषद शाला के मुख्याध्यापक ने एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या वास्तविक संख्या से अधिक बताई थी. इसी दौरान नांदेड़ में बोगस छात्रों के होने का मामला उजागर होने पर सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में छात्र गणना कराने की घोषणा कर दी. छात्र गणना अभियान दल के दौरों के कार्यक्रमों की घोषणा के बाद वहां के मुख्याध्यापक इतने घबरा गए कि अभियान शुरू होने के एक दिन पहले ही उनको दिल का दौरा पड़ा. उनको अपनी नौकरी ख़तरे में नज़र आई. इस चिंता में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई.

स्याही न लगाने के लिए रिश्वत

नागपुर ज़िले के रामटेक तालुका में ही टांगला गांव हैं. वहां आदिवासी बच्चों के लिए संचालित आश्रमशाला है. स्कूल के सूत्रों के अनुसार आश्रमशाला के मुख्याध्यापक ने छात्र गणना करने आए पथक के अधिकारियों को विद्यार्थियों की अंगुली पर स्याही न लगाने के लिए रिश्वत देने की पेशकश की. राज्य में ऐसे कितने स्कूलों में यह हुआ होगा, यह भी जांच का विषय है.

सीबीएसई स्कूलों से तालमेल नहीं

छात्र जांच अभियान के दौरान सीबीएसई स्कूलों से जांच में जुटे प्रशासन का कोई तालमेल नहीं था. 3 से 5 अक्टूबर के दरम्यान जब जांच अभियान चल रहा था तब सीबीएसई स्कूलों में उनके कैलेंडर के अनुसार दशहरे के उपलक्ष्य में तीन-चार दिन का अवकाश घोषित किया गया था. इन स्कूलों की कक्षाओं के छात्र उपस्थित रजिस्टर मंगाकर बाद में स्कूल में जाकर जांच की गई. इस संबंध में एक अधिकारी का कहना था कि चूंकि इस जांच अभियान में सीबीएसई स्कूलों को पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अभियान शुरू होने के एक दिन पहले सीबीएसई स्कूलों की भी जांच करने का निर्णय लिया गया. तब सप्तमी, अष्टमी, नवमी की छुट्टियां घोषित हो चुकी थीं, इसलिए बाद में कक्षाओं में जाकर जांच की गई, पर छात्रों को स्याही नहीं लगाई गई. इन छुट्टियों का फ़ायदा बोगस शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने वहां के बच्चों को अपने स्कूल का बताकर उठाया.

feedback@chauthiduniya.com

राज्य सहकारी बैंक की रिपोर्ट में ख़ुलासा

सूतगिरणी में ताला लगाने का प्रयास

महाराष्ट्र सरकार पर राज्य की शक्कर लॉबी को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है. दूसरी ओर संकट में घिरी सूतगिरणी की समस्याओं को सुलझाने के प्रति सरकार का टालमटोल का रवैया सर्वविदित है. इसकी पुष्टि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में है. [illegible]

सरकार आर्थिक मदद बंद करे

[illegible]

[illegible]

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भविष्य निधि पेंशन भोगियों की चिंता बढ़ी

भविष्य निर्वाह निधि कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा होती है. यह उनके जीवन भर की कमाई होती है. वक़्त-बेवक़्त उनकी व परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपयोगी साबित होती है. वे पेंशन के सहारे ही अपने जीवन के अंतिम दिनों को सुचारू ढंग से गुज़ारने की आशा करते हैं, लेकिन उनकी अमानत में यदि कोई ख़यानत करता है तो उस पर धोखाधड़ी का मामला बनता है. यदि यह काम कर्मचारियों की भविष्य निधि धरोहर रक्षा करने वाले विभाग में ही किया जाता हो तो चिंता होना लाज़िमी है. उल्लेखनीय है कि भविष्य निर्वाह निधि (प्रोविडेंट फंड) अधिनियम को 15 नवंबर 1995 से निजी संस्थाओं में भी सख्ती से लागू किया गया है. निजी संस्थाओं में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी भविष्य निधि अधिनियम के दायरे में लाया गया है. जिस कर्मचारी की भविष्य निधि उसके वेतन से काटी जाती है, उसमें नियोक्ता द्वारा अपना जितना हिस्सा मिलाकर भविष्य निधि कार्यालय में जमा किया जाता है, उसका 8.33 प्रतिशत हिस्सा एक स्वतंत्र पेंशन फंड में डाला जाता है. यही निधि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की वृद्धावस्था का सहारा बनती है, लेकिन अब पेंशन योजना के अनुसार देय पेंशन के निर्धारण करने में गड़बड़ी करने की आशंकाएं कुछ पेंशनभोगियों द्वारा व्यक्त की जा रही हैं. इसके चलते लोगों को कम पेंशन भुगतान करने की शिकायतें मिली हैं. सबसे अहम बात यह है कि पेंशन निर्धारण का कार्य भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है. भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा जब किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन निधि का निर्धारण किया जाता है तो उसकी नौकरी के सामान्य दस्तावेज़ों के अलावा एलिजिबल सर्विस, एक्चुअल सर्विस और पेंशनेबल सर्विस पर विशेष तौर से ग़ौर किया जाता है. एलिजिबल सर्विस का अर्थ है उक्त व्यक्ति ने जितने वर्ष नौकरी की वह अवधि. एक्चुअल सर्विस से आशय है 15 नवंबर 1995 के बाद पूरा किया गया सेवाकाल. पेंशन निर्धारण के समय पेंशनेबल सर्विस का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. इसलिए पेंशनेबल सर्विस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अधिक पेंशन की निधि निर्धारित होना तय माना जाता है. यहीं पर सबसे अधिक गड़बड़ी होती है. आशंका जताई जाती है कि भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय के अधिकारी पेंशन निर्धारण के दरम्यान पेंशनेबल सर्विस को कम करके आंकते हैं. ध्यान देने की बात यह है कि पेंशनेबल सर्विस निर्धारित करने के लिए 15 नवंबर 1995 के बाद की नौकरी (एक्चुअल सर्विस) का समय मुख्य होता है. इस अवधि में पूरे हुए वर्षों के बाद यदि छह माह का समय अधिक है तो उसे पूरा एक साल माने जाने की अपेक्षा रहती है. उदाहरण के तौर पर 20 साल 7 माह 15 दिन हुआ तो उसे 21 साल माना जाएगा. जानकारों का कहना है कि यहीं पर पेंशनेबल सर्विस के समय का निर्धारण करते समय इस नियम को लागू करने में पक्षपात किया जाता है. इस तरह का अनुभव कई पेंशनभोगियों को हुआ है. पेंशनभोगियों की शिकायत है कि अक्सर साल छह-सात माह की अवधि के वक़्त को एक साल मानने की बजाय उसको कम करके पेंशनेबल सर्विस के समय को आंका जाता है. इस अवधि के कम होने से पेंशन निधि के निर्धारण में भी फ़र्क़ पड़ता है. मझगांव डाक्स में एक कंपनी से सेवानिवृत हुए क्लाइव माइकल रोजारिओ और गोपाल महादेव जोग का मामला इसका उदाहरण बनकर सामने आया है. रोजारिओ की उक्त कंपनी में एक्चुअल सर्विस 15 नवंबर 1995 के पश्चात 9 साल 10 माह 10 दिन हुई थी. पेंशन निर्धारण के दौरान उसकी पेंशनेबल सर्विस पूरी दस साल मानी गई. वहीं गोपाल महादेव जोग की एक्चुअल सर्विस 14 साल 7 महीने 16 दिन की थी, लेकिन गोपाल जोग के पेंशनेबल सर्विस को मात्र 14 साल माना गया. गोपाल के पेंशनेबल सर्विस के निर्धारण में भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय के अधिकारियों ने सात माह 16 दिन का हिसाब नहीं जोड़ा, जिसके कारण उनकी पेंशन निधि भी कम तय की गई. इनमें से रोजारिओ का मामला मुंबई के वासी स्थित भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय का है, जबकि गोपाल महादेव जोग का प्रकरण बांदा के पी.एफ. ऑफिस का है. इसका मतलब यह है कि हर भविष्य निधि कार्यालय में अलग-अलग फार्मूले के आधार पर पेंशन निर्धारण का कार्य वहां के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, लेकिन इससे हुआ नुक़सान सेवानिवृत कर्मचारियों को कम पेंशन निधि के रूप में भोगना पड़ता है. ऐसे मामलों में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

अपराधियों की राजधानी

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जहां माफ़िया संगठनों का केंद्र है, वहीं उप राजधानी में अपहरण का नया कारोबार शुरू हो गया है, जबकि पुलिस का दावा है कि यहां आपराधिक घटनाओं में कमी आई है. वहीं उनके दावे के विपरीत नागपुर में हत्या, अपहरण और लूट की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. इसीलिए आजकल मीडिया में उप राजधानी को अपराधियों की राजधानी पुकारा जाने लगा है. नागपुर शहर को भी अपहरण का रोग लग गया है. यहां बच्चे सुरक्षित नहीं हैं. लोगों के लिए पैसा भगवान हो गया है. बड़े-बुज़ुर्गों का कहना है कि बच्चों के मन में भगवान बसता है. इसलिए बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है. अब समाज कंटक भगवान रूपी बच्चों का अपहरण कर अपनी धन प्राप्ति की लिप्सा पूरी करने में लगे हैं. उनको श्रेष्ठियों (श्रीमंतों) के बच्चे मोटी रक़म जुगाड़ने का आसान तरीक़ा लगते हैं. इसकी वजह है बच्चों का सरल मन जो प्यार से बात करने वाले हर व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है. अपहरणकर्ता उन्हें बहला-फुसलाकर या किसी चीज़ का लालच देकर आसानी से अपने साथ ले जाने में कामयाब होते हैं, लेकिन अपहरणकर्ताओं से निपटने में उप राजधानी की पुलिस नाकाम साबित हुई है. ज्ञात हो कि 29 मई 2000 के दिन शहर के जाने-माने सर्राफा व्यवसायी नीलेश पारेख के बेटे आदित्य उर्फ़ आदिश पारेख का अपहरण किया गया था. उसकी खोजबीन नागपुर की पुलिस आज तक नहीं कर पाई है. उसी तरह सितंबर 2000 में हरेकृष्ण ठकराल, अक्टूबर 2000 में प्राची हारोडे, मार्च 2008 में पार्थ कैकाडे, जनवरी 2010 में मिथिलेश हिरवाणी, जून 2010 में बालाजी तलवेलकर के अपहरण की घटनाएं हो चुकी हैं. इस वर्ष 11 अक्टूबर को सुरुचि मसाला कंपनी के संचालक प्रशांत कटारिया के पुत्र कुश का अपहरण कर लिया गया, जिसकी अपहरणकर्ता ने हत्या भी कर दी और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. कोई व्यक्ति अपने शौक़ पूरे करने के लिए किसी बच्चे की निर्ममता से हत्या करेगा, यह सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहां अपहरणकर्ता आयुष पुगलिया ने अपने सट्टा, हुक्का पार्लर, स्नूकर पूल और शराब-शबाब के शौक़ पूरे करने के लिए पैसों का जुगाड़ करने हेतु मासूम कुश का अपहरण कर लिया. नराधम आयुष को लगा कि करोड़ों का व्यवसाय करने वाले कुश के पिता उसकी दो करोड़ की मांग पूरी कर देंगे, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, लिहाज़ा उसने उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी. पुलिस इस प्रकरण में पहले तो अंधेरे में हाथ-पांव मारती रही. संदेह होने पर भी उसने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया. कुश के साथ के दो बच्चों और चौकीदार की पत्नी ने घरवालों को बताया था कि कुश आयुष के साथ गया है. कुश के परिजनों ने यह बात पुलिस को भी बताई थी. इसके बाद भी पुलिस ने आयुष को पकड़कर उससे पूछताछ क्यों नहीं की? क्या आयुष का पुराना रिकॉर्ड पुलिस की डायरी में दर्ज था या नहीं? आयुष पहले भी चोरी आदि मामलों संलिप्त था. क्या पुलिस आयुष के ख़िलाफ़ धीमी गति से कार्रवाई इसलिए करती रही, क्योंकि पुलिस वालों से उसके क़रीबी संबंध थे. वहीं दूसरी ओर प्रशांत कटारिया के दो ड्राइवरों पर पुलिस ने अपनी ताक़त आज़माई. अगर उसी तरह आयुष से पूछताछ की गई होती तो शायद कुश को बचाया जा सकता था. राज्य के गृहमंत्री आर. आर. पाटिल साहब तो मुंबई में बैठे बयानबाज़ी करते रहते हैं और उनके मातहत आने वाला पुलिस महकमा अपनी सुस्त चाल से चलता नज़र आता है. राज्य में सबकुछ राम भरोसे ही चल रहा है. इसलिए नागपुर की पुलिस कुश अपहरण मामले में टालमटोल का रवैया अपनाए रही. उप राजधानी के पुलिस कमिशनर अंकुश धनविजय आख़िर आपके राज में ये हो क्या रहा है? आपका महकमा क्या कर रहा है? क्यों अपराधी इतने चुस्त हैं और पुलिस सुस्त बनी हुई है. आपके अधिकारियों से जब घटनाओं के विषय में पूछा जाता है तो रटा-रटाया जवाब मिलता है. इसलिए धनविजय साहब कुछ कीजिए और पुराने ढर्रे को बदलने का प्रयास करिए. वैसे भी आपको लोग राजनीतिक पुलिस आयुक्त कहने लगे हैं. यह आपकी व आपके महकमे के लिए अच्छी बात नहीं होगी. कुछ तो बदलाव आपके राजकाज में आना ही चाहिए. आपका नागपुर कार्यकाल अपराधियों और अपराधों के लिए जाना जाए ऐसा तो नहीं चाहेंगे आप. इसलिए अपने पुलिस महकमे को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कुछ तो ठोस क़दम उठाइये. उप राजधानी को अपराधियों की राजधानी बनने से रोकिए. ऐसा न हो कि उप राजधानी में बढ़ रहे अपराध आपके पुलिस करियर में ग्रहण साबित हो जाए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नौकरशाहों ने दुकान लगाई

पैसा दो, स्कूल लो

किसी ने सच कहा है कि आजकल सबकुछ बिकता है, बस ख़रीदने वाला कोई होना चाहिए. महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है. बस आपकी पहुंच मंत्री के पीए, सचिव और उपसचिव या मंत्रालय के किसी अफ़सर तक होना ज़रूरी है. आप अपनी अंटी से नोटों की गड्डियां निकालिए और संबंधित अफ़सर के हाथ में दीजिए, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी. हाल में शिक्षा मंत्री के पीए को रंगेहाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किए जाने के बाद से ऐसा ही लगता है. यदि आपकी ऊपर तक पहुंच है और संबंधित अधिकारियों की डिमांड के अनुसार लाखों रुपये ख़र्च करने की क्षमता रखते हैं तो राज्य में कहीं भी स्कूल या कॉलेज खोलने की मान्यता बड़ी आसानी से मिल सकती है. यदि कोई काग़ज़ी कमी रह जाती है तो संबंधित अधिकारी उसे पूरा करा लेगा, बस आपको उसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे. क़ानून-क़ायदे सब आपके पक्ष में स्वतः हो जाएंगे. यदि आप पैसे ख़र्च नहीं कर सकते हैं तो आपका मामला चाहे कितना ही सही हो आपके काग़ज़ात पूरे हों पर बिना चढ़ावे के काम होने वाला नहीं है. चाहे आप दफ़्तरों के चक्कर लगाते क्यों न रहें. इस काम के लिए आप से मिलने वाला पैसा पीए से होते हुए अपर सचिव, सचिव से होते हुए मंत्री तक पहुंचता है. पैसे दिए बिना आपकी फाइल आगे बढ़ने वाली नहीं है. अब आप कहीं मत जाओ, हमें ढाई लाख दो और आपकी संस्था को कक्षा आठवीं से बारहवीं तक मान्यता मिलने का आदेश साथ लेकर जाओ.. उक्त शब्द हैं राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री के स्वीप सहायक दीपक कारंडे और इस विभाग के सहायक प्रशांत अंधारे के, जिन्होंने पैसे मांगते हुए ये बातें कही थीं. नासिक में इसका ख़ुलासा किया है सटाना तहसील के ताहाराबाद स्थित सिद्धी इंग्लिश मीडियम स्कूल के संचालक डॉ. प्रसाद सोनवणे ने. उनके इस साहसिक क़दम से रिश्वतख़ोर दीपक कारंडे व विभागीय सहायक प्रशांत अंधारे और लिपिक प्रवीण बोडके को भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. इन तीनों की गिरफ्तारी से यह बात साफ़ हो जाती है कि भ्रष्टाचारियों की मंडली किस तरह राज्य के हर मंत्रालय में सक्रिय है. इनके कारण ही राज्य में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और शिक्षण संस्थान एक व्यावसायिक केंद्र बनकर रह गए हैं. इस कड़वी सच्चाई को सरकार नहीं झुठला सकती है. मंत्रालयों में बैठा हर अधिकारी पावर के दम पर अधिक से अधिक पैसा बनाने की जुगत में लगा रहता है. नतीजतन, भ्रष्टाचार अपना मुंह फैलाता जा रहा है. डॉ. सोनवणे ने कहा कि इन भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ क़दम उठाने की प्रेरणा मुझे अन्ना हजारे से मिली. मैंने जब ताहाराबाद गांव स्थित सिद्धी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आठवीं से 12वीं तक कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव मंत्री के पास भेजना चाहा तो शालेय शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा के स्वीप सहायक (पीए) ने उन तक प्रस्ताव को पहुंचाने के लिए 50 हज़ार रुपये की मांग सबसे पहले की. उसके बाद इस विभाग के सहायक प्रशांत अंधारे व लिपिक प्रवीण बोडके ने अपनी अलग से मांग की. तभी मैंने यह सोच लिया था कि मेरा स्कूल बंद होता है तो हो जाए पर इन भ्रष्टों को सबक़ सिखाकर रहूंगा. उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि 9 वर्ष पहले जब कक्षा पहली से कक्षा सातवीं तक बिना अनुदानित स्कूल की मान्यता ली थी तब ऐसा कटु अनुभव नहीं हुआ था. इसके उलट तत्कालीन शिक्षा मंत्री अमरीश भाई पटेल ने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल शुरू करने के लिए स्वागत किया था. पिछले साल सरकार ने बिना अनुदानित स्कूलों में आठवीं से 12वीं तक कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया था. सरकार के उक्त निर्णय को मद्देनज़र रखते हुए मार्च 2011 में अपने स्कूल में 8वीं से 12वीं तक कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव शासन-प्रशासन के पास भेजा था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई. इस पर पूछताछ करने पर पता चला कि शिक्षण विभाग को भेजे प्रस्ताव की फाइल ग़ायब हो गई है. कई बार के प्रयासों के बाद फाइल खोजी गई. फाइल मिलने पर प्रस्ताव में कई त्रुटियां बताई गईं. उन त्रुटियों का दूर कर जब दोबारा फाइल पेश की गई तो कुछ दिनों पता चला कि वह पुनः ग़ायब हो गई है. बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी फाइल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई. इस पर जब पूछताछ करने शिक्षा मंत्रालय पहुंचा तब पता चला कि फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 50 हज़ार रुपये लगते हैं. एडवांस में 15 हज़ार रुपये देने पर तुरंत फाइल सामने आ गई. जब फाइल दीपक कारंडे के पास पहुंची तो उसने कहा कि अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ ढाई लाख रुपये देकर मान्यता मिलने का आदेश ले जाओ. काफ़ी सौदेबाज़ी करने के बाद 90 हज़ार रुपये में यह मामला तय हुआ था. इसके लिए 50 हज़ार रुपये काम के पहले और 40 हज़ार रुपये काम होने के बाद देने की बात दीपक करांडे ने कही थी. डॉ. सोनवणे ने बताया कि भ्रष्टाचार का यह रूप देखने के बाद मान्यता प्राप्त करने के लिए पैसे देने की मेरी इच्छा ज़रा भी नहीं थी. अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दरम्यान मैंने ताहाराबाद में भी आंदोलन के समर्थन में एक रैली निकाली थी. इसलिए किसी तरह के कार्य के लिए रिश्वत देना उचित नहीं लगा. अंततः भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते के ऑफिस में जाकर शिकायत कर दी. इस घटनाक्रम से मंत्रालयों-सचिवालय में मौजूद भ्रष्टाचार का पता चलता है कि शिक्षा माफ़िया किसके दम पर पूरे राज्य में अपना व्यवसाय फैलाते जा रहे हैं. क्या यही प्रगतिशील महाराष्ट्र का असली चेहरा है? यहां आम आदमी का जीना मश्किल हो रहा है. रिश्वतख़ोर किसी को नहीं बख़्श रहे हैं. हर कोई भ्रष्टाचार से हलकान है और जिनकी नाक के नीचे यह गोरखधंधा चल रहा है वे अपने को पाक-साफ़ बताते हैं. नागपुर के एक राजनेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जब अपनी सरकार के रहते हमें ही जूनियर कॉलेज के लिए पांच लाख रुपये देने पड़े तो डॉ. सोनवणे तो मात्र एक सामाजिक आदमी हैं. बिना दिए राजनीतिक लोगों का काम भी नहीं होता है. इसलिए बोगस विद्यार्थियों के नाम पर अनुदान की रक़म हड़पने जैसे भ्रष्टाचार होते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

अधिकारियों की लापरवाही से बिजली संकट गहराया

राजेश नामदेव

महाराष्ट्र बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. हालत यह है कि एक घंटे की लोडशेडिंग पिछले डेढ़ हफ्ते के दौरान 7-12 घंटे में बदल गई है. ग्रामीण इलाक़ों में तो 16 घंटे तक लोडशेडिंग की जाने लगी है. इसके बावजूद राज्य सरकार जनता की इस परेशानी से बेफ़िक्र नज़र आ रही है. यही वजह है कि बिजली संकट की गंभीर समस्या की उन्हें कोई सुध नहीं है. उनकी आंख तब खुली जब बढ़ते अंधकार से गुस्साई जनता ने बिजली विभाग के दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और सड़कों को जाम कर दिया. तब कहीं जाकर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ने हड़बड़ाहट में राजनीतिक बयानबाजी शरू कर दी. दोनों ने इस संकट के लिए पृथक तेलंगाना आंदोलन और उड़ीसा में आई बाढ़ को ज़िम्मेदार ठहराया. वहीं स्थिति बिगड़ती देख उपमुख्यमंत्री केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष अतिरिक्त बिजली आपूर्ति करने की गुहार लगाने दिल्ली भागे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आपा-धापी में बैठक बुलाकर समस्या पर विचार-विमर्श करना शुरू किया, लेकिन जब तक समस्या ने गंभीर रूप धारण नहीं कर लिया तब तक सरकार ने उसके संबंध में कोई योजना बनाने की तैयारी नहीं की थी.

ग़ौरतलब है कि तेलंगाना आंदोलन नवरात्रोत्सव से पहले शुरू था और उसके उग्र होने की आशंका भी थी. इसका स्वाभाविक रूप से असर यातायात संसाधन में पड़ना ही था. ऐसी अवस्था में सरकार को आने वाले संकट से निपटने के लिए उपाय किए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार पहले समस्या को नज़रअंदाज़ करती रही. सरकार यदि समस्या के प्रति गंभीर होती तो तेलंगाना आंदोलन से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस क़दम उठाती. आज स्थिति यह है कि राज्य में बिजली की मांग जहां 16,000 मेगावाट है, वहीं राज्य में कुल उत्पादित बिजली महज़ 11,000 मेगावाट ही है. मतलब मांग और पूर्ति के मध्य 5000 मेगावाट का अंतर है. इस अंतर को सरकार द्वारा भरने के प्रयास अब तक नाकाफ़ी ही साबित हुए हैं. निजी कंपनियों से बिजली ख़रीदने के बाद भी सरकार जनता को बिजली कटौती से राहत नहीं दे पा रही है, बल्कि संकट और गहराता जा रहा है. इसकी वजह यह है कि तेलंगाना आंदोलन के जल्द ख़त्म होने के कोई आसार नहीं हैं. ऐसे में प्रदेश की जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अफ़सोस इस बात का है कि प्रदेश में बिजली की क़िल्लत दूर करने की बजाय राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में जुट गए हैं.

वहीं लोडशेडिंग के क़हर से जनाक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा है. किसान बेहाल हैं, कल-कारख़ानों में काम की गति को विराम लग गया है. त्योहारों के इस मौसम में व्यवसायियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है. इन हालात में बिजली महावितरण कंपनी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. औद्योगिक इकाइयों व खेतों को भी सप्ताह में 16 घंटे की लोडशेडिंग (स्टैगरिंग डे) का सामना करना पड़ रहा है. महावितरण कंपनी इस बिजली संकट में जिंदल पावर से 300 मेगावाट, रिलायंस इंफ्रा से 220 मेगावाट, ग्लोबल से 110 मेगावाट, इंद्रजीत से 24 मेगावाट और वर्धा से 100 मेगावाट की ख़रीद कर रही है. इसके अलावा जिंदल पावर से लांग टर्म पर 300 मेगावाट बिजली अलग से ख़रीदी जा रही है, लेकिन इन कंपनियों से ख़रीदी जा रही बिजली वर्तमान संकट के समक्ष ऊंट के मुंह में ज़ीरा साबित हो रही है. दूसरी ओर महाजेनको ताप बिजली केंद्रों का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है जो आने वाले दिनों में गंभीर संकट के संकेत दे रहे हैं. विदर्भ स्थित कोराड़ी बिजली उत्पादन केंद्र की दो यूनिटें बंद होने से मात्र 170 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, जबकि उसकी कुल उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है. इसी तरह चंद्रपुर केंद्र की उत्पादन क्षमता 2223 मेगावाट है, लेकिन यहां 1789 मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही है. अन्य ताप बिजली केंद्रों की हालत भी ख़स्ता है. तेलंगाना आंदोलन यदि लंबा खिंचा तो बिजली उत्पादन में और अधिक गिरावट आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. इस बीच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार दिल्ली जाकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे से अनुनय-विनय कर 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का जुगाड़ करने में कामयाब रहे. फिर भी अक्टूबर माह में बिजली की आंखमिचौनी से जनता को राहत नहीं मिली. मुख्यमंत्री ने जहां इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या बताकर अपना दामन बचाना चाहा, वहीं दूसरी ओर राज्य की जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इसे प्रदेश के हर शहर में धरना-सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहे हैं.

हालांकि, इस गंभीर बिजली संकट को लेकर सतही राजनीति करने में नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी. भाजपा ने बिजली कटौती के ख़िलाफ़ राज्य सरकार के विरोध में धरना-प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया. वहीं शिवसेना, आरपीआई और मनसे ने भी चव्हाण सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. चौतरफ़ा विरोध का सामना कर रही सरकार में उप मुख्यमंत्री आनन-फ़ानन में दिल्ली से 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का जुगाड़ कर लौटे अजित पवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेसी मंत्रियों ने निशाना बनाया. उद्योग मंत्री नारायण राणे सहित कई कांग्रेसी मंत्रियों ने अजीत पवार की कार्यशैली और बिजली संकट से निपटने की उनकी ढिलाई पर सवाल खड़े किए. साथ ही मुख्यमंत्री से कोई रास्ता निकालने का अनुरोध किया. कांग्रेसी मंत्रियों के इस विरोध का गृहमंत्री आर.आर. पाटिल व अन्य राकांपा नेताओं ने विरोध किया. इतना सब कुछ होने के बाद भी राज्य का कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति यह बताने को तैयार नहीं था कि जनता को बिजली संकट से कब छुटकारा मिलेगा? बनावटी बिजली संकट सरकारी रुख़ और महावितरण कंपनी के अधिकारियों के बयानों में काफ़ी अंतर होने से बिजली संकट को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति बन रही है. आख़िर वह किसकी बात पर विश्वास करे? एक ओर सरकार राज्य में बिजली संकट के लिए तेलंगाना आंदोलन और उड़ीसा में बाढ़ को ज़िम्मेदार बता रही थी. दूसरी ओर महावितरण के आला अधिकारियों का कहना था कि मांग और उत्पादन में बढ़ते अंतर के कारण बिजली संकट पैदा हुआ.

लिहाज़ा उनके पास लोडशेडिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. ख़ास बात यह थी कि राज्य में 26 सितंबर तक बिजली संकट के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे थे. सब कुछ ठीक चल रहा था. 26 सितंबर को महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग ने महावितरण कंपनी की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें उसने महंगी बिजली निजी कंपनियों से ख़रीदने के लिए बिजली के दाम में प्रति यूनिट 61 पैसे की वृद्धि करने की मांग की है. उसके दूसरे दिन यानी 27 सितंबर से राज्य में बिजली कटौती का क़हर टूट पड़ा. एक सप्ताह में बिजली संकट इतना विकराल हो गया कि शहरों में 4 से 7 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 12 से 16 घंटे लोडशेडिंग की जाने लगी. लोडशेडिंग के क़हर के लिए सरकार ने तेलंगाना आंदोलन और उड़ीसा में आई बाढ़ के कारण कोयले की आपूर्ति बाधित होना बताया.

दूसरी ओर यह भी पता चला है कि बिजली उत्पादक कंपनी महानेनको के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है. बिजली कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि राज्य में जारी लोडशेडिंग महावितरण की महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग पर दबाव बनाने की रणनीतिक चाल है, ताकि उसकी बिजली में क़ीमत वृद्धि याचिका को मंज़ूर कर लिया जाए. स्वयं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस बाबत दिल्ली जाने से पहले पत्रकारों से बिजली संकट पर चर्चा के दौरान बिजली दर में वृद्धि की मांग को जायज़ ठहराया और कहा कि यदि उपभोक्ताओं को बिजली चाहिए तो उसकी क़ीमत चुकानी होगी. यदि राज्य नियामक आयोग ने महावितरण की मूल्य वृद्धि की मांग को मंज़ूरी दे देती है तो राज्य में बिजली बिल में तक़रीबन 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली का ऐसा संकट कहीं नहीं देखा गया. आंध्रप्रदेश (जहां तेलंगाना आंदोलन चल रहा है) वहीं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में तो इतना बिजली संकट भी नहीं है फिर अचानक महाराष्ट्र में बिजली संकट क्यों हैं? कहीं यह संकट बनावटी तो नहीं है?

महावितरण ने ग्रिड से चोरी की

महाराष्ट्र बिजली संकट से निपटने के लिए अब महावितरण के अधिकारी बिजली की चोरी भी करने लगे हैं. यह चोरी मंत्रालय से लेकर महावितरण के आला अधिकारियों की सर्वसम्मति से किए जाते हैं. वैसे यह बिजली चोरी जनहित में की गई, लेकिन चोरी तो आख़िर चोरी है. इसीलिए 5 से 10 अक्टूबर तक महाराष्ट्र पर बिजली चोरी के लिए 3 करोड़ 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. जिन अधिकारियों ने बिजली चोरी की है अगर उनके ख़िलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उन्हें सज़ा भी हो सकती है. चूंकि अधिकारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज नहीं किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि यह चोरी सर्वसम्मति से की गई है. अब सवाल यह उठता है कि राज्य की जनता की सहूलियत के लिए की गई चोरी हेतु ज़िम्मेदार अधिकारियों का सत्कार किया जाए या उनको दंडित?

feedback@chauthiduniya.com

लोडशेडिंग के कहर से जनाक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा है. किसान बेहाल हैं, कल-कारख़ानों में काम की गति को विराम लग गया है. त्योहारों के इस मौसम में व्यवसायियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है. इन हालात में बिजली महावितरण कंपनी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. औद्योगिक इकाइयों व खेतों को भी सप्ताह में 16 घंटे की लोडशेडिंग (स्टैगरिंग डे) का सामना करना पड़ रहा है.

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार
महाराष्ट्र

सदस्यता फार्म (वार्षिक)

सदस्यता शुल्क- २५० /- रुपये
मैं "चौथी दुनिया" साप्ताहिक समाचार पत्र का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ।
मेरा नाम श्री./ श्रीमती .....
मेरा पता .....
जिला.....राज्य .....पिन कोड.....
फोन (आ).....(का).....मोबाईल.....
ई -मेल.....
मैं रु. वार्षिक सदस्यता के लिए चेक क्रमांक.....
दिनांक .....बैंक.....शाखा..... द्वारा भेज रहा/ रही हूँ

नोट- यह सदस्यता शुल्क भारत में ही मान्य है तथा यह योजना सीमित अवधि के लिए है। समाचार पत्र केवल साधारण डाक द्वारा भेजा जाएगा।

सदस्यता शुल्क केवल चेक द्वारा आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि. नागपुर के पक्ष में सदस्यता फार्म के साथ निम्नलिखित पते पर प्रषित करे या फिर हमारे प्रतिनिधी को फार्म कलेक्ट करने के लिए फोन पर सूचित करे.

कार्यालय
"चौथी दुनिया"- महाराष्ट्र,
आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.,
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने,होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड,सीताबर्डी, नागपुर.
फोन नं.- 0712-2544988, 2549846
Email: chauthiduniyaa@gmail.com

पाठक ध्यान दें
जिन पाठको कों चौथी दुनिया की वार्षिक सदस्यता चाहिए वे फार्म भरकर भेजें या कार्यालय में संपर्क करें.

Postal Regn. No.RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 31 अक्टूबर–06 नवंबर 2011

फिल्म को लेकर ईशा से ज़्यादा हेमा उत्साहित हैं और फिल्म की यूएसपी भी ईशा नहीं, बल्कि उनकी मां हेमा है, जिनका जादू आज भी बरक़रार है.

ईशा से जुड़े मां के सपने

हेमा मालिनी काफी दिनों से अपनी बेटी ईशा को लेकर व्यस्त हैं, वजह है फिल्मों में उन्हें री–लांच करना. इसलिए हेमा ने ईशा के लिए फिल्म बनाई है टेल मी ओ ख़ुदा. फिल्म को लेकर ईशा से ज़्यादा हेमा उत्साहित हैं और फिल्म की यूएसपी भी ईशा नहीं, बल्कि उनकी मां हेमा है, जिनका जादू आज भी बरक़रार है. फेसबुक पर एक प्रशंसक ने लिखा कि हेमा जी आज भी अपनी बेटी ईशा से ज़्यादा जवान दिखती हैं. जितनी भीड़ उन्हें देखने के लिए लगती है, उसकी आधी भी ईशा को देखने के लिए नहीं लगती. 63वें साल में क़दम रख चुकीं हेमा मालिनी की सुंदरता के आज भी लोग प्रशंसक हैं. वह जहां भी जाती हैं, वहां लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखते हैं. ख़ैर, यह देखना दिलचस्प होगा कि हेमा जी की कोशिश और मेहनत ईशा के लिए कितनी कारगर होगी.

एक नई मां का सफ़र

जीवन में एक प्रतिष्ठित मुक़ाम हासिल करने के बाद हर औरत का नया सफर शुरू होता है मां बनकर. सेलिब्रिटिज के लिए भी ख़ास है मां बनना. पेज थ्री, खोसला का घोंसला और मस्ती जैसी फिल्मों में काम करने वाली तारा शर्मा ने कुछ दिनों बाद शादी रचा ली और उनके करियर को ब्रेक लग गया. मां बनने के बाद तो वह सिल्वर स्क्रीन से बिल्कुल ग़ायब हो गई थीं. ख़बर है कि वह जल्द ही प्रशंसकों के बीच होंगी और इसके लिए उन्होंने लिया है टेलीविज़न का सहारा. वह एक टीवी शो होस्ट कर रही हैं, जिसका नाम है द तारा शर्मा शो–एक नई मां का सफर. इस शो में वह मां बनने के बेहतरीन अनुभवों पर बात करेंगी. किसी भी सेलिब्रिटी के जीवन में इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि वह काम करते हुए अपने परिवार के साथ वक़्त बिताए. यह ख़ास मौक़ा मिला है तारा शर्मा को. मां बनने के बाद बच्चों के साथ बिताए गए पलों को समेट कर इस शो में पेश किया गया है. शो के ज़रिए आम लोगों को एक सेलिब्रिटी मॉम का जीवन क़रीब से देखने का मौक़ा मिलेगा. शो के दौरान तारा शर्मा इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ नई नवेली सेलिब्रिटी मॉम के अनुभव पर्दे पर लाएंगी, जैसे कोंकणा सेन शर्मा, मलाइका ख़ान, नंदिता दास आदि. शो के लिए तारा ने बहुत मेहनत की. शो का आइडिया आने के बाद उन्होंने ख़ुद इसकी स्क्रिप्टिंग की, ख़ुद होस्ट कर रही हैं और को–प्रोड्यूसर भी हैं. तारा अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं हैं. वह आशावादी हैं और मानती हैं कि जीवन का हर फेज कुछ न कुछ सिखाता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉरपोरेट वर्ल्ड में की, फिर रुख़ कर लिया मॉडलिंग की तरफ़ और फिर एक्ट्रेस बन गईं. लगभग 18 फिल्मों में छोटी–बड़ी भूमिकाएं निभाने वाली तारा अपने टेलीविज़न शो और आने वाली फिल्मों को लेकर काफी उत्साहित हैं. उनकी आने वाली फिल्म 10 एमएल लव शरत कटारिया द्वारा निर्देशित है. इस फिल्म में वह रजत कपूर, पूरब कोहली और टिस्का चोपड़ा के साथ नज़र आएंगी. इसके अलावा मुंबई कटिंग और अमावस भी जल्द रिलीज होने वाली हैं.

सेलिना को जुड़वा बच्चे!

अचानक शादी कर लेने की वजह से सुर्ख़ियों में आई सेलिना जेटली मां बनने वाली हैं. उन्होंने ऑस्ट्रिया में अपने ब्वॉयफ्रेंड पीटर हैग के साथ शादी कर ली थी. हैग का होटल व्यवसाय है. जब इनकी शादी की ख़बर मीडिया में आई, तब यह बात भी सामने आई कि सेलिना प्रेगनेंट हैं, लेकिन तब उन्होंने इससे इंकार करते हुए कहा था कि पीटर की दादी की अचानक तबीयत ख़राब होने के कारण उन्हें शादी करनी पड़ी. फिर ख़बर आई कि वह अप्रैल 2012 में अपने बच्चे को जन्म देंगी, लेकिन कुछ दिनों पहले फूड प्वाइजनिंग के कारण जब उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो सेलिना को ख़ुशख़बरी मिली कि वह एक नहीं, दो बच्चों की मां बनने वाली हैं. डॉक्टर ने बताया कि उनके गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं. इस वक़्त सेलिना दुबई में हैं. हम आपको बता दें कि सेलिना ने लगभग एक महीने पहले पीटर हैग से हुई अपनी शादी की ख़बर ट्विटर पर दी और सबको हैरत में डाल दिया. फिर प्रेगनेंट होने की ख़बर से वह मीडिया में छा गईं. अब एक और ख़बर आ रही है कि सेलिना प्रेगनेंट नहीं हैं और जबसे उन्हें इस अफवाह का पता चला है, वह अपसेट हो गई हैं.

हॉलीवुड से...

शिक्षा के क्षेत्र में शकीरा

कोई विख्यात शख़्स अगर समाजसेवा के क्षेत्र में उतर जाए तो उसका परिणाम सकारात्मक होना स्वाभाविक है. पॉप स्टार शकीरा ने समाजसेवा से जुड़ने की घोषणा की है. वह अब अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने शकीरा को शैक्षणिक उत्कृष्टता सलाहकार आयोग का सदस्य बनाया है. उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता एड्रियन पेज़ोजा और एरिजोना के स्कूल ज़िला अधीक्षक केंट पी स्क्रीबनर को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया है. ओबामा ने कहा, मैं आभारी हूं कि इन प्रभावशाली लोगों ने देश और जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हुए ख़ुद को इस काम के लिए समर्पित करना पसंद किया. अभी हाल में शकीरा ने संगीतकार रोजर वाटर्स के साथ मिलकर लगभग 1.6 करोड़ डॉलर में एक कैरिबियाई द्वीप ख़रीदा है. शकीरा और वाटर्स इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं. यहां वे ऐसे आरामदायक घरों का निर्माण करेंगे, ताकि लोग छुट्टियों में बेहिचक इस आईलैंड पर आ सकें. यहां समुद्र तट और होटल भी बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को विकल्प मिल सके. शकीरा हर स्तर पर अपने से जुड़ने वालों को काफी कंफर्ट महसूस कराती हैं, चाहे वह उनका निजी मामला हो या प्रोफेशनल. बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह ख़ान का कहना है कि उन्हें शकीरा के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं आती है.

बॉलीवुड सर्किट में शाहरुख

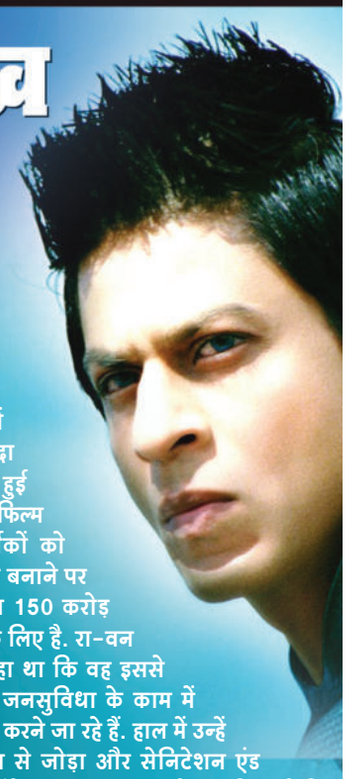

अपनी किसी भी उपलब्धि पर शाहरुख ख़ान को उतनी ख़ुशी नहीं होती, जितना दुःख इस बात का होता है कि उनके माता–पिता इस दुनिया में नहीं हैं. फैमिली वैल्यूज़ का हमेशा सम्मान करने वाले शाहरुख को इस बात का गम है कि उनके बच्चे अपनी मातृभाषा ठीक से नहीं सीख पाएंगे. उनका ख्याल है कि घर में बड़े–बुज़ुर्ग हों तो बच्चे आसानी से अपनी भाषा सीख लेते हैं और उनका चरित्र निर्माण भी बढ़िया होता है. बच्चों में अपने आप अच्छी आदतें आ जाती हैं और वे ज़्यादा सामाजिक हो जाते हैं. अभी हाल में रिलीज हुई उनकी फिल्म रा–वन बच्चों को सीख देने वाली फिल्म है. एक तरफ़ जहां बॉलीवुड में बाल दर्शकों को नज़रअंदाज कर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फिल्में बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं शाहरुख का 150 करोड़ रुपये का ड्रीम प्रोजेक्ट खासकर बच्चों के लिए है. रा–वन के प्रोमोशन के दौरान शाहरुख ने कहा था कि वह इससे मिलने वाले पैसों को महिलाओं की जनसुविधा के काम में लगाना चाहते हैं. अब वह कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं. हाल में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित अभियान से जोड़ा और सेनिटेशन एंड हाइजिन अभियान का ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. डायरिया जैसी बीमारी के कारण हर वर्ष दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं और इसकी रोकथाम का सटीक उपाय है हर घर में टॉयलेट का निर्माण. संयुक्त राष्ट्र संघ और उनका प्रयास है कि आधारभूत सफाई सुविधाओं के बग़ैर रहने वाले लोगों की संख्या 2015 तक आधी हो और डायरिया से बच्चों की रक्षा हो सके. शाहरुख का कहना है, सभी के लिए शौचालय की उपलब्धता से महिलाओं, लड़कियों और समाज के पिछड़े लोगों को काफी फ़ायदा होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

मिले ना मिले हम

काफी दिनों से ख़बर आ रही थी कि कंगना रानावत राजनेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ ज़्यादातर समय बिता रही हैं. बात यह है कि दोनों फिल्म मिले ना मिले हम में साथ काम कर रहे हैं. यह चिराग की बॉलीवुड में डेब्यू होगी. ख़बर है कि राजनेता पुत्र होने का पूरा फ़ायदा चिराग को मिल रहा है. फिल्म के प्रोड्यूसर–डायरेक्टर चिराग के नखरे ख़ूब उठा रहे हैं. फिल्म का टाइटल भी चिराग की पसंद का है. पहले इसका टाइटल वन एंड ओनली रखा गया था. प्रोड्यूसर अनुज सक्सेना ने बताया कि चिराग को पहले वाला टाइटल पसंद नहीं था, जब उन्होंने नया टाइटल सुझाया तो पूरी टीम को पसंद आया. चिराग को फिल्म में अपनी सह कलाकार कंगना का साथ भी बेहद पसंद आया. फिल्म में कंगना ने चिराग के साथ कई रोमांटिक सीन दिए हैं. कंगना का कहना है कि चिराग के साथ काम करते हुए कभी नहीं लगा कि वह न्यू कमर है. मिले ना मिले हम के संगीत लांच समारोह और दूसरे प्रोमोशनल अवसरों पर कंगना रानावत, सागरिका घटके और चिराग पासवान मौजूद थे. बॉलीवुड में आएदिन नए कलाकारों का आना लगा रहता है, लेकिन उनमें कुछ ही ऐसे होते हैं, जिन्हें मौक़ा मिलता है. फिल्म मिले ना मिले को निर्देशित किया है तनवीर ख़ान ने और सहायक निर्देशक हैं नीरज सोनी, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं. पिछले दिनों अंधेरी के फिस्टा स्टूडियो में इस फिल्म की डबिंग हुई. इस मौक़े पर रामविलास पासवान अपने बेटे का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जन्मदिन (4 नवंबर) पर विशेष

तुम जियो हजारों साल

बेमिसाल अभिनेत्री तब्बू

आम बॉलीवुड अभिनेत्रियों से अलग हैं तब्बू. उनके बारे में बहुत कम पढ़ने, देखने और सुनने को मिलता है. वह टेलीविजन पर कम आती हैं, मीडिया में इंटरव्यू भी कम देती हैं. सिल्वर स्क्रीन पर तब्बू को फिल्म तो बात पक्की में देखा गया, उसके बाद वह ख़बरों में आईं पद्मश्री मिलने पर. लोगों को शुक्रिया कहकर तब्बू जो पर्दे के पीछे गईं तो फिर नज़र नहीं आईं. स्वभाव से शांत और एकांत पसंद तब्बू की पहचान पिछले 28 सालों में हर तरह की भूमिकाएं निभाने की वजह से बन पाई. बॉलीवुड में जितने भी शेड के किरदार एक अभिनेत्री के लिए लिखे जाते हैं, तब्बू ने उन सभी किरदारों को बड़ी संजीदगी से निभाया. विजय पथ की दिलफेंक रुक–रुक गर्ल, साजन चले ससुराल में गोविंदा की दूसरी पत्नी, माचिस में सिख बग़ावत में फंसी परेशान पंजाबी लड़की से लेकर कई फिल्मों में संजीदा माशूका तक, हर किरदार उन्होंने इस तरह निभाया कि वह पर्दे पर जीवंत हो उठा. दरअसल यही तब्बू की पहचान बनाने में सहायक भी बना, क्योंकि उन्होंने उस समय इंडस्ट्री में क़दम रखा था, जब धक–धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में थीं और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में थीं रवीना टंडन, जूही चावला और करिश्मा कपूर सरीखी अभिनेत्रियां.

उस वक्त भारतीय सिनेमा में नए प्रयोग हो रहे थे और सभी अभिनेत्रियां अपने लिए ज़मीन तलाश रही थीं, लेकिन तब्बू ने स्थिति को बख़ूबी सोचते–समझते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उनकी बहन फरहा और आंटी शबाना सिनेमा में स्थापित नाम बन चुके थे, लेकिन उनके नाम का फ़ायदा न उठाते हुए तब्बू ने म्यूज़िकल और हल्के–फुल्के मूड वाली फिल्में जैसे, पहला–पहला प्यार, विजय पथ, प्रेम, साजन की बांहों में, साजन चले ससुराल आदि कीं. तब्बू भी मीनाक्षी शेषाद्री और सोनाली बेंद्रे की तरह आई–गई हो जातीं, अगर उन्हें गुलजार की फिल्म माचिस नहीं मिलती, जिसने उन्हें पहला नेशनल अवॉर्ड दिलाया. फिर प्रियदर्शन ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी पीरियड फिल्म काला पानी में लिया. हालांकि पार्वती के रोल में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े–बड़े कलाकारों, जैसे मोहनलाल, नेडुमुडी वेनु और अमरीश पुरी के सामने खड़े होने की हिम्मत ने उन्हें ख़ूब प्रशंसा दिलाई. भारतीय सिनेमा में तब्बू के समय की शायद ही कोई अभिनेत्री होगी, जिसने अपने अभिनय के बल पर तब्बू जैसा समृद्ध और गौरवशाली इतिहास लिखा हो. तब्बू को शायद यह गुण विरासत में मिला. उनकी आंटी शबाना आजमी ऐसी ही भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, लेकिन तब्बू अपने फिल्मी सफर में शबाना जी के हस्तक्षेप से इंकार करती हैं. शबाना एक क्रिटिक की तरह हमेशा तब्बू की एक्टिंग में कोई न कोई कमी बताती रहीं, लेकिन इससे हतोत्साहित होने के बजाय उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया. दो नेशनल और पांच फिल्म फेयर अवॉर्ड ने उन्हें इंडस्ट्री की एक अलग छवि वाली अभिनेत्री बना दिया. वह ख़ुद को कभी करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ सरीखी अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा नहीं कर पाईं, लेकिन शबाना आजमी की तरह उन्होंने भी प्रतिष्ठित अदाकारा का सम्मान पाया. उनका सपना भी यही था.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 31 अक्टूबर-06 नवंबर 2011

www.chauthiduniya.com

स्लीपर घोटाले का जिन्न फिर जागा

सरोज सिंह

नीतीश कुमार के रेल मंत्रितत्व काल में हुए स्लीपर घोटाले का जिन्न एक बार फिर सामने आ गया है. लगभग दो सौ करोड़ रुपये के इस घोटाले पर पटना हाईकोर्ट ने भले ही सीबीआई को कोई निर्देश देने से मना कर दिया, पर याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार सिंह ने बहुत जल्द इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने की तैयारी शुरू कर दी है. उनके वकील दीनू कुमार व शिव कुमार प्रभाकर नए सिरे से काग़ज़ात को खंगालने में जुट गए हैं. लगता है हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद स्लीपर घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है. स्लीपर घोटाले को समझने के लिए पहले रेलवे के कुछ नियमों को समझना ज़रूरी है. रेलवे बोर्ड का नियम था कि क्रंकीट स्लीपर की ख़रीद खुली निविदा से ही होगी. इस नियम के कारण इस काम से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी. इसका हल निकालने के लिए एक ख़ास लॉबी ने ममता बनर्जी के सामने एक प्रस्ताव रखवाया कि क्रंकीट स्लीपर की ख़रीद खुली निविदा की बजाय सीमित टेंडर के मार्फत हो. इसके अलावा यह भी आज़ादी हो कि किसी भी जोन से कहीं के लिए भी स्लीपर ख़रीदे जा सकें. ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव में छिपे घोटाले की बदबू को पहले ही महसूस कर लिया इसलिए इस पूरे प्रस्ताव को उन्होंने सिरे से ख़ारिज कर दिया. इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह आदेश भी निर्गत कर दिया कि निविदा तीन के बजाय दो साल पर होगी. लेकिन ममता बनर्जी के हटने के बाद नीतीश कुमार के कार्यकाल यानी 19 मार्च, 1998 से 5 अगस्त, 1999 और 20 मार्च, 2001 से 22 मई, 2004 में सारे नियम बदल डाले गए. संसद में रेलवे की स्थायी समिति ने जांच के दौरान कुछ तथ्यों को उजागर किया. स्थायी समिति ने पाया कि रेल मंत्री के आदेश के कारण रेलवे को एक मोटे अनुमान के अनुसार दो सौ करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. नियमों को ताक़ पर रखकर गया की दया इंजीनियरिंग वर्क्स को स्लीपर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. 17 अगस्त, 2004 को स्थायी समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में निर्णय लिया कि जिन लोगों ने रेलवे को घाटा पहुंचाया है, उनकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो. 17 फरवरी, 2005 को स्थायी समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि कंक्रीट स्लीपर घोटाले की जांच सीबीआई ने ले ली है. इस बात की जानकारी लोकसभा व राज्यसभा को भी दे दी गई. अब बात आई कि आख़िर सीबीआई की जांच किस तेज़ी से चल रही है और कब पूरी होगी. लोक चेतना मंच के संयोजक मिथिलेश सिंह ने यह जानने के लिए एक आरटीआई डाली. इसके जवाब में रेल मंत्रालय ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने सूचना देने से रेल मंत्रालय को मना कर दिया है. मिथिलेश सिंह ने महसूस किया कि चूंकि नीतीश कुमार बिहार के सीएम के पद पर विराजमान हैं इसलिए कहीं न कहीं से मामले को लटकाने का दबाव बन रहा है. इसलिए अपने वकील दीनू कुमार की मार्फ़त उन्होंने एक याचिका पटना हाईकोर्ट में डाली. याचिका में आग्रह किया गया था कि मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन क्षेत्राधिकार की बात कह अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया. याचिकाकर्ता मिथिलेश सिंह कहते हैं कि माननीय अदालत ने केवल क्षेत्राधिकार का मामला उठाया है, केस की मेरिट पर टिप्पणी नहीं की है. इसलिए यह मामला पूरी तरह से ज़िंदा है और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में नीतीश कुमार की पूरी संलिप्तता है और उच्चतम न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. दूसरी तरफ़ वरिष्ठ वकील दीनू कुमार का कहना है कि सारी सूचनाएं मेरे याचिकाकर्ता के पटना के पते डी 104 पर आई हैं, इसलिए उच्च न्यायालय में भी सुनवाई हो सकती है. ख़ैर अब और मज़बूती से उच्चतम न्यायालय में मामले को रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच को लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता है. जो तथ्य हैं, उससे साफ़ झलकता है कि रेलवे को इस ख़रीद में भारी नुक़सान उठाना पड़ा है.

feedback@chauthiduniya.com

> अब उच्चतम न्यायालय में मामले को और मज़बूती से रखा जाएगा. जांच को लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता है. जो तथ्य हैं, उनसे साफ़ झलकता है कि रेलवे को इस ख़रीद में भारी नुक़सान उठाना पड़ा.
>
> *- दीनू कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता*

> माननीय न्यायालय ने केवल क्षेत्राधिकार का मामला उठाया है, केस की मेरिट पर टिप्पणी नहीं की है. इसलिए यह मामला पूरी तरह से ज़िंदा है और हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे. इस मामले में नीतीश कुमार की पूरी संलिप्तता है.
>
> *- मिथिलेश सिंह, याचिकाकर्ता*

बियाडा ज़मीन आवंटन का मामला फिर गरमाया

पटना हाईकोर्ट ने प्लॉट आवंटन में अनियमितता के मामले में बियाडा से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति टी. मीणा कुमारी व न्यायमूर्ति विकास जैन की पीठ ने बियाडा से इस मुद्दे पर हल्फ़नामा दाख़िल करने को कहते हुए सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है. याचिकाकर्ता पीके सिन्हा एवं अन्य की तरफ़ से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि न्यायालय ने ही बियाडा से आवंटन निविदा के माध्यम से करने को कहा था और इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई लंबित भी थी. इसके बावजूद सरकार ने रसूखवालों को प्लॉट देने के लिए 24 दिसंबर, 2007 को आवंटन संबंधी नियम में ही बदलाव कर दिया एवं पहले आओ और पहले पाओ की व्यवस्था लागू कर दी. इस बदलाव के बाद कई रसूखवाले लोगों को औने-पौने दाम पर प्लॉट दे दिया गया. इस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली कर सरकार को करोड़ों रुपये की चपत लगाई गई है. इस दौरान लगभग 17 सौ लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए. उन्होंने सभी प्लाटों का आवंटन निरस्त कर मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया. वहीं बियाडा की तरफ़ से अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि उन्होंने प्लॉट का आवंटन नियमों के तहत किया है और आवंटन में कोई ख़ामी नहीं है. पहले प्लॉट लेने के लिए कोई नहीं आ रहा था. नियमों के अनुसार प्लॉट आवंटित किया गया है और किसी भी आवंटी से एक रुपया कम नहीं लिया गया है. इस तरह से कैसे कहा जा सकता है कि आवंटन औने-पौने दाम पर किया गया. साथ ही किसी रसूखवाले को प्लॉट देने का आरोप भी ग़लत है, क्योंकि उनके बच्चों को संविधान ने किसी अधिकार से वंचित नहीं किया है. अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है और रसूखवाले का बच्चा है तो इसमें उसका क्या दोष? रसूखवाले पिता के कारण क्या वह व्यवसाय करना छोड़ दे और प्लॉट न ले. पीठ ने अपर महाधिवक्ता से कहा कि वह सभी बातें हल्फ़नामे के ज़रिये कहें. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रसूखवाले लोगों को बियाडा की ज़मीन आवंटित करने के लिए वर्ष 2007 में नियम बदल दिया गया और बिना जांच के उन्हें करोड़ों रुपये की भूमि आवंटित कर दी गई. इन आवंटनों से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हुई है. याचिका में कहा गया है कि बियाडा की भूमि पहले निविदा के ज़रिये आवंटित होती थी. ऐसा वर्ष 2006 तक होता रहा. इसके बाद नियम बदलकर आवंटन का अधिकार बियाडा के प्रबंध निदेशक को दे दिया गया. राज्य सरकार ने ख़ुद ही सर्वोच्च न्यायालय से एक मामले में कहा था कि वह सभी को बराबरी का अधिकार देगी और आगे किसी भी तरह का आवंटन निविदा के ज़रिये करेगी. इसके बावजूद नियम बदल दिया गया. याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम के तहत भूमि को तभी आवंटित किया जा सकता है जब उसे चहारदीवारी से घेरा गया हो एवं उसमें सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों, जिससे वह उद्योग लगाने के लायक़ हो जाए. उसके बाद सभी तरह की लागत का आकलन कर भूमि को आवंटित किया जाए. यह सब नहीं किया गया और भूमि आवंटित कर दी गई. याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने दो मंत्रियों व विधायक एवं एमएलसी के संबंधियों को औने-पौने दाम पर ज़मीन आवंटित कर दी और जब इसे मीडिया ने उजागर किया जो इस पर क़ानूनी कार्रवाई की अनुशंसा कर दी. मुख्यमंत्री ने इस बाबत जो जांच भी करवाई वह महज़ दिखावा है.